चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 19 सितंबर–25 सितंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

ग़लती किसी की सज़ा किसी को

पेज-5

तस्वीर और तक़दीर दोनों बदल रही हैं

पेज-7

कांग्रेस को दोस्ती निभाना नहीं आता

पेज-9

साई की महिमा

पेज-12

बिहार सरकार के

सुशासन का सच

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बिहार में नीतीश सरकार ने दस माह पूरे कर लिए हैं. पिछली सरकार की तरह इस बार भी नारों और दावों का दौर जारी है. सब्ज़बाग़ दिखाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि बिहार देश का नंबर एक राज्य बनेगा. कभी विशेष राज्य तो कभी हरित प्रदेश तो कभी जगमग बिहार. कभी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश तो कभी क़ानून का राज वाला प्रदेश तो कभी दलितों एवं महादलितों का ख्याल रखने वाला प्रदेश. इन बातों में कोई पेंच फंसे तो केंद्र सरकार के भेदभाव का रोना. मतलब यह संदेश देना कि हम तो चाहते हैं, पर हमारे हाथ बंधे हैं. लेकिन इन सब्ज़बाग़ों के बीच सरकार की उपलब्धियों और नाकामियों का प्रदेश में एक नए तरीक़े का आकलन जारी है. नीतीश सरकार के पहले कार्यकाल का आकलन लालू एवं राबड़ी के शासनकाल से किया गया. लगभग ज़ीरो से गाड़ी बढ़ी तो लोगों को लगा कि चलो, अब सरपट दौड़ने का वक़्त आ गया है. क़ानून व्यवस्था एवं सड़क की गाड़ी दौड़ी भी, पर बाक़ी दूसरी गाड़ियां लगातार पंक्चर होती गईं. उधर मीडिया में विज्ञापनों की झड़ी लगाकर ऐसी तस्वीर बनाई गई कि जनता को लगा कि पंक्चर गाड़ियां भी दौड़ रही हैं.

सरोज सिंह

नीतीश कुमार की पहली सरकार को काफ़ी अच्छे अंक मिले, लेकिन अब पैमाना बदला है. एनडीए के लाख चाहने के बावजूद जनता नीतीश सरकार की दूसरी पारी की तुलना लालू–राबड़ी के शासनकाल से नहीं, बल्कि इस सरकार की पहली पारी से करने लगी है. ख़ासकर, क़ानून व्यवस्था और सड़क के मामले में पिछड़ती दिखती सरकार को लोग ध्यान से देख रहे हैं. सरकार के ख़ुद के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में संज्ञेय अपराध के मामले बढ़े हैं. कृषि, सिंचाई एवं उद्योग आदि में राज्य पीछे जा रहा है. प्रदेश पर 57 हज़ार 664 करोड़ रुपये का क़र्ज़ हो गया है यानी प्रत्येक बिहारी पांच हज़ार सात सौ रुपये के क़र्ज़ तले दबा है. बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के सभी राज्यों से कम है. बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं. दूसरे स्थानों की बात तो अलग, राजधानी पटना में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने अपने पांव पसार लिए हैं. एक साल पहले सीएजी की रिपोर्ट के ज़रिए 16 हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था. इसके बाद सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें घोटाले की यह राशि दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गई है. मामला अदालत में विचाराधीन है. मतलब पिछली सरकार में जो गिनी–चुनी गाड़ियां थोड़ी चलती हुई दिखी थीं, उनके भी पंक्चर होने की परिस्थितियां पैदा होने लगी हैं.

हाल में 75 लाख रुपये की फिरौती के लिए कृषि विभाग के एक अफसर के बेटे को मार डाला गया. गोपालगंज जेल में डॉक्टर की हत्या कर दी गई. पटना के बस अड्डे पर एक बड़े एजेंट को भून डाला गया. फारबिसगंज में पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मौत ने तो क़ानून के राज की पोल ही खोल दी. बिहार पुलिस की वेबसाइट बताती है कि 2005 में संज्ञेय अपराधों की संख्या 1,04,781 थी, जो 2010 में बढ़कर 1,37,572 हो गई. क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में प्रतिदिन 10 अपहरण होते हैं, जिनमें एक राजधानी पटना में होता है. भले ही राज्य सरकार पुलिस की छवि को आम जनता में मित्र के रूप में पेश करने का दावा करती है, मगर सारण ज़िले के मांझी थाने में हत्या के एक मामले में मंडल कारा में बंद एक युवती को पुलिस रिमांड पर लेकर उसके साथ किए गए दुराचार ने राज्य सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा दिया. उक्त युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ ज़बरस्ती किए जाने से प्रदेश में सनसनी फैल गई. उसे मांझी थाना कांड संख्या 115/11 के तहत दर्ज हत्या के एक मामले में 24 घंटे के लिए रिमांड पर लिया गया था. रिमांड से लौटने के बाद उसने अपने साथ दुराचार किए जाने का आरोप लगाया तो मंडल कारा प्रभारी काराधीक्षक कुमार मंगलम ने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर महिला चिकित्सक डॉ. किरण ओझा से उसकी मेडिकल जांच कराई. डॉ. ओझा ने युवती के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि करते हुए अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है. सांसद राम कृपाल यादव कहते हैं कि क्या सुशासन में थाने में बलात्कार होगा, क्या जेल में डॉक्टर की हत्या होगी, क्या हक़ मांगने पर पुलिस गोली चलाएगी?

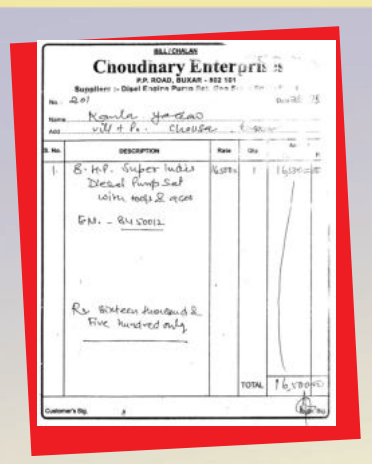

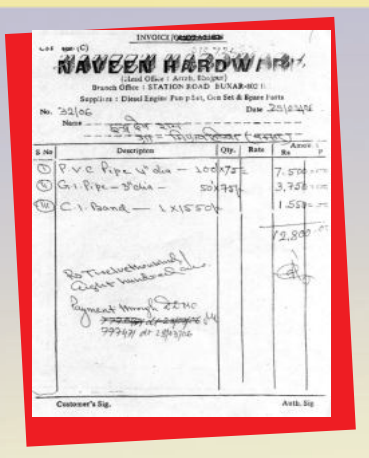

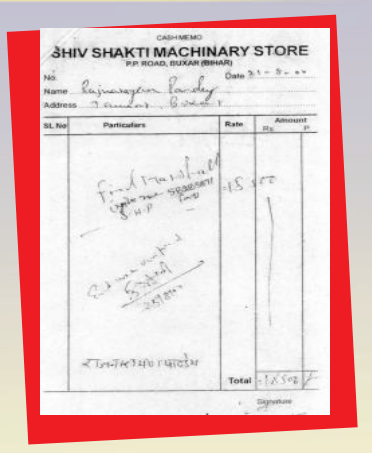

विधानसभा चुनाव के समय जब केंद्रीय मंत्री बिहार आकर केंद्रीय योजनाओं की आधी-अधूरी प्रगति पर बोलते थे तो कहा जाता था कि चुनावी लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा है. पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश पटना आए थे. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को ख़र्च की रफ़्तार बढ़ाने की ज़रूरत है.

विधानसभा चुनाव के समय जब केंद्रीय मंत्री बिहार आकर केंद्रीय योजनाओं की आधी–अधूरी प्रगति पर बोलते थे तो कहा जाता था कि चुनावी लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा है. पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश पटना आए थे. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को ख़र्च की रफ़्तार बढ़ाने की ज़रूरत है. मनरेगा की प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जहां दूसरे राज्यों में 60 फ़ीसदी काम हुआ है, वहीं बिहार की उपलब्धि 35 फ़ीसदी है. अगर राज्य सरकार मांग करे तो 12 हज़ार करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं. मनरेगा के तहत प्रदेश का लेबर बजट 2600 करोड़ रुपये का है, जिसे चार गुना बढ़ाया जा सकता है. ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लिए विशेष महालेखाकार तैनात किए जाएंगे. जयराम ने कई ग़लतफ़हमियां दूर कर दीं. पहली यह कि जितना कहा जा रहा है, उतना काम प्रदेश में नहीं हो रहा है. राज्य चाहे तो केंद्र पैसा देने को तैयार है, पर काम और उसके ख़र्चे पर अब कड़ी निगरानी होगी. ज़ाहिर है, पैसा–पैसा करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख

(शेष पृष्ठ 2 पर)

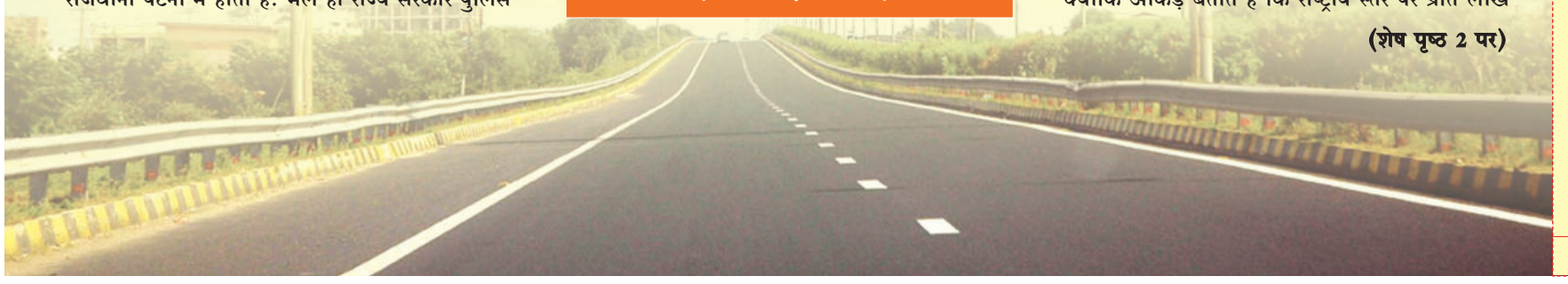

वर्ष 2010-2011

विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को भुगतान की गई राशि का विवरण (गैर योजना मद)

क्रम सं.	पत्र/पत्रिका/चैनल का नाम	भुगतान राशि (रुपये)
1.	हिंदुस्तान	10,12,13,999
2.	हिंदुस्तान टाइम्स	58,63,454
3.	दैनिक जागरण	5,33,68,449
4.	आज	1,30,54,899
5.	प्रभात खबर	1,10,08,037
6.	राष्ट्रीय सहारा	67,41,602
7.	रोजनामा राष्ट्रीय सहारा	1,47,313
8.	टाइम्स ऑफ इंडिया+ईटी	1,13,52,332
9.	प्रत्युष नव विहार, पटना	30,29,027
10.	कौमी तंजीम	98,72,810
11.	फारूकी तंजीम	62,35,314
12.	पिंदार	44,11,220
13.	संगम	13,80,890
14.	इंकलाब-ए-जदीद	20,57,062
15.	प्यारी उर्दू	16,30,667
16.	मोसल्लस	4,21,899
17.	प्रात: कमल	39,63,519
18.	हालात-ए-बिहार	6,67,867
19.	सन्मार्ग, कोलकाता	6,81,003
20.	बिजनेस स्टैंडर्ड, दिल्ली	4,27,607
21.	इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली	5,95,800
22.	अमर उजाला, दिल्ली	3,88,493
23.	पायनियर, दिल्ली	7,12,994
24.	पंजाब केसरी दिल्ली	10,11,461
25.	डीएनए, मुंबई	1,12,268
26.	न्यू इंडियन एक्सप्रेस	27,776
27.	झारखंड जागरण	1,42,503
28.	स्टेट्समैन, कोलकाता	1,68,723
29.	मेल टुडे, दिल्ली	7,07,635
30.	नई बात, भागलपुर	22,11,150
31	देश विदेश, भागलपुर	7,22,536
32.	दैनिक भास्कर, भोपाल	4,06,440
33.	विश्वमित्र, कोलकाता	93,395
34.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	6,07,904
35.	रांची एक्सप्रेस, रांची	1,38,893
36.	इंडिया टुडे ट्रैवल्स प्लस	7,50,000
37.	दी वीक	15,20,000
38	ईस्टर्न क्रोनिकल	3,43,750
39.	टुडे ट्रैवल्स	4,50,000
40.	न्यू ग्लोबल इंडिया	1,42,850
41.	पांचवां स्तंभ	9,37,500
42.	पांचजन्य	80,000
43.	नई दुनिया	6,00,000
44.	आलिया प्रोडक्शन	1,60,000
45.	गुंजन मूवीज	1,26,883
46.	प्रणव मोशन पिक्चर्स	1,77,583
47.	आरुषि न्यूज नेटवर्क	4,00,000
48.	ईटीवी	1,05,12,784
49.	महुआ टीवी	98,77,537
50.	आईबीएन-7	1,46,689
51.	प्रसार भारती आकाशवाणी	16,37,289
52.	प्रसार भारती (दूरदर्शन)	29,41,701
53.	इंडपेंडेंट न्यूज सर्विस	3,14,286
54.	रेडियो मिर्ची	9,41,000
55.	सौभाग्य मिथिला	3,57,372
56.	सहारा टीवी	1,40,300
57.	साधना न्यूज	28,83,347
58.	टीवी टुडे नेटवर्क	3,53,876
59.	आईएनएक्स न्यूज	35,613
60.	रेडियो धमाल	99,854
61.	इन्साइट टीवी न्यूज	28,333
62.	ब्रांड बिहार डॉट कॉम	56,666
	योग	28,15,92,154

(अट्ठाइस करोड़ पंद्रह लाख बानवे हजार एक सौ चौवन रुपये)

संघ लोक सेवा आयोग भी अगले वर्ष की शुरुआत में डीएसपी स्तर के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

नियुक्तियों को लेकर सतर्कता

ओएनजीसी प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. लंबे समय से इस संगठन को अपने प्रमुख का इंतज़ार है, लेकिन अभी यह इंतज़ार ख़त्म होता नहीं दिखाई पड़ रहा है. यूपीए सरकार नियुक्ति के सिलसिले में किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती है. इसी कारण सीवीसी और पेट्रोलियम मंत्रालय से सुधीर वासुदेव को क्लीन चिट मिलने के बावजूद सरकार उन्हें ओएनजीसी के प्रमुख के पद पर नियुक्त नहीं कर रही है. नियुक्ति संबंधित कैबिनेट कमेटी ने वासुदेव की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है. प्रधानमंत्री किसी भी बाबू की नियुक्ति के मामले में काफी सावधानी बरत रहे हैं. उन्होंने बाबुओं की नियुक्ति के लिए नए सिरे से विजिलेंस रिपोर्ट मंगवाई है. थॉमस के मामले में हुई किरकिरी से सरकार काफी सावधान हो गई है, लेकिन इसका खामियाजा ओएनजीसी को भुगतना पड़ रहा है. लगता है, इसके प्रमुख का पद अभी कुछ समय तक और खाली रहेगा.

बाबुओं की चिंता

सरकारी आदेशों के प्रति लापरवाह बाबुओं को अब सावधान रहना होगा. सरकार ने पारदर्शिता बहाल करने के लिए सभी बाबुओं को एक जनवरी तक अपनी संपत्तियों का वार्षिक ब्योरा देने को कहा है. अधिकांश बाबुओं ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा दे दिया है, लेकिन अभी भी 208 बाबू शेष हैं. जबकि सरकार कई बार समय सीमा बढ़ा चुकी है. हालांकि उन्हें अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरह उनकी निजी सूचनाएं सार्वजनिक कर रही है, उससे वे असहज महसूस कर रहे हैं. कार्मिक राज्यमंत्री नारायण सामी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन 208 लोगों ने ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें प्रोन्नति न दी जाए. लगता है, इस बार सरकार कड़ा रुख अपना रही है और बाबुओं को ठीक करने पर तुली है.

सरकार की लापरवाही

देश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बावजूद सरकार भारतीय पुलिस सेवा के खाली पड़े पदों को भरने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा में 1477 अधिकारियों की कमी है. इसके बावजूद गृह मंत्रालय इन पदों को भरने में रुचि नहीं दिखा रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में क़दम अवश्य उठाए हैं. उसने इसके लिए युवा सेना अधिकारियों को आईपीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की बात की है. संघ लोक सेवा आयोग भी अगले वर्ष की शुरुआत में डीएसपी स्तर के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा. इसके साथ ही सरकार का ध्यान विभिन्न खुफिया विभागों में रिक्त पदों को भरने की ओर है. केवल आईबी में ही 10,000 अधिकारियों की आवश्यकता है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

गिरीश प्रधान सचिव बनेंगे

1977 बैच के आईएएस अधिकारी गिरीश बी प्रधान को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बनाया जा सकता है. वह अभी ऊर्जा मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं. इस मंत्रालय के वर्तमान सचिव डॉ. दीपक गुप्ता इस माह के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

जेएस बने दुबे

1982 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार दुबे को पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. उन्होंने अवतार सिंह सहोता का स्थान लिया.

चेयरमैन के लिए नामों का चयन

चाय बोर्ड कोलकाता के अध्यक्ष पद पर अब जल्द ही नियुक्ति किए जाने की संभावना है. संयुक्त सचिव स्तर का यह पद दस महीने से खाली है. इसके लिए तीन लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं.

जूट कमिश्नर की खोज

जूट कमिश्नर कोलकाता के पद पर नियुक्ति के लिए तीन अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं. बीते मई माह में विनोद किसपोट्टा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से नए कमिश्नर की खोज जारी है.

बिहार सरकार के सुशासन का सच

पृष्ठ एक का शेष

आबादी पर 257 किलोमीटर सड़क है, जबकि बिहार में प्रति लाख आबादी पर मात्र 90 किलोमीटर सड़क है. कृषि विकास का लाख ढिंढोरा पीटने के बावजूद यह कड़वी सच्चाई है कि बिहार में कृषि उत्पादन प्रति एकड़ घटता जा रहा है. यहां प्रति हेक्टेयर धान की उपज 15 क्विंटल है, जबकि पंजाब में 40 क्विंटल. 2001–2002 में प्रति व्यक्ति धान उत्पादन क्षमता 55 किलो थी, जो 2008–09 में घटकर 51 किलो रह गई. बिहार में मक्का का उत्पादन 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि आंध्र प्रदेश में 40 क्विंटल. बीज, खाद एवं उपकरण जैसी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसानों को क़र्ज़ देने की योजना राज्य में सफल नहीं रही है. क़र्ज़ देने के लिए जो वार्षिक लक्ष्य रखे गए हैं, वे पिछले पांच सालों में कभी पूरे नहीं हुए. 2005–06 में पांच लाख 66 हज़ार क्रेडिट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य था, पर वितरित हुए मात्र तीन लाख 18 हज़ार कार्ड. 2008 में 15 लाख के मुक़ाबले केवल 10 लाख क्रेडिट कार्ड बने.

डीजल सब्सिडी के नाम पर जो लूट मची, वह जगज़ाहिर है. गया ज़िले में तो मृतकों को भी डीजल सब्सिडी दे दी गई. मेला लगाकर सब्सिडी देकर किसानों को कृषि उपकरण देने की योजना भ्रष्टाचार में डूबी है. बक्सर में बैंकों एवं प्रशासन द्वारा विक्रेताओं से मिलीभगत करके ख़रीद में करोड़ों रुपये के घोटाले करने का आरोप लगाया गया. आरटीआई आवेदन के बाद इसकी जांच हुई. जांच रिपोर्ट की बानगी देखिए. सर्वश्री नवीन हार्डवेयर, स्टेशन रोड़, बक्सर, बिल नंबर 32/06, दिनांक 29 मार्च, 2006. स्टेशन रोड़ बक्सर में उक्त प्रतिष्ठान का कहीं पता नहीं चला. स्थानीय लोगों से पूछने पर उन्होंने इस प्रतिष्ठान के बारे में अनभिज्ञता जताई. जांच में वाणिज्य कर उपायुक्त प्रमोद कुमार ग्वालिया के अलावा सीबीआई के दुर्गा प्रसाद मंडल एवं शशि भानु भी शामिल थे. इसी तरह सर्वश्री शिव शक्ति मशीनरी स्टोर्स और सर्वश्री चौधरी इंटरप्राइजेज के बारे में जांच रिपोर्ट कहती है कि इन नामों का कोई प्रतिष्ठान वर्तमान में नहीं है. ग़ौरतलब है कि नवीन हार्डवेयर से 12 हज़ार आठ सौ, चौधरी इंटरप्राइजेज से 16 हज़ार पांच सौ और शिव शक्ति मशीनरी स्टोर्स से 18 हज़ार 500 रुपये की ख़रीद दिखाई गई, जबकि जांच रिपोर्ट कहती है कि इन नामों से कोई दुकान बक्सर में है ही नहीं. इसी तरह के हज़ारों मामले पूरे बिहार में भरे पड़े हैं. केवल कागज़ों में ख़रीद कर कृषि उपकरण बांट दिए गए. अभी हाल में जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह पर घूसखोरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ में पदस्थापित राजबली सिंह कैंसर से पीड़ित थे. अपने अंतिम समय में उन्होंने परिवार के साथ छपरा में रहने की इच्छा जताई थी, पर लाख प्रयासों के बावजूद मंत्री भीम सिंह ने राजबली सिंह का तबादला नहीं किया. आख़िरकार राजबली सिंह ने दम तोड़ दिया. लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि क्या कोई सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि अंतिम सांस गिन रहे अपने कर्मचारियों की इच्छा का भी सम्मान नहीं कर सकती.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह बंटाधार कर दिया गया है. उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक तरह–तरह से उंगली उठाई जा रही है. एएसएआर (स्वतंत्र संस्था) के सर्वे के अनुसार, बिहार में पांचवीं कक्षा के 70 प्रतिशत छात्र कक्षा दो स्तर का भी ज्ञान नहीं रखते. शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए केंद्र से पैसा आया, पर प्रशिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई और पैसा वापस चला गया. देश की औसत साक्षरता दर 74.6 प्रतिशत है, जबकि बिहार की औसत साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है. योजना आयोग की एक समिति ने 2008–09 में राज्य का सर्वे किया था. समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि बुनियादी शैक्षिक संरचना संकेतक के मुताबिक़ बिहार का देश में 35वां स्थान है. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर पर बिहार सबसे पीछे है, जबकि केंद्र सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पैसा मुहैय्या कराती है. बिहार में 408 में से 235 प्रशिक्षकों के पद आज भी खाली हैं. 6.5 फ़ीसदी स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, 20 फ़ीसदी में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, 56 फ़ीसदी में शौचालय नहीं हैं और 88 फ़ीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं. 63 फ़ीसदी छात्र–छात्राएं ही प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक विद्यालय में पहुंचते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 84 फ़ीसदी है. ठेके पर बहाल शिक्षकों के बारे में काफी कुछ लिखा–पढ़ा जा चुका है. वीसी की नियुक्ति पर जो बवाल मचा, उससे उच्च शिक्षा का हाल ख़ुद–बख़ुद जाना जा सकता है.

डीजल सब्सिडी के नाम पर जो लूट मची, वह जगज़ाहिर है. गया ज़िले में तो मृतकों को भी डीजल सब्सिडी दे दी गई. मेला लगाकर सब्सिडी देकर किसानों को कृषि उपकरण देने की योजना भ्रष्टाचार में डूबी है. बक्सर में बैंकों एवं प्रशासन द्वारा विक्रेताओं से मिलीभगत करके ख़रीद में करोड़ों रुपये के घोटाले करने का आरोप लगाया गया.

राज्य का सिंचित भू–क्षेत्र पिछले पांच साल से कम हो रहा है. 2005–06 में कुल सिंचित भूमि 4830 हजार हेक्टेयर थी, जो 2009–10 में घटकर 4441 हज़ार हेक्टेयर रह गई. 380 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई सुविधाओं से वंचित हो गई. नहर सिंचाई 2005–2006 में 1661 हज़ार हेक्टेयर (34.38 प्रतिशत) थी, जो घटकर 2009–2010 में 1202.45 हज़ार हेक्टेयर (27.3) प्रतिशत रह गई. 2005–06 तक बड़ी नहरें 1661 हज़ार हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र के 34 प्रतिशत हिस्से को पानी उपलब्ध कराती थीं. उनकी भागीदारी 2009–10 में घटकर 1202 हज़ार हेक्टेयर यानी 27 प्रतिशत रह गई. छोटी नहरों द्वारा सिंचित भूमि में भी कमी आई है. यह 1920 हजार हेक्टेयर से घटकर मात्र 17.5 हज़ार हेक्टेयर रह गई है. सिंचाई के लिए बड़े और मंझोले किसान ट्यूबवेल की तरफ़ मुड़े हैं और उनकी हिस्सेदारी कुल सिंचाई में बढ़ी है, पर ज़्यादातर बढ़ोत्तरी निजी ट्यूबवेलों में हुई है. हालांकि बिजली की कमी और डीजल महंगा होने की वजह से उनका भी हाल–बेहाल है, जिन्होंने ट्यूबवेल लगवाए हैं. 2006–07 में नाबार्ड के तहत वर्ष 2009–10 तक प्रदेश में 2764 बिजली नलकूप लगाने की योजना बनाई गई, लेकिन केवल 938 ट्यूबवेल लगाए जा सके. उद्योगों की बात करें तो मार्च 2007 से मार्च 2009 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की 28 कंपनियां बंद हुईं. रोज़गार मुहैय्या कराने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र काफी पीछे हैं. मार्च 2009 तक कुल 21 हज़ार 250 कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में थे, इनमें से 15 हज़ार 317 कर्मचारी केवल 4 कॉरपोरेशनों में हैं. हालांकि ये चारों भी घाटे में चल रहे हैं. बाक़ी क़रीब 7 हज़ार कर्मचारी 59 कंपनियों में हैं. 31 कंपनियां तो ऐसी हैं, जिनमें कई ने तो 16 वर्षों से कोई ऑडिट ही नहीं कराया है. मसलन बिहार राज्य पर्यटन विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मत्स्य विकास निगम, बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन आदि शामिल हैं.

पूंजी निवेश की शुरुआती कोशिशों में नीतीश सरकार को मदद मिली, पर जैसे–जैसे यथार्थ का बोध निवेशकों को हुआ, वे भागने लगे. 2008–09 से लेकर अक्टूबर 2010 तक कुल एक लाख 81 हज़ार 4 सौ करोड़ रुपये के 398 प्रस्तावों को राज्य सरकार ने मंज़ूर किया, पर इन तीन सालों में अक्टूबर 2010 तक इनमें कोई वास्तविक निवेश नहीं हुआ. बियाडा ज़मीन आवंटन में धांधली का मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है. राज्य में चीनी का उत्पादन घट रहा है. वर्ष 2006–07 में यह 4.5 लाख टन था, जो 2007–08 में 3.90 लाख टन और 2008–09 में और कम होकर 2.2 लाख टन पर पहुंच गया. राज्य में कुल 33 चीनी मिलें थीं, जिनमें अब 28 मिलें बची हैं और इनमें भी सभी सरकारी मिलें बंद हो गई हैं. स्वास्थ्य के मामले में भी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है. 1641 प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में से केवल 533 केंद्र 24 घंटे काम करते हैं. 69,246 सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा योजना के तहत नियुक्त 10 हज़ार से ऊपर कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं हैं. किसी के पास दवाओं का किट बैग नहीं है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या पहले ही ज़रूरत से काफी कम थी, अब और घटती जा रही है. राज्य में 2489 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होने चाहिए, जबकि हैं केवल 1774. वर्ष 2008 में कुल 11,107 स्वास्थ्य केंद्र थे, जो अक्टूबर 2010 तक घटकर 10,632 रह गए. 2008 में एक लाख की आबादी पर 13 स्वास्थ्य केंद्र थे, जो 2009 और 2010 में केवल 11 रह गए. बाल मृत्यु दर में बिहार सबसे आगे है. यहां हर 1000 बच्चों में एक तिहाई कुपोषण से मरते हैं. सिटीजन एलायंस अगेंस्ट मालन्यूट्रीशियन संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है. विज्ञापनों के माध्यम से सरकार की सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश का असर कितने दिनों तक रहेगा, यह तो पता नहीं, पर अब ज़रूरत सही मायनों में बिहार के वास्तविक विकास की ओर ध्यान देने की है.

बिहार के इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य का निराशाजनक पहलू यह है कि विपक्षी पार्टियां भी पूरी ताक़त के साथ सड़कों पर आकर सुशासन के सब्जबाग का विरोध करने में हिचक रही हैं. पहले तो विपक्ष ने यह कहा कि वह छह महीने तक कुछ नहीं बोलेगा. इन छह महीनों में नीतीश की किसी भी ग़लत नीति का विरोध नहीं हुआ. जब यह वक़्त बीत गया तो भी हिचक पूरी तरह नहीं टूट पा रही है. इक्का–दुक्का विरोध दिखता है, पर जनता के बीच यह संदेश नहीं जा रहा है कि विपक्ष पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है. पूर्णिया उपचुनाव में भी विपक्ष का साझा उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा की प्रत्याशी भारी मतों से जीत गईं. कहने को तो राजद और लोजपा में गठबंधन है, पर जमीन पर यह कहीं दिखता नहीं है. कांग्रेस अपने ही दुश्मनों से परेशान है और वामदल अपनी ज़मीन बचाने में लगे हैं. एक तरह से जनता के सामने नीतीश के ख़िलाफ़ विकल्पहीनता की स्थिति है, जिसका फ़ायदा पिछले चुनाव में जदयू–भाजपा गठबंधन को मिला. हालात कमोबेश वैसे हैं और अगर इसमें सुधार न हुआ तो सब्जबाग दिखाने के बावजूद नीतीश कुमार का कथित सुशासन क़ायम रहेगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 28
दिल्ली, 19 सितंबर–25 सितंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आज भी भजनपुर के लोग डरे-सहमे हैं. उन्हें अपनों के खोने का गम सता रहा है. उधर ग्लूकोज कंपनी सुंदरम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और प्रशासन की तरफ से गांव के सभी लोगों के ख़िलाफ़ कई आपराधिक मुक़दमे कर दिए गए हैं.

अररिया ज़िले का भजनपुर गांव

दबंगई का अंतहीन सिलसिला

अशरफ अस्थानवी

यह भजनपुर गांव है. बिहार के राजनीतिक एवं भौगोलिक नक्शे के अनुसार एक ऐसा गांव, जो ज़िला अररिया के अनुमंडलीय नगर फारबिसगंज से मात्र दो किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से इतना पिछड़ा है कि वहां आज तक न्याय और विकास जैसे राजनीतिक नारे की आवाज़ तक नहीं पहुंच सकी. नंग-धड़ंग और कुपोषण के शिकार बच्चे, अर्द्धनग्न महिलाएं, मायूस एवं लाचार बूढ़े और अपने भविष्य को शून्य में ढूंढती युवा पीढ़ी. यही है इस गांव की असली पहचान. लगभग तीन हजार की आबादी वाले इस गांव में 95 फ़ीसदी मुसलमान बसते हैं. यह गांव महादलित वाली स्थिति से भी बदतर ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर है. आज से तीन माह पहले तक इस गांव को कोई जानता भी नहीं था. हां, वोट के सौदागरों को इतना मालूम था कि संसदीय क्षेत्र अररिया और विधानसभा क्षेत्र फारबिसगंज में एक गांव ऐसा भी है, जिसके पास बिना किसी हील-हुज्जत के थोक वोट हैं. सभी राजनीतिक दल इस गांव पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखते हैं, लेकिन चुनावी मौसम के बाद यह गांव फिर गुमनामी के अंधेरे में विलीन हो जाता है. यह गांव जिन संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, उनकी नुमाइंदगी का झंडा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है.

भजनपुर गांव का दुर्भाग्य है कि यह पहली बार एक ऐसे समय में अख़बारों की सुर्खियों में आया है, जब वोट के लिए मारामारी का कोई मौसम नहीं है, लेकिन इस स्थिति की पृष्ठभूमि में राजनीति का खेल ज़रूर है. रास्ते के सवाल पर चार ग्रामीणों को गोलियों से भून डाला गया. क्रूरता का दानव इतने से ही शांत नहीं हुआ. वर्दीधारी शैतान लाशों को गालियां देते हुए अपने बूटों से घंटों रौंदते रहे. वर्दीधारियों की इस हरकत को पूरी दुनिया ने देखा. इसके बावजूद इंसानियत को शर्मसार करने वालों के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. गांव के लोग बताते हैं कि इस काली करतूत के पीछे राज्य सरकार के एक दबंग मंत्री का हाथ है. मामले की लीपापोती के लिए एक न्यायिक जांच आयोग पूर्व न्यायाधीश जस्टिस माधवेंद्र शरण की अध्यक्षता में गठित कर दिया गया है. इससे पहले राज्य के गृह सचिव आमिर सुब्हानी ने घटनास्थल का दौरा करके जो प्रतिवेदन दिया, उसमें ग्रामीणों की मौत क्रॉस फायरिंग में होने की बात कही गई है, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने जब भजनपुर का दौरा किया तो आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने आमिर सुब्हानी की रिपोर्ट को सच्चाई से परे करार दिया और कहा कि राज्य के गृह विभाग ने आयोग को गुमराह किया है. जबकि वास्तविकता कुछ और है.

भजनपुर स्थित बियाडा (बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) की करोड़ों की ज़मीन औने-पौने दामों पर अपने चहेतों को बतौर लीज देने और ग्लूकोज फैक्ट्री स्थापित कराने की कार्रवाई के दौरान चाहरदीवारी के नाम पर गांव से बाहर निकलने का रास्ता बंद किया जा रहा था तो गांव वालों ने आपत्ति जताते हुए रास्ता देने की गुहार लगाई. इस पर दबंगों और सरकारी वर्दीधारियों ने जलियां वाला बाग कांड की याद ताजा कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जांच आयोग गठित कर दिया गया है, रिपोर्ट के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक सत्ताधारी दल का एक भी सदस्य वास्तविकता जानने-समझने के लिए भजनपुरा नहीं गया. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान, फिल्म निर्माता महेश भट्ट, प्रसिद्ध समाजसेवी शबनम हाशमी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर, पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ, जदयू के बागी सांसद राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर आदि ने भजनपुरा का दौरा करके मृतकों के परिवारीजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और घटना की निंदा करते हुए न्याय दिलाने की बात कही.

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भजनपुरा पहुंच कर पीड़ितों के आंसू पोछने का प्रयास ज़रूर किया. लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद ने बीते 5 सितंबर को फारबिस गंज मार्च का आयोजन किया. फारबिसगंज स्थित आईटीआई मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा न्यायिक जांच केवल सरकारी दोष छुपाने की आपराधिक कोशिश है. लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन का शंखनाद करते हुए कहा कि न्याय के साथ विकास की पोल खुल चुकी है. इससे पहले लालू प्रसाद भजनपुरा गांव गए और पुलिस एवं दबंगों की गोलियों से मारे गए मोहम्मद मुस्तफा (18), मुख्तार अंसारी (20), नौशाद अंसारी (तीन माह का बच्चा, जो मां की गोद में था) और फेकन अंसारी (25) के आश्रितों को उन्होंने एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि दी. इसके साथ ही गर्भवती महिला रशीदा बेगम (28) सहित घायल दस अन्य ग्रामीणों को भी दस-दस हज़ार रुपये दिए. रशीदा बेगम को इतना पीटा गया कि उसका गर्भपात हो गया.

आज भी भजनपुर के लोग डरे-सहमे हैं. उन्हें अपनों के खोने का गम सता रहा है. उधर ग्लूकोज कंपनी सुंदरम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और प्रशासन की तरफ से गांव के सभी लोगों के ख़िलाफ़ कई आपराधिक मुकदमे कर दिए गए हैं. पीड़ितों की तरफ से केवल तीन मुकदमे हुए हैं. एक मुकदमा रफीक अंसारी वल्द रफी अंसारी निवासी भजनपुर की तरफ से फारबिस गंज अनुमंडल पदाधिकारी और अररिया पुलिस के 100 नामालूम जवानों पर किया गया है और उन पर भादवि की धारा 149, 148, 147, 120, 109, 302, 307, 342 और 341 लगाई गई है. इस मुकदमे का नंबर 1341/2011 है. दूसरा मुकदमा फेकन अंसारी की तरफ़ से किया गया है, जिनमें 9 लोगों को नामजद करते हुए उन पर उक्त धाराएं लगाई गई हैं. इस मुकदमे का नंबर 37203/2011 है. एक प्राथमिकी प्रशांत कुमार की तरफ से पुलिस जवान सुनील कुमार यादव के विरुद्ध दर्ज कराई गई है, जिसमें मोहम्मद मुस्तफा नामक ग्रामीण को बूटों से कुचल कर मार देने के आरोप में धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही गई है. ताजा स्थिति यह है कि ग्रामीणों की ओर से दायर मुकदमों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है. गांव के लोग बताते हैं कि धनबल और बाहुबल के सहारे हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अररिया की एसपी प्रेमा सिंह की भूमिका की जांच अवश्य होनी चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

गुरु शंकर देव का अचानक ग़ायब होना और उनकी हत्या की आशंका के साथ शक की सूई इन्हीं मठाधीशों की ओर जाना योग पीठ को दाग़दार बना रहा है.

उत्तर प्रदेश

भ्रष्ट तंत्र को तोड़ना आसान नहीं

अजय कुमार

अन्ना ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अलख क्या जगाई, गांव की चौपालों से लेकर शहर के नुक्कड़ों तक लोगों का गुस्सा निकल कर सामने आ गया. गुस्सा भी ऐसा कि सरकार और संसद तक को झुकना पड़ा. हर तरफ़ एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि अब भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे. आम जनता भ्रष्टाचार को लेकर हलकान है, वहीं भ्रष्टाचारी लोग जनता में आई जागरूकता से हैरान हैं. ख़ासकर राजनेता और आईएएस अधिकारी इस आंदोलन से काफी डरे-सहमे दिखे. फ़र्क़ इतना है कि जनता को सबका भ्रष्टाचार दिख रहा है, वहीं नेताओं और नौकरशाहों को सिर्फ़ अपने विरोधियों का. कोई भी नेता या नौकरशाह अपने गिरेबां में झांकने को तैयार नहीं है. उत्तर प्रदेश में मायावती से पहले मुलायम सिंह, भाजपा, कांग्रेस आदि की सरकार रह चुकी हैं. इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन आरोप लगाने वालों के चेहरे ज़रूर समय-समय पर बदलते रहे.

मुलायम सिंह की सरकार के भ्रष्टाचार को आईना बसपा दिखा रही थी, अब यह काम समाजवादी कर रहे हैं. हालांकि भाजपा और कांग्रेस जैसे दल भी बसपा सरकार पर हल्ला बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें वह दम नहीं दिखता, जो सपा में दिख रहा है. प्रदेश में नंबर दो की पार्टी सपा चाहती है कि विधानसभा चुनाव में मुक़ाबला उसके और बसपा के बीच सिमट जाए. सपा को पता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा शासित विभिन्न प्रदेशों की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं. ऐसे में इन दोनों दलों के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सपा विपक्ष में है, इसलिए उसके प्रति जनता की नाराज़गी कम है. भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी मायावती ने पहले अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन और उसके बाद मुख़ालफत करके अपने लिए मुसीबतों को जन्म दे दिया. वह भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी वोट बैंक की राजनीति में फंसाकर कमज़ोर करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रही हैं. मायावती ने अन्ना के आंदोलन की मुख़ालफत क्या की, विपक्ष को उन पर हल्ला बोलने का मौक़ा मिल गया. समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री मायावती और उनके मंत्रियों ख़ासकर, नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी, सतीश मिश्रा, लाल जी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, अनंत मिश्रा उर्फ़ अंटू एवं अवध पाल सिंह की चल-अचल, नामी-बेनामी संपत्ति की सीबीआई जांच कराई जाए. उक्त मंत्री अधिकारियों के साथ मिलकर लूट-खसोट कर रहे हैं. देश के बड़े-बड़े शहरों में इन्होंने होटल, मॉल और मल्टीप्लेक्स बनवा रखे हैं. कई बड़े अफसर ऐसे हैं, जो विदेशों तक अपने पैर पसार रहे हैं. बसपा का ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले एक बड़े नेता ने सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति एकत्र कर रखी है. उसका मुंबई में एक होटल भी है. इस ब्राह्मण नेता को गुमान है कि उसी के चलते बसपा सत्ता में आई है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. विपक्ष का आरोप है कि बसपा के एक कद्दावर नेता ने लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित अपने बंगले में नोट गिनने की मशीन लगा रखी है. वहीं बसपा प्रमुख अरबों रुपये के हीरे-जेवरात एकत्र करके अपनी संपत्ति बढ़ा रही हैं. सपा प्रमुख मुलायम सिंह कहते हैं कि सीबीआई को चाहिए कि वह एनआरएचएम में ज़बरदस्त लूट में मुख्यमंत्री कार्यालय की भागीदारी की जांच गंभीरता से करे. दो पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा और बाबू सिंह कुशवाहा सीबीआई के शिकंजे में हैं. अन्य दो मंत्रियों के भ्रष्टाचार के बारे में लोकायुक्त अपनी जांच रिपोर्ट जल्द देने वाले हैं. कैग की रिपोर्ट में मायावती सरकार पर अरबों रुपये के घोटाले का आरोप लगा तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ. विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी मायावती ने स्वयं की तिजोरी भरी ही, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए पार्कों-स्मारकों के निर्माण में भी जमकर धन लुटाया. मायावती ने अपनी मूर्तियों तक में कमीशन खाया. आबकारी आयुक्त महेश कुमार गुप्ता और माध्यमिक शिक्षा सचिव जितेंद्र कुमार भी सपा के निशाने पर हैं. महेश गुप्ता सूचना विभाग में हुए भर्ती घोटाले में आरोपित हैं, लेकिन राज्य सरकार उन पर मुक़दमा चलाने की अनुमति देने से कतरा रही है. पैकफेड के एमडी विपिन कुमार चौधरी के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी तरीक़े से फ्लैट आवंटन का मामला ग़ाज़ियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज है. अभियोजन मंजूरी के लिए शासन को पत्र लिखे क़रीब दो वर्ष गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई. पहले सहकारिता मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने फाइल दबा रखी थी. उनके जाने के बाद भी मामला अधर में है.

नौकरशाह जसवीर सिंह के क़रीबी संबंध कुख्यात हसन अली से होने की बात सामने आई थी, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया. वरिष्ठ आईएएस सुनंदा रिटायर हो गईं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ चल रहे मामलों में सरकार ने अभियोजन मंजूरी नहीं दी. डूडा के सर्वेसर्वा राम बहादुर हाथी घोटाले में फंसे हैं. नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने आबकारी विभाग में अरबों रुपये के घोटाले पकड़े हैं. नेता प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह का कहना था कि मायावती सरकार सिर्फ़ पूंजीपतियों से रिश्ता निभाने और अपनी संपत्ति में इज़ाफ़ा करने के लिए मिलें और किसानों की जमीनें औने-पौने दामों में बेच रही है. सरकार ने साढ़े चार साल में कितनी ज़मीन अधिग्रहीत की और किन पूंजीपति घरानों को बांटी, इस पर एक श्वेतपत्र जारी किया जाए. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र ने मायावती सरकार को धान एवं गेहूं की ख़रीद के लिए आठ हज़ार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई. 11 हज़ार मीट्रिक टन गेहूं बाहर पड़ा है. हॉस्पिटल इन्फॉरमेशन सिस्टम के उच्चीकरण के लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई. मंत्री के दबाव में यह कार्य मेसर्स एसआरआईटी बंगलुरु को दे दिया गया और भुगतान भी कर दिया गया, मगर आज तक कोई काम नहीं हुआ. पीजीआई में एचआरएफ विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपये की दवाएं ख़रीदी जाती हैं, लेकिन उक्त ख़रीद चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इशारे पर चहेती मेडिकल कंपनियों से मानकों के विपरीत की जा रही है. 1973 बैच के आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ बेहुरा उड़ीसा के मूल निवासी हैं. वह 15 नवंबर, 2005 को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए थे. उन्हें उस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर तैनाती मिली थी. बाद में मुख्य सचिव के समकक्ष ग्रेड में आते ही वह दूरसंचार सचिव के पद पर प्रोन्नत हुए. बेहुरा उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और उनकी छवि पर सवाल भी उठते रहे. अफसरों के बीच उन्हें साइलेंट ऑपरेटर कहा जाता था. वह सूबे में कभी किसी मामले में नहीं फंसे. दूरसंचार सचिव पद से भी वह सितंबर 2009 में बेदाग रिटायर हो गए. हालांकि बाद में घोटाला सामने आने पर जांच में वह फंसे और गिरफ्तार किए गए. केंद्र में सचिव पद पर तैनात रहने के बाद गिरफ्तार होने वाले बेहुरा उत्तर प्रदेश कैडर के पहले आईएएस अधिकारी थे. उत्तर प्रदेश कैडर के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी बलजीत सिंह लाली भी प्रसार भारती के सीईओ की हैसियत से भ्रष्टाचार में फंस गए. पंजाब के मूल निवासी लाली के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं. लाली अप्रैल 2007 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने जुगाड़ करके प्रसार भारती में सीईओ का पद हथिया लिया. भूमि घोटाले में राकेश बहादुर और संजीव सरन फंसे हैं. 1983 बैच के आईएएस अधिकारी सदाकांत भी एक मामले में फंसे हैं. वह 2007 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और उनका कार्यकाल 2012 में पूरा होना था, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो केंद्र ने समय से पहले उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी. सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है. यह भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि कई आईएएस अधिकारी केंद्र के निर्देश के बाद भी अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं. जिन अधिकारियों ने अपनी संपत्तियों का जो ब्योरा दिया है, वह चौंकाने वाला है. कई आईएएस अधिकारी ऐसे हैं, जिनके दो से अधिक मकान और प्लाट हैं. एक अधिकारी की पत्नी की लखनऊ में ज्वैलरी की दुकान है. 55 से अधिक आईएएस अधिकारियों के फॉर्म हाउस और दर्जन भर से अधिक अधिकारियों के पास लखनऊ एवं दिल्ली सहित कई महानगरों में मॉल तथा पत्नी के नाम दुकानें होने की बात सामने आई है.

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

बालकृष्ण की जालसाज़ी का भंडाफोड़

राजकुमार शर्मा

बाबा रामदेव एंड कंपनी की जालसाज़ी का ख़ुलासा होने से जनता में यह संदेश जा रहा है कि काले धन की वापसी और व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले पतंजलि पीठ के खेवनहार रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ख़ुद एक बड़े जालसाज़ हैं. बालकृष्ण के पासपोर्ट की जांच के दौरान उनके द्वारा दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए जाने का ख़ुलासा हुआ है. पहले प्रमाणपत्र में उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता भारतीय, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र में उन्हें नेपाली बताया गया है. हरिद्वार नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का लाभ उठाते हुए आचार्य बालकृष्ण ने गुरु शंकर देव की ओर से दिए गए शपथपत्र को आधार बनाकर 5 दिसंबर, 1997 को पहला जन्म प्रमाणपत्र हासिल कर लिया. इसी प्रमाणपत्र के आधार पर बालकृष्ण ने 1998 में पासपोर्ट बनवाया. 16 मई, 2006 को उन्होंने गुरु शंकर देव के फ़र्ज़ी हस्ताक्षरों से बने एक अन्य शपथपत्र के सहारे जन्म प्रमाणपत्र के लिए पुन: आवेदन कर दिया, जिसमें उन्होंने ख़ुद और अपने माता-पिता को नेपाली नागरिक बताया. नगरपालिका के अफ़सरों ने भी नज़राना पाकर बिना कोई जांच किए दूसरा जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया.

दो-दो जन्म प्रमाणपत्र, एक में भारतीय नागरिक और दूसरे में नेपाली नागरिक बताया जाना ही बालकृष्ण के गले की फांस बन गया. हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बालकृष्ण के पासपोर्ट की छायाप्रति लेकर हरिद्वार पहुंची तीन सदस्यीय सीबीआई टीम को उपलब्ध करा दी है. सीबीआई ने पासपोर्ट नवीनीकरण के समय पेश दस्तावेज और एलआईयू रिपोर्ट भी राज्य पुलिस से हासिल कर ली है. सीबीआई को जांच के दौरान दो पासपोर्ट तो नहीं मिले, लेकिन दो बुकलेटों का जारी होना प्रकाश में आया है, जबकि पासपोर्ट एक है. बालकृष्ण ने 29 अप्रैल, 1998 को जो पासपोर्ट हासिल किया, उसकी वैधता दस वर्ष थी, जिसका 7 फरवरी, 2007 को नवीनीकरण करा लिया गया. साथ ही एक जंबो बुकलेट जारी कराकर पहले वाली बुकलेट रद्द करा दी गई. बुकलेट की जांच ही बालकृष्ण की परेशानी का सबब बनी हुई है. आचार्य के भाई की नागरिकता नेपाली है, आचार्य भी मूलत: नेपाली हैं, उनके माता-पिता आज भी नेपाल में रहते हैं. सीबीआई आचार्य के जन्म के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए दो टीमें बनाकर दर-दर की खाक छानने में जुटी है. सीबीआई गुरु शंकर देव के हस्ताक्षरों वाले दो शपथपत्रों, जो आचार्य ने दो बार अलग-अलग अपने हित साधने के लिए दिए, की तह तक जाना चाहती है. गुरु शंकर देव का अचानक ग़ायब होना और उनकी हत्या की आशंका के साथ शक की सूई इन्हीं मठाधीशों की ओर जाना योग पीठ को दाग़दार बना रहा है. अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हठयोगी कहते हैं कि सीबीआई को शंकर देव की मौत के सच का ख़ुलासा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए. संत हठयोगी का दावा है कि बालकृष्ण की डिग्री भी फ़र्ज़ी है. दोनों ने दान की धनराशि अपने व्यापार में लगाकर न्यास की भावना के विपरीत काम किया है. पतंजलि योग पीठ की मासिक पत्रिका योग संदेश के मई 2011 के अंक में सम्राट अशोक के बाद के शासकों और बौद्ध धर्म पर की गई टिप्पणियों का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया है.

बौद्ध कम्यून इंटरनेशनल एंड लॉर्ड बुद्धा वेलफेयर सोसाइटी ने एक जनहित याचिका दाखिल कर ऐसे अनर्गल प्रकाशन पर रोक लगाने और पत्रिका का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की मांग की है. एसएसपी हरिद्वार के अनुसार, सीबीआई आचार्य के पासपोर्ट नवीनीकरण के संबंध में एलआईयू रिपोर्ट और विधिक राय नज़रअंदाज़ किए जाने के मामले की तह तक जाना चाहती है. सरकार की कार्यवाही से दिव्य योग पीठ परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है. रामदेव द्वारा क़ब्ज़ाई गई ग्रामसभा की 45 एकड़ ज़मीन मुक्त कराकर ग्रामीणों को वापस कर दी गई है. बाबा का साथ देने का दंभ भरने वाली निशंक सरकार ने उनके द्वारा ग्रामसभा की भूमि पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा करने के मामले का ऐसे समय पर ख़ुलासा किया, जब बाबा पर चारों ओर से हमले हो रहे थे. बाबा रामदेव द्वारा नारायण दत्त तिवारी को पटाकर सैकड़ों बीघा ज़मीन हथियाने का मामला भी तूल पकड़ रहा है. बाबा एंड कंपनी ने जिस तरह अपने शीशे के महल से सरकार पर पत्थर फेंका, उसी का परिणाम था कि रामदेव को महिलाओं के कपड़े पहन कर रामलीला मैदान से भागना पड़ा. समर्थक कहते हैं कि बाबा रामदेव को सरकार से सीधे टकराने की ग़लती नहीं करनी चाहिए थी.

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली हाईकोर्ट के रिसेप्शन के पास हुए विस्फोट के तुरंत बाद सरकार का बयान आता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, अभी नहीं बता सकते.

दिल्ली बम विस्फोट

ग़लती किसी की सज़ा किसी को

मरने वाला अकेला नहीं मरता. उसके साथ मरती हैं कई और ज़िंदगियां. ताउम्र, तिल-तिलकर. दिल्ली बम धमाके में जिन 13 लोगों की मौत हुई, उनके परिवार वालों की आंखों से निकलते आंसू देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए. पीएम से लेकर भविष्य में होने वाले पीएम तक अस्पताल पहुंचे, लेकिन व्यवस्था किस क़दर संवेदनशून्य हो सकती है, इसका नमूना शव लेने अस्पताल पहुंचे परिवारीजनों को तब हुआ, जब उनसे अस्पताल प्रशासन ने शव के लिए कफ़न और 2 मीटर प्लास्टिक बाज़ार से ख़रीद कर लाने को कहा. बहरहाल, सवाल यही है कि आख़िर कब तक ये धमाके होते रहेंगे, आख़िर चूक कहां हो रही है?

सवाल यह है कि क्या हमारी ख़ुफ़िया एजेंसियों को इसकी ख़बर थी? सुरक्षा में तैनात जवान कहां थे? आतंकवादी वहां आराम से आते हैं, विस्फोटक (अटैची में) रखकर चले जाते हैं. आख़िर उस वक़्त पुलिस वाले कहां थे? बाद में इनके स्केच जारी कर दिए जाते हैं. आख़िर इन आतंकियों को भागने के लिए सेफ पैसेज कहां से मिल गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आख़िर क्यों इन आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बार-बार धमकी देकर धमाके कर देते हैं? क्या उन्हें क़ानून और सज़ा का डर नहीं है? ज़ाहिर है, डर नहीं है. और हो भी क्यों? आतंकवाद के ख़िलाफ़ टाडा और पोटा जैसे क़ानून थे, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया. अब आतंक के ख़िलाफ़ एक ऐसा क़ानून है, जिसकी वजह से दोषी साबित हो चुके आतंकियों को भी सज़ा नहीं मिल पाती. मुंबई में आतंकी हमले के बाद सरकार की ओर से की गई घोषणाओं पर अब तक अमल नहीं हो सका है. ख़ुफ़िया सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नेटग्रिड बनाने की बात थी, वह अब तक नहीं बनाया जा सका है. ख़ुफ़िया विभाग में अधिकारियों की कमी अभी भी है.

दिल्ली हाईकोर्ट के रिसेप्शन के पास हुए विस्फोट के तुरंत बाद सरकार का बयान आता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, अभी नहीं बता सकते. कुछ ही समय बाद हूजी (आतंकी संगठन) ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ले ली. फिर नाम आया इंडियन मुजाहिदीन का. मेल में बताया गया कि इस धमाके में हूजी (हरकत उल जेहादी इस्लामी) की नहीं, इंडियन मुजाहिदीन की भूमिका है. आईएम ने धमाके की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेने के साथ धमकी भी दी कि अभी और विस्फोट होंगे. तीन दिनों के बाद भी जांच के नाम पर एनआईए (नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी) देश के सामने कुछ ख़ास बता पाने की हालत में नहीं थी. बहरहाल, इस धमाके में पीईटीएन का प्रयोग पहली बार हुआ और यह ख़बर आई कि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ सेना में होता है और पड़ोसी देश या किसी और देश से इसकी आपूर्ति की भी आशंका जताई गई. दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ ख़ुफ़िया विभाग की पोल भी इस धमाके से खुल गई. तीन महीने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट के पास एक धमाका हुआ था. हालांकि उसमें जान-माल की कोई क्षति नहीं हुई थी. फिर तीन महीने बाद एक और धमाका हो गया, लेकिन इस बीच सरकार ने क्या किया? हालत यह है कि उचित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे.

दिल्ली में हुए प्रमुख बम विस्फोट

7 सितंबर, 2011: हाईकोर्ट के गेट नंबर पांच के बाहर धमाका, 13 लोगों की मौत, 50 घायल
25 मई, 2011: दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर मामूली धमाका, कोई हताहत नहीं
19 सितंबर, 2010: जामा मस्जिद के पास विदेशी पर्यटकों की बस पर गोलीबारी, दो घायल
27 सितंबर, 2008: महरौली बाज़ार में एक देसी बम फेंका गया, तीन लोगों की मौत
13 सितंबर, 2008: अलग-अलग जगहों पर हुए धमाकों में 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए
14 अप्रैल, 2006: जामा मस्जिद के प्रांगण में दो धमाके हुए, करीब 14 लोग घायल
29 अक्टूबर, 2005: सरोजिनी नगर, पहाड़गंज एवं गोविंदपुरी में धमाके, 59 लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल
22 मई, 2005: दो सिनेमाघरों में हुए धमाकों में दो मरे, कई घायल
18 जून, 2000: लाल क़िले के पास धमाके में आठ साल की बच्ची समेत दो लोगों की मौत
16 मार्च, 2000: सदर बाज़ार इलाक़े में धमाका, सात लोगों की मौत
6 जनवरी, 2000: पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के भीतर धमाका, 20 लोग घायल
3 जून, 1999: लाल किले और चांदनी चौक के बीच धमाके, करीब 27 लोग घायल
31 अगस्त, 1998 : तुर्कमान गेट के पास बम धमाके में एक की मृत्यु, 17 लोग घायल
14 जुलाई, 1997: लाल क़िले के पास हुए धमाकों में 18 लोगों की मौत
23 मई, 1996: लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में बम धमाकों में 16 लोगों की मौत

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

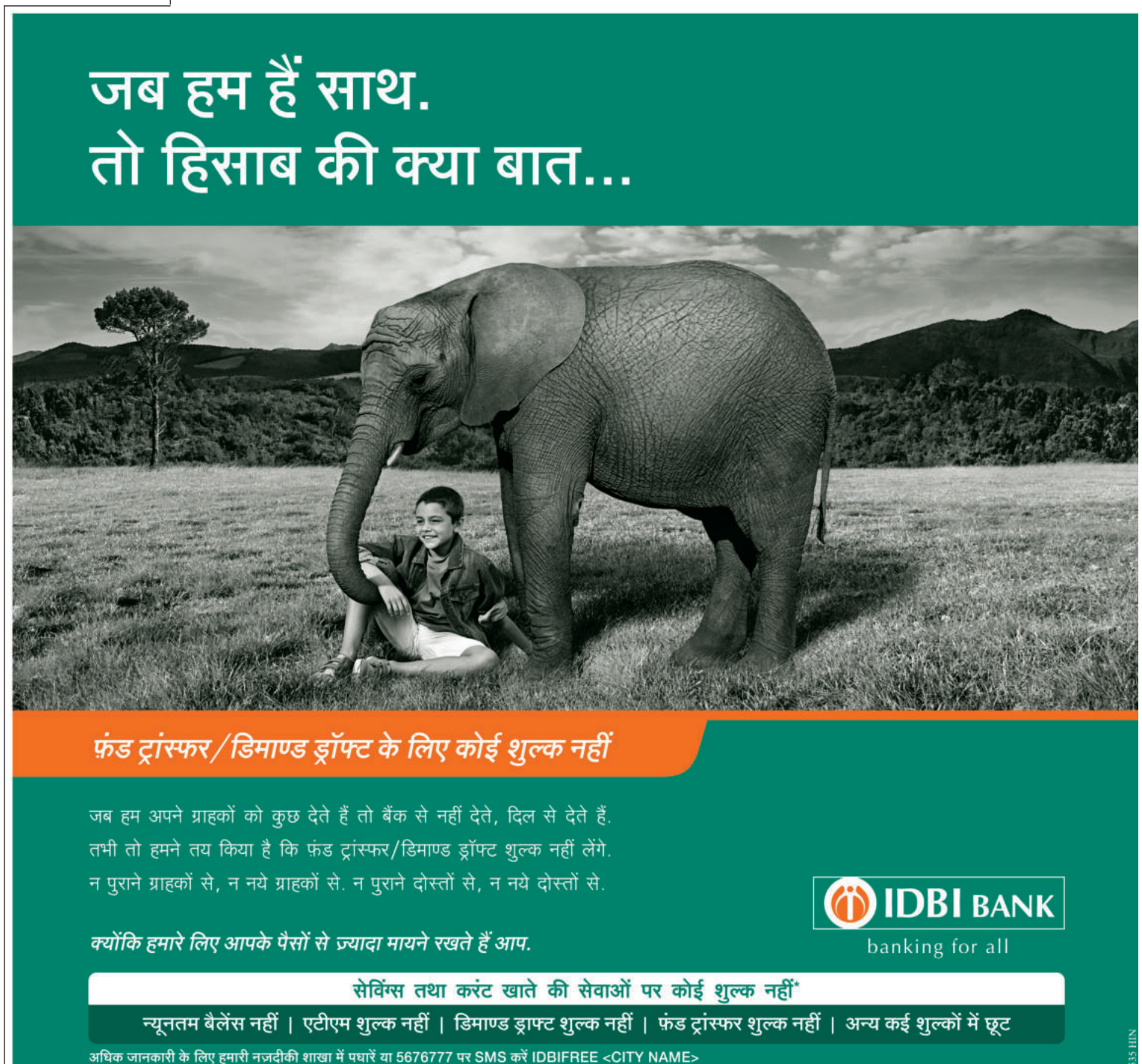

वाणी प्रकाशन के सेल्स ऑफिसर श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि पहले की अपेक्षा इस बार भीड़ भले ही कम रही हो, लेकिन बिक्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ा.

दिल्ली पुस्तक मेला

पाठकों के जोश से बाज़ार को उम्मीद

महेंद्र अवधेश

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि ये जहां रहती हैं, वह जगह अपने आप स्वर्ग हो जाती है. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन एवं द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के संयुक्त तत्वावधान में प्रगति मैदान में बीते 27 अगस्त से 04 सितंबर तक चले 17वें दिल्ली पुस्तक मेले में आए असंख्य लोगों ने कमोबेश यही संदेश दिया कि पुस्तकें आज भी मनुष्य की सच्ची मित्र हैं. पुस्तकों ने ई-बुक्स और सीडी का स्वरूप भले ही धारण कर लिया हो, लेकिन उनके प्रति लोगों की दिलचस्पी जस की तस है. मेले में आए अधिकांश लोग इस कोशिश में दिखे कि लौटते वक़्त उनके हाथ में कम से कम एक पुस्तक ज़रूर हो. पाठकों के मन का यह भाव बताता है कि पुस्तकों का बाज़ार आने वाले दिनों में और भी ऊंचाइयां हासिल करेगा. यात्रा एवं पर्यटन थीम पर आधारित इस मेले में इस बार लगभग 300 प्रकाशकों ने हिस्सा लिया और हॉल नंबर 8 से लेकर 12 तक उनके लिए 620 स्टॉल लगाए गए. नौ दिनों तक चले इस मेले में क़रीब ढाई लाख लोगों ने हिस्सा लिया.

सबसे बड़ी बात यह रही कि इस मेले के प्रति जो उत्साह बच्चों और युवाओं में दिखाई पड़ा, बुजुर्ग भी उसी जोश और जज़्बे के साथ यहां नज़र आए. हर एक की पसंद और ज़रूरत भले ही जुदा रही हो, लेकिन पुस्तकों के प्रति उनका लगाव देखते ही बन रहा था. 2 सितंबर को शनिवार का दिन था, लोग बाहर के महंगे और ज़रूरत से ज़्यादा मसालेदार भोजन से बचते हुए घर से बना खाना साथ लेकर आए थे. यानी एक-दो राउंड घूमने के बाद लंच और फिर ख़रीददारी का फाइनल राउंड. प्रवेश के लिए टिकट ख़रीदने वालों की ठीकठाक भीड़ थी और उनका जोश उनकी संख्या को मात कर रहा था, मानो वे किसी नई मूवी का टिकट ख़रीद रहे हों. बढ़ती महंगाई ने पाठकों के हाथ सिकोड़ दिए हैं, वे महंगी किताबें चाहकर भी नहीं ख़रीद पाते, इसलिए इस बार पुस्तकों के पेपरबैक संस्करणों की ज़बरदस्त मांग रही और वे बिके भी ज़्यादा. जैसा कि एक पाठक ने कहा कि दो साजिल्द पुस्तकों की क़ीमत पर हम तीन या चार पेपरबैक पा सकते हैं. सुरक्षा के लिए हम उन पर ब्राउन पेपर चढ़ा लेंगे. ज़्यादातर ख़रीददारी सौ रुपये से लेकर दो सौ रुपये मूल्य वाली पुस्तकों की हुई. गृहिणियों और पेंशनधारी बुजुर्गों ने अपनी ज़्यादातर ख़रीददारी इसी मूल्य वर्ग के इर्द-गिर्द केंद्रित रखी.

अन्ना हजारे, किरण बेदी और चेतन भगत

मेले में अन्ना हजारे और किरण बेदी की पुस्तकों की खासी धूम रही. हिंदी में सुदर्शन भाटिया कृत क्रांतिदूत अन्ना हजारे और अंग्रेजी में प्रतीक्षा एम तिवारी कृत अन्ना हजारे: द न्यू रिवोल्यूशन को लोगों ने काफी पसंद किया और इनकी जमकर ख़रीददारी की. डायमंड पॉकेट बुक्स के एरिया मैनेजर संदीप श्रीवास्तव एवं नारायण शर्मा पुस्तकों के प्रति पाठकों के रुझान को देखकर काफी ख़ुश थे. संदीप ने कहा कि लोगों ने सिर्फ़ पुस्तकें पसंद ही नहीं कीं, बल्कि उन्होंने यथासंभव ख़रीददारी भी की. नारायण शर्मा ने बताया कि अन्ना हजारे पर आई पुस्तकों की उन्होंने 30 हज़ार प्रतियां बेचीं. किरण बेदी की कई पुस्तकों ने पाठकों को आकर्षित किया, जिनमें मुद्दे और दृष्टिकोण, कब तक सहोगे एवं हिम्मत है! आदि प्रमुख रहीं. युवाओं के एक बड़े वर्ग में अंग्रेजी लेखक चेतन भगत छाए रहे. उनकी पुस्तकों के हिंदी संस्करण की काफी मांग रही. सफल उद्योगपति नारायण मूर्ति, रतन टाटा और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित पुस्तकें भी जमकर बिकीं. इसके अलावा युवाओं का रुझान मुख्यत: करियर ओरिएंटेड, मोटिवेशन, आरटीआई, बिजनेस मैनेजमेंट आदि विषयक पुस्तकों की ओर रहा. डायमंड पॉकेट बुक्स के स्टाल पर मिलीं मैथ ऑनर्स की छात्रा निधि ने दो किताबें ख़रीदीं, एक अन्ना हजारे पर सुदर्शन भाटिया की और दूसरी जोगिंदर सिंह की पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें. निधि अन्ना को नहीं जानतीं, केवल टीवी पर देखा है और यह जाना-समझा कि वह देश के लिए लड़े. इसलिए उनके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा पैदा हुई और उन्होंने नज़र पड़ते ही यह किताब ख़रीद ली. जोगिंदर सिंह की किताब इसलिए ख़रीदी कि शीर्षक आकर्षक लगा. जबकि निधि की सहेलियों ने रेसिपी की किताबें ख़रीदीं.

वाणी प्रकाशन के सेल्स ऑफिसर श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि पहले की अपेक्षा इस बार भीड़ भले ही कम रही हो, लेकिन बिक्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. लोग आए और पसंद की पुस्तकें मिलने पर उन्हें ख़रीदा भी, यह काफी संतोष की बात है. वाणी प्रकाशन ने अपनी पुस्तकों पर 10 फ़ीसदी की छूट दी. यहां कहानियों एवं कविताओं के संकलनों के अलावा कई बड़े लेखकों के उपन्यासों की ख़रीददारी पाठकों ने की. राजपाल एंड संस प्रकाशन के स्टॉल पर उपन्यास और ग़ज़ल संग्रह ख़रीदने वालों की भीड़ दिखाई दी. यहां उर्दू शायरी के प्रति दिलचस्पी रखने वाले कई बुज़ुर्ग भी दिखे, जिन्होंने निदा फाजली, अहमद फराज, शहरयार, फिराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूंनी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, अख्तर शीरानी, सरदार जाफरी, जिगर, जोश, जौंक, मजाज और कतील शिफाई जैसे प्रख्यात शायरों के ग़ज़ल संग्रह ख़रीदने में रुचि दिखाई. यहां सेल्स मैनेजर चंद्रशेखर चतुर्वेदी एवं प्रणव ने बताया कि आत्मकथात्मक और मोटिवेशन से संबंधित किताबों की बेहद मांग रही. लोगों के कम संख्या में आने का मुख्य कारण अन्ना हजारे का आंदोलन रहा. राजकमल प्रकाशन के मुकेश झा ने कहा कि मेला अगस्त में लगा, इसलिए भीड़ कम रही, बावजूद इसके हिंदी पुस्तकों का बाज़ार काफी बढ़ा है. ई-बुक्स संस्करण की काफी मांग रही. राजेंद्र यादव कृत मुबारक़ पहला क़दम और 25 वर्ष-25 कहानियां आदि की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई. मुकेश ने बताया कि उनके प्रकाशन ने हिंदी पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे हिंदी पुस्तकों के प्रति लोगों में रुचि पैदा होगी.

राजकमल प्रकाशन के अनूठे प्रयास

राजकमल प्रकाशन समूह ने पाठकों को पुस्तकों के क़रीब लाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं पेश की हैं. इसके तहत पास इट ऑन, पुस्तक ऋण, पाठक पुस्तक पुरस्कार और घर बैठे मनचाही किताब जैसी योजनाओं के माध्यम से पाठकों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक माहेश्वरी के अनुसार, उनके प्रकाशन समूह ने अपने 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पास इट ऑन योजना शुरू की, जिसके तहत सात बेस्ट सेलर पुस्तकें देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पंचायतों एवं पुस्तकालयों में इस उद्देश्य के साथ रखी गईं कि लोग उन्हें प्राप्त करेंगे और पढ़ने के बाद आगे अन्य लोगों को देते रहेंगे. इसी तरह पत्र लेखन और समीक्षा लेखन को बढ़ावा देने के लिए पाठक पुस्तक पुरस्कार योजना है, जिसके तहत श्रेष्ठ पत्र लेखन के लिए तीन सौ रुपये और श्रेष्ठ समीक्षा लेखन के लिए एक हज़ार रुपये मूल्य की पुस्तकें दी जाएंगी. राजकमल ने पुस्तक मित्र योजना भी शुरू की है, जिसमें एक हज़ार रुपये जमा करके सदस्य बनते ही पाठक को दो सौ रुपये की मनपसंद पुस्तकें दी जाती हैं और आजीवन हर वर्ष दो सौ रुपये की पुस्तकें देने का प्रावधान है. पुस्तक ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए एक हज़ार रुपये देकर पुस्तक मित्र योजना की सदस्यता लेनी होगी. इस योजना में दस हज़ार रुपये तक की पुस्तकें ऋण स्वरूप दी जाएंगी. लाभार्थी को देयराशि का भुगतान एक वर्ष के भीतर करना होगा. लाभार्थी के पास मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, पैनकार्ड, बैंक-डाकघर खाता होना अनिवार्य है और उसे अपने क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से अनुमोदन भी हासिल करना होगा. मेले के अंतिम दिन राजकमल प्रकाशन को तीन पुरस्कार मिले. राजकमल को उक्त पुरस्कार बच्चों पर केंद्रित मेरी पहली किताब, कला पर केंद्रित प्रगति और प्रगतिष्ठ, मुझे ऐसे पढ़ाओ, प्रकाशन समाचार और विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लिए दिए गए.

बच्चों में दिखा ग़ज़ब का उत्साह

हॉल नंबर 8 में स्टेशनरी के स्टॉल थे. बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ वहां जमकर ख़रीददारी की. मनपसंद पेंसिलें, शॉर्पनर, कलर्स, नोटबुक्स, ड्राइंगबुक्स और मैप पाकर वे काफी ख़ुश दिखे. यह सारा सामान यहां 10 से 20 फ़ीसदी के डिस्काउंट पर उपलब्ध था. हॉल नंबर 11 में दिल्ली प्रेस का स्टॉल था, जहां बच्चों के लिए कई पुस्तकें उपलब्ध थीं, जैसे लिटिल स्पाइडर फर्स्ट वेब, व्हाय आई एम सो टॉल, दि शीप एंड दि पिग, लेजी संडे फंडे एवं लिटिल टुप्पन.

ई-बुक्स और सीडी

बच्चों के साथ मेले में आए अधिकांश अभिभावकों का प्रयास ऐसी चीजें खोजने में ज़्यादा था, जो उन्हें आसानी से पढ़ना-लिखना सिखा सकें. यही वजह थी कि ई-बुक्स और सीडी के प्रति लोगों की खासी दिलचस्पी रही और उन्होंने इनकी ख़रीददारी भी की. एस चंद पब्लिकेशन और दिल्ली प्रेस समूह ने विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों पर ई-बुक्स और सीडी की एक विशाल सीरीज पेश की.

ओल्ड इज गोल्ड

राजेंद्र यादव का उपन्यास सारा आकाश, श्रीलाल शुक्ल की कालजयी रचना राग दरबारी, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान और जयशंकर प्रसाद की कामायनी को बड़ी संख्या में लोगों ने पसंद किया.

कई लोग हुए निराश

दिल्ली के नजफगढ़ निवासी धर्मेंद्र सिंह चौधरी मेले में बड़ी आशा के साथ आए थे. उन्होंने हिंदी विषय से एमए किया और हिंदी साहित्य से उनका काफी जुड़ाव रहा है. वह दिनकर और विद्यापति की पुस्तकें तो पा गए, लेकिन रेणु की परती परिकथा समेत कई किताबें उन्हें लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल सकीं. इसी प्रकार उदयपुर (राजस्थान) से आए अर्जुन सिंह अपनी पीएचडी के सिलसिले में अपने मित्र के साथ किताबों की एक लंबी सूची लिए इधर-उधर घूमते रहे, लेकिन एक भी किताब नहीं पा सके.

विश्व पुस्तक मेले से उम्मीद

प्रकाशकों को अगले वर्ष यानी 2012 की शुरुआत में लगने वाले विश्व पुस्तक मेले से काफी उम्मीदें हैं. यह विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से शुरू होगा और 4 मार्च तक चलेगा. इस मेले में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी प्रकाशकों द्वारा हिस्सा लेने की उम्मीद है.

साथ में राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

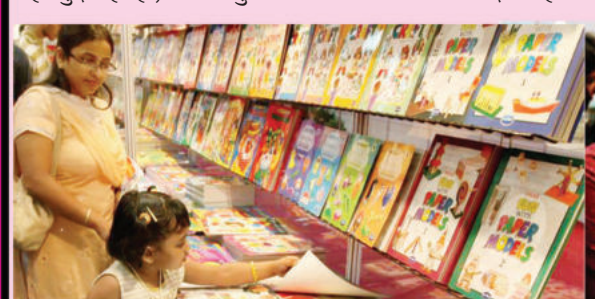

मेरी दुनिया.... आडवाणी और रथ यात्रा

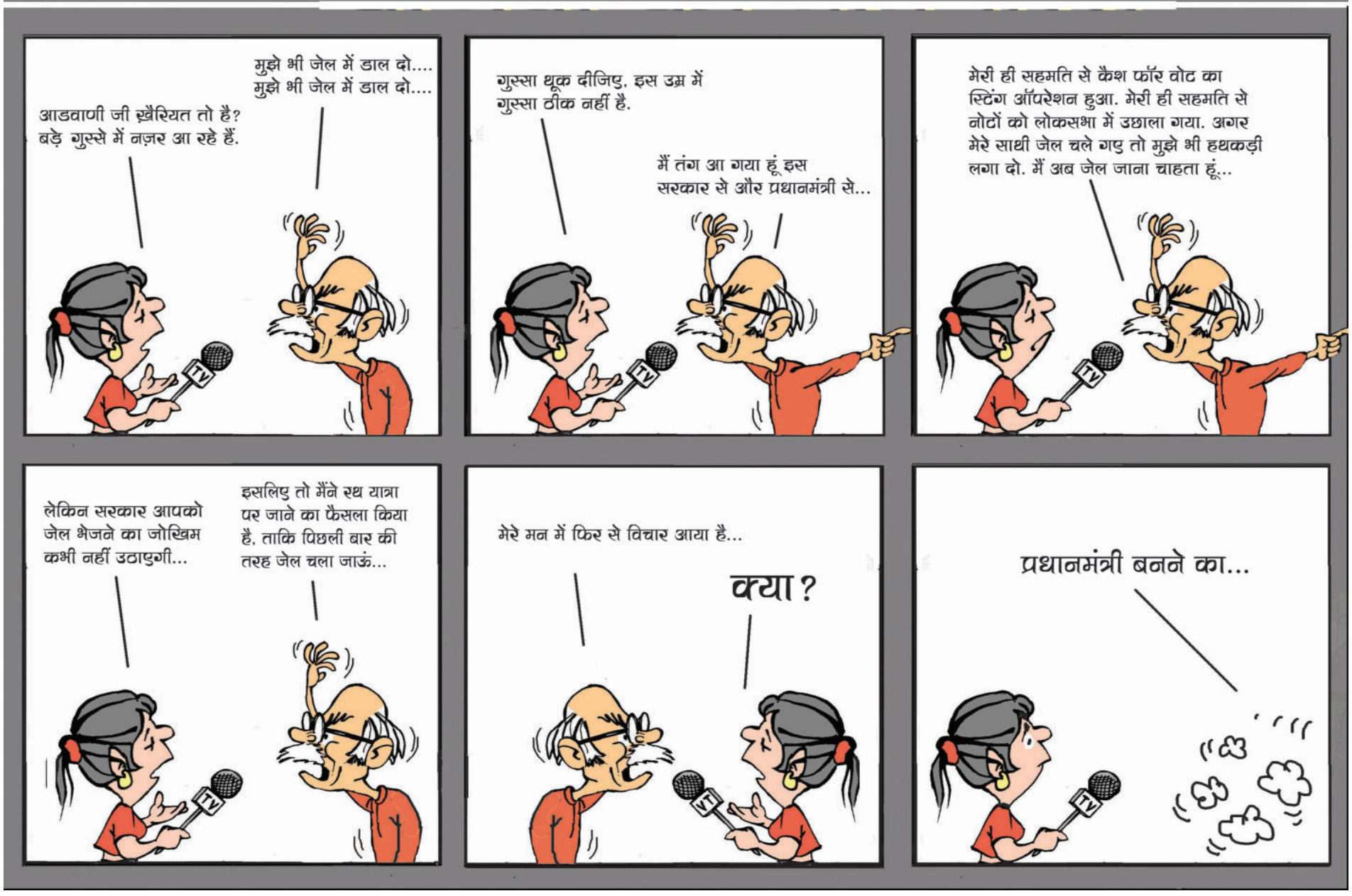

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिए फाउंडेशन ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का भी काम कर रहा है. कटराथल गांव के कान सिंह और सुशीला देवी अपने फॉर्म हाउस में देशी-विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

तस्वीर और तक़दीर दोनों बदल रही है

बीस साल का समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता. वह भी एक ऐसे इलाक़े के विकास के लिए, जहां पानी की कमी हो, ज़मीन अर्द्ध रेतीली हो. राजस्थान का शेखावाटी भी एक ऐसा ही इलाक़ा है. यहां की अर्द्ध रेतीली ज़मीन पर विकास की धारा बहाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आज 20 साल बाद आप यहां की ज़मीन पर न सिर्फ़ हरा सोना पैदा होते देख सकते हैं, बल्कि विकास की एक बिल्कुल अलग तस्वीर से भी रूबरू होते हैं. चाहे यहां के किसान हों, महिलाएं हों, युवक-युवतियां हों, हर किसी की आंखों में एक नया सपना है, एक नई उम्मीद है, एक नई सोच है.

शशि शेखर

आज से लगभग 20 साल पहले इस क्षेत्र में मोरारका फाउंडेशन ने विकास की नई इबारत लिखने का काम शुरू किया. इस फाउंडेशन ने विकास नाम के शब्द को पुन: पारिभाषित करने की सोच के साथ काम करना शुरू किया. रासायनिक खाद के इस्तेमाल से खेतों की घटती उर्वरता को बचाने के लिए जैविक खेती की नई क्रांति का आगाज किया. पानी की कमी से निपटने के लिए खेती और सिंचाई की नई तकनीक ईजाद की. महिलाओं के लिए सैकड़ों स्वयं सहायता समूह और सांझा चूल्हे बनाए गए. विकलांग और बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए. कल तक महाजनों से क़र्ज़ लेकर खेती करने वाले शेखावाटी के किसानों की समृद्धि देखकर आप उन सरकारी नीतियों के बारे में क्या कहेंगे, जो मानो किसानों के विकास के लिए नहीं, बल्कि उनके विनाश के लिए बनाई गई हों. सरकार की ऐसी कृषि नीति का क्या फ़ायदा, जो इस देश में एक नया विदर्भ, एक नया बुंदेलखंड पैदा कर देती है.

शेखावाटी के झुंझुनू, चुरु और सीकर ज़िले के किसान मोरारका फाउंडेशन के संपर्क में आने और यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद अपनी ज़मीन में जैविक खेती कर रहे हैं और उनकी लगन, मेहनत और अपनी ज़मीन से प्यार को देखना और समझना किसी के लिए एक सुखद अनुभव से कम नहीं है. ये किसान ख़ुद ही कम लागत में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश जैसी जैविक खाद और कीटनाशक बना लेते हैं. पानी की कमी से निजात पाने के लिए मोरारका फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक ईजाद की है, जिसका नाम हाइड्रोपोनिक तकनीक है. इसके बारे में मोरारका फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक मुकेश गुप्ता बताते हैं कि इस तकनीक का विकास उन्होंने सिंगापुर सरकार के अनुरोध पर किया है. दरअसल, ज़मीन की कमी की वजह से सिंगापुर सरकार ने फाउंडेशन से रूफ (छत) गार्डेनिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित करने का अनुरोध किया था. मुकेश गुप्ता बताते है कि इस तकनीक के तहत सब्जी की खेती आसानी से की जा सकती है. इस तकनीक में पाइप की कई सतहें बिछाकर उनमें छोटे-छोटे प्लास्टिक ग्लास डाल दिए जाते हैं और फिर उनमें पौधे तैयार किए जाते हैं और पानी को रिसाइक्लिंग विधि से पौधों तक पहुंचाया जाता है.

इसी तरह फाउंडेशन ने ट्रे कल्टीवेशन तकनीक का भी विकास किया है, जिसमें बहुत ही कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सकती है. फाउंडेशन के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब यहां के हज़ारों किसानों ने रासायनिक खाद या पेस्टीसाइड का इस्तेमाल पूर्णत: बंद कर दिया है. मोरारका फाउंडेशन इन किसानों को न सिर्फ़ जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि उन्हें उनकी उपज का उचित दाम और एक बड़ा बाज़ार भी मुहैय्या करा रहा है. देश भर में फैले डाउन टू अर्थ रिटेल सेंटर किसानों की उपज को देश-विदेश तक पहुंचाने के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ाने का काम कर रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में भी झुंझुनू ज़िला अब एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहा है तो इसके पीछे भी फाउंडेशन की ही सोच है. सीकर ज़िले के बेरी गांव के कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी में मदद दी जा रही है. मोरारका फाउंडेशन ने मुंबई के एक शिक्षण संस्थान, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑनलाइन उच्च शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराता है, से समझौता करके यह सुविधा अब इस स्कूल को भी दिलवा दी है और आगे वह इस योजना को अन्य स्कूलों में भी लागू करने की तैयारी कर रहा है.

शेखावाटी की ग़रीब महिलाओं के लिए फाउंडेशन ने स्वयं सहायता समूह के ज़रिए रोज़गार के नए साधन उपलब्ध कराए हैं. इस वक़्त शेखावाटी के 128 गांवों में 350 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे क़रीब दस हज़ार से भी ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं. मोरारका फाउंडेशन अपने रिटेल सेंटर के लिए ज़रूरी पेपर बैग का निर्माण भी इन्हीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से करा रहा है. इसके अलावा पचास से सौ तक के समूह में ये महिलाएं छोटे-मोटे काम, जैसे बंधेज बनाने या फल-सब्जी बेचने का काम भी करती हैं. ज़रूरत पड़ने पर इन्हें समूह से ही ऋण मिल जाता है. ये महिलाएं आज हर महीने दो-ढाई हजार रुपये कमा लेती हैं. शेखावाटी ग्रामीण बैंक ने इन्हें छोटे-मोटे काम शुरू करने के लिए ऋण भी दिया है. फाउंडेशन की ओर से गांव की ग़रीब महिलाओं के लिए सांझा चूल्हा भी चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत ग़रीब महिलाएं, जो कभी खेतों से लकड़ियां चुनकर अपना चूल्हा जलाती थीं, आज रसोई गैस पर खाना बना रही हैं. 4-5 महिलाएं एक साथ एक केंद्र पर पहुंच कर सांझा गैस रसोई योजना का लाभ उठा रही हैं. ईंधन का मासिक ख़र्च जो पहले हज़ार रुपये से ज़्यादा था (जलाई गई लकड़ी और कंडों की क़ीमत जोड़कर), वह अब सिर्फ़ तीन-साढ़े तीन सौ रुपये आता है. साथ ही हर सेंटर को चलाने के लिए एक महिला को हेड भी बनाया गया है यानी यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए रोज़गार के एक अवसर के रूप में भी सामने आई है. इसके अलावा ऑर्गेनिक टिफिन स्कीम के ज़रिए भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं. सीकर ज़िले के बेरी गांव की सुशीला कंवर और मूल सिंह को लोगों तक ऑर्गेनिक खाना पहुंचाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. इस स्कीम के तहत छात्रों, नौकरीपेशा या अस्पताल या कचहरी में आने वाले लोगों तक ऑर्गेनिक टिफिन पहुंचाया जाता है. इसके लिए नवलगढ़ के तहसील कार्यालय, 3 अस्पतालों और मोरारका ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर को कलेक्शन सेंटर बना दिया गया है, जहां से ऑर्गेनिक टिफिन लोगों तक पहुंचाए जाते हैं. शेखावाटी के लोगों को बना-बनाया ऑर्गेनिक खाना मिल सके, इसलिए नवलगढ़ में एक ऑर्गेनिक रेस्तरां भी खोला गया है.

मोरारका फाउंडेशन की सोच और यहां के लोगों की भागीदारी को देखते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि आने वाले समय में शेखावाटी जैविक खेती और ग्रामीण विकास का एक ऐसा मॉडल बन जाएगा, जिसे इस देश के संपूर्ण विकास के लिए अपनाना ही होगा. हमारी सरकार को विकास की सही परिभाषा को समझना ही होगा. वैज्ञानिक खेती के नाम पर ज़मीन और इंसान के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा. ज़ाहिर है, तस्वीर और तकदीर सिर्फ़ शेखावाटी की नहीं, बल्कि पूरे देश की बदलनी चाहिए. इसके लिए सरकार और नीति बनाने वाले अधिकारियों को शेखावाटी से सबक लेना चाहिए.

ग्रामीण लड़कियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से 2010 में मोरारका फाउंडेशन ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की थी. एक साल बाद यह योजना अब सिक्किम तक पहुंच गई है. सिक्किम से आईं लड़कियां फाउंडेशन के जयपुर स्थित कार्यालय से ट्रेनिंग पा चुकी हैं और अब वे सिक्किम के किसानों को जैविक खेती के गुर बता रही हैं, वह भी स्थानीय भाषा में. सिक्किम से आईं लड़कियां अब अपने प्रदेश जाकर इस योजना को और विस्तार देने वाली हैं. झुंझुनू ज़िले की नवलगढ़ तहसील के विकलांग युवाओं के लिए भी मोरारका फाउंडेशन ने सौर लालटेन के ज़रिए रोज़गार उपलब्ध कराया है. घोड़ीवारा कलां गांव की नीलम कंवर पोलियोग्रस्त हैं. तीन बच्चों की मां नीलम का पति मज़दूरी करके किसी तरह परिवार चलाता है. फाउंडेशन ने नीलम को सौर ऊर्जा से चलने वाली 25 लालटेन और एक सौर पैनल उपलब्ध कराया है. इसी तरह कालू भाट और राधेश्याम जैसे विकलांग युवाओं को भी इस योजना से जोड़ा गया है. वे इन लालटेनों को दिन में चार्ज कर लेते हैं, जिन्हें गांव वाले अपनी ज़रूरत के हिसाब से किराए पर ले जाते हैं. छात्रों के लिए 5 रुपये और अन्य लोगों के लिए 10 रुपये प्रति रात किराया निर्धारित है. शादी-समारोहों में और दुकानदारों एवं छात्रों द्वारा इन सौर लालटेनों का इस्तेमाल किया जाता है.

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिए फाउंडेशन ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का भी काम कर रहा है. कटराथल गांव के कान सिंह और सुशीला देवी अपने फॉर्म हाउस में देशी-विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं. एक तो जैविक खेती, दूसरे यहां के ग्रामीण परिवेश का सुखद अनुभव किसी को भी दोबारा आने के लिए मजबूर कर देता है. इसके अलावा नवलगढ़ के सिगनौर गांव के तीन किसान परिवार भी इस योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए काम कर रहे हैं. ये लोग अपने घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनके खाने-पीने से लेकर घूमने तक का इंतज़ाम करते हैं. बदले में इन परिवारों को उचित पैसा भी मिल जाता है. फाउंडेशन ने पूरे राजस्थान में लगभग 500 ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण पर्यटन के लिए प्रशिक्षित किया है. बहरहाल, शेखावाटी की यह विकास यात्रा पिछले 20 सालों से लगातार जारी है. मोरारका फाउंडेशन की सोच और यहां के लोगों की भागीदारी को देखते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि आने वाले समय में शेखावाटी जैविक खेती और ग्रामीण विकास का एक ऐसा मॉडल बन जाएगा, जिसे इस देश के संपूर्ण विकास के लिए अपनाना ही होगा. हमारी सरकार को विकास की सही परिभाषा को समझना ही होगा. वैज्ञानिक खेती के नाम पर ज़मीन और इंसान के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा. ज़ाहिर है, तस्वीर और तकदीर सिर्फ़ शेखावाटी की नहीं, बल्कि पूरे देश की बदलनी चाहिए. इसके लिए सरकार और नीति बनाने वाले अधिकारियों को शेखावाटी से सबक लेना चाहिए.

shashishekhar@chauthiduniya.com

कांग्रेस ने जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी है, उससे तो ऐसा लगता है कि मुद्दे को पहचानने का उसका सेंस कमज़ोर हो गया है.

कैश फॉर वोट की कहानी में कई मोड़ हैं. किसने किसे, कहां और कैसे धोखा दिया, यह समझना भी बड़ा कठिन है. सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार वोटिंग से पहले बहुमत में नहीं थी.

धनवान बनने के लोभ का कारण

महावीर प्रसाद आर मोरारका

असमान वित्त वितरण से पैदा हुए अनेक ख़तरे हैं. खाली व्यापार-धंधों में ही नहीं, बल्कि फौज में या सेना में कहीं भी देख लीजिए, एक सिपाही की जितनी आमदनी होती है, उसके अफसर को उससे कई गुना ज़्यादा होती है. परिणामस्वरूप काफी असंतोष होता है. इसी तरह न्यायालय में, विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह असमान वित्त वितरण की वजह से घोर असंतोष फैला हुआ है और मानव अपनी बुद्धि या योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता. समान वित्त वितरण आजमाई हुई चीज़ है, कोई नई बात नहीं. यह पूर्ण रूप से संभव है. आज यह कुछ अंशों में वर्गों के बीच विद्यमान भी है, पर व्यक्तियों में नहीं है. एक राज या बढ़ई को अगर 8 रुपये या 10 रुपये रोज़ाना मज़दूरी मिलती है तो दूसरे राज या बढ़ई को भी लगभग उतनी ही मिलती होगी. भारत के समस्त राज या बढ़ई इसी तरह क़रीब-क़रीब समान आय वाले होंगे. समस्त पोस्टमैन भी क़रीब-क़रीब समान आय वाले होंगे, पर एक पोस्टमैन या एक अध्यापक से एक डॉक्टर, वकील या व्यापारी की आय कई गुना ज़्यादा है. अतः यह असमान वित्त वितरण दुखदायी हो जाता है. अब अगर इस समान आय की पद्धति का सब वर्गों में विस्तार किया जा सके तो पहेली सुलझ सकती है.

हो सकता है कि कोई व्यक्ति अद्भुत प्रतिभा वाला निकल आए और अपनी श्रेणी के दूसरे कार्यकर्ता से कई गुना ज़्यादा काम भी कर सके और शायद कोई इस ढंग का भी निकल आए, जो अपनी श्रेणी के दूसरे कार्यकर्ता से आधा भी न कमा सके, पर ये बहुत अल्प संख्या के ही प्राणी होंगे. ज़्यादातर तो औसत योग्यता या प्रतिभा के ही व्यक्ति मिलेंगे. समान वित्त वितरण किसी उद्योग में काम करने मज़दूरों में या सार्वजनिक सेवा में लगे सरकारी नौकरों में लागू कर दिया जाए, तो बहुत अंशों में यह प्रथा सफल भी हो सकती है. आप पूछ सकते हैं कि फिर भाई, जब आपको समान मिलेगा तो फिर यह तो संभव है ही कि कई लोग तो बचाकर धीरे-धीरे धनिक बन जाएंगे और कई लोग धीरे-धीरे ज़्यादा ग़रीब बन जाएंगे. क्या फ़ायदा है, एक बार आपने समान बंटवारा कर भी दिया तो? मानव की योग्यता या बुद्धि का तो आप समान बंटवारा कर नहीं सकते, फिर यह बहस फिज़ूल हो जाती है. मानव जैसा है, वैसा ही रहेगा, उसकी स्थिति को बदल सकना कैसे संभव होगा?

शायद आप ठीक कहते हों, पर मैं समझता हूं, जब समान वित्त वितरण हो जाएगा और कोई धनिक या कोई दरिद्र ही नहीं रहेगा, तो धनिक बनने में आज जो विशेष आकर्षण है, वह भी न रहेगा. बचा सकने की बात तो ख़ैर निर्मूल है ही, पर किसी भी उपाय से अगर मानव धनिक बन सकता है, वह भी बनने में उसे कुछ विशेष फ़ायदा या अधिकार नहीं मिल पाए तो उसे धनिक बनने का प्रयत्न करने में कोई आकर्षण नहीं रहेगा. मानव अपनी योग्यता, बुद्धि या प्रतिभा का पूरा-पूरा उपयोग करके सुख प्राप्त करने का प्रयास ज़रूर करेगा और यह समान वित्त वितरण हो जाने से ही उसे उपलब्ध भी होगा. समान वित्त वितरण संभव है और इसके स्थायी रूप से चल सकने में कोई कठिनाई नहीं है. किसको कितना मिलना चाहिए, इस विवाद का भी अंत हो जाएगा. सब अपनी-अपनी प्रतिभा द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर सकें, इसके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मिलेगा.

दरिद्रता पर किसी का अधिकार नहीं

प्रश्न उठता है कि जब समान रूप से ही बंटवारा होना है तो अपनी अपनी योग्यता या प्रतिभा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकने का विस्तृत क्षेत्र मिलने का क्या अर्थ? लोग अपनी योग्यता या प्रतिभा का उपयोग ही क्यों करेंगे? जब एक कम अक्ल वाला आदमी को या ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति को समान ही मिलना है तो क्यों कोई व्यर्थ काम करेगा? क्यों दिमाग़ लगाएगा? शंका सही है. मानव-मानव की संपत्ति में, आय में जो फ़र्क है, उसे शायद प्रयत्न से समाप्त किया जा सकता है, पर योग्यता या प्रतिभा कभी छिप नहीं सकती. बहुत ही योग्य या प्रतिभाशाली व्यक्ति पूर्ण श्रम करते हुए भी भारत में आज क़रीब-क़रीब भूखों मरते हैं, जबकि कम अक्ल या बिल्कुल मूर्ख, निर्दयी-स्वार्थी या धूर्त करोड़पति बने बैठे हैं. कुछ काम न करके भी निठल्ले बैठे-बैठे भी इनके करोड़ों रुपयों में श्रीवृद्धि ही होती रहती.

मान लीजिए, देश के एक महान वैज्ञानिक ने कोई मानवोपयोगी नया यंत्र आविष्कृत किया और आपकी संसद या सरकार ने प्रसन्न होकर उस वैज्ञानिक को 2 लाख रुपया पारितोषिक दे दिया (यह होना भारत में तो असंभव सा ही है) तो भी वह वैज्ञानिक उन चालाक व्यापारियों के सामने बिल्कुल दरिद्र या निर्धन ही है, जिन्होंने गेहूं का सारा स्टाक खरीद कर गोदामों में भर लिया है और बहुत ऊंचे भाव में बेचा है या जो असली घी के बदले में वनस्पति घी देते हैं या जो कपड़े के ताने-बाने में सूत के बदले सिर्फ़ मांडी ही भर देते हैं या जो दवाइयों या खानपान की तमाम चीज़ों में मिलावट करके बेचते हैं या जो कई ही फ़सल कम होगी, यह जानकारी पहले से हासिल कर लेते हैं या जो झूठे विज्ञापनों से प्राप्त धन से समाचारपत्रों को समृद्ध बनाए हुए हैं या जो अनेक घृणित कार्यों से करोड़ों-अरबों रुपये इकट्ठा किए हुए हैं. जबकि बहुशिक्षित, होनहार आदर्श आदमी, जो मानवीय ज्ञान शक्ति बढ़ाने में प्रयत्नशील है, उसे बहुत ही कम धन प्राप्त हो पाता है. इसलिए गुणों की अपेक्षा धन की महत्ता ज़्यादा होती है और समाज में हर जगह धनवान का समादर गुणवान की अपेक्षा ज़्यादा होता है. अगर धन का समान वितरण हो जाए तो गुणी पुरुष अपने आप अपने गुणों के कारण चमक उठेगा. वही समाज में मान्य होगा. उसको आदर्श मानकर बाक़ी दूसरे आदमी भी उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे. बिना गुणवान या प्रतिभा के धन का महत्व ही क्या है?

समाज की वर्तमान प्रचलित भावनाएं बदलनी होंगी. वित्त वितरण समान होने के बाद मानव का श्रेणी विभाजन उनकी प्रतिभा, सदाचार या गुणों पर ही आधारित होगा, वही तो उत्तम समाज होगा. मनुष्यों में फिर भी बड़े, मध्यम और छोटे लोगों की श्रेणी होगी ही, पर उनका मापदंड उनका धन न होकर उनकी बुद्धि, प्रतिभा या गुण ही होंगे. जो देश के लिए कला, विज्ञान या शिल्प में आदर्श स्थापित करेंगे, वे ही बड़े और महान माने जाएंगे. जो लोग देश के और अपने हित में जनसाधारण की सेवा में ही अपना-अपना कार्य समुचित ढंग से करते रहेंगे, वे ही मध्यम श्रेणी के या भले आदमी कहे जाएंगे और जो शठ, मूर्ख, धूर्त लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए बड़े या मध्यम लोगों के कार्य में रोड़ा अटकाएंगे, वे ही निम्न कोटि के छोटे आदमी माने जाएंगे. मापदंड तथ्यपूर्ण होगा, उस दिन रुपये की महत्ता घट जाएगी. सदाचार या गुणों की या नैसर्गिक प्रतिभा की ही ज़्यादा क़ीमत होगी, उनका ही समादर होगा. वही समाज ज़्यादा उपादेय, ज़्यादा पूज्य और आदरणीय होगा.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नद्रष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

पूरे तंत्र को सुधारने की ज़रूरत है

बार-बार कहने के बावजूद सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है. सरकार से मतलब सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि सरकार से मतलब पूरा सिस्टम, दारोगा से लेकर गृह सचिव तक. ये सब नशे की गोली खाकर सो रहे हैं और देश हर दूसरे-तीसरे महीने ख़तरे का सामना कर रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में तीन महीने के भीतर हुआ दूसरा बम धमाका हमारे सिस्टम के खोखलेपन और सबसे अंत में प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के नकारेपन को चीख-चीखकर बयान कर रहा है. अंग्रेजों के जमाने में तंत्र इतना बड़ा नहीं था, जितना आज है. उस समय थाने में दस सिपाही होते थे और सौ गांवों को कंट्रोल करते थे. सिपाही अकेला चला जाता था और लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि सरकार की साख थी, सरकार का इकबाल था. वह सिस्टम मुखबिरों के बल पर चलता था. पूरे इलाके में, चाहे वह शहर का मोहल्ला हो, शहर के थाना क्षेत्र का कोई भी हिस्सा हो या देहात के थाना क्षेत्र का कोई भी गांव हो, वहां से अपने आप लोग खबरें लेकर दारोगा के पास पहुंचते थे. दारोगा उन खबरों पर अपने विवेक से फैसला लेता था कि क्या करना है, लेकिन जानकारी उसके पास सब रहती थी. इसीलिए उन दिनों मामले बहुत आसानी से सुलझा लिए जाते थे.

आजादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दस सालों तक यह सिस्टम चलता रहा, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार ने इस सिस्टम को खाना शुरू कर दिया. मुखबिरों को मिलने वाला पैसा अफसर खाने लगे. मुखबिरों से मिलने वाली खबरें कम होने लगीं. किसी को इसकी चिंता नहीं हुई कि अगर मुखबिर नहीं रहेंगे, वे खबरें नहीं देंगे तो तंत्र काम कैसे करेगा. लूट, हत्या, बलात्कार, अलग-अलग तरह के अपराध और अब बड़े पैमाने पर आतंकवाद है. इनके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी. ऐसा नहीं है कि मुखबिरों के नाम पर सरकार के बजट में पैसा नहीं होता. पूरे तंत्र में खुफियागिरी के नाम पर अनकाउंटेड मनी (पैसा) खर्च होती है और उसका कोई लिखित हिसाब नहीं होता. इसी कारण यह पैसा भ्रष्टाचारी अफसरों या तंत्र के मुंह में चला जाता है. नतीजे के तौर पर सूचनाएं आनी बंद हो जाती हैं. ऐसा पिछले 25 सालों से हो रहा है. पहले इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब इसका दुष्परिणाम संसद से 3 किलोमीटर दूर पहुंच गया.

खुफिया सूचनाओं के अभाव में संसद पर भी आज से दस साल पहले हमला हुआ था, लेकिन संसद पर हमले को अगर हम अपवाद मानें तो अब जितने भी हमले इस देश में हो रहे हैं, वे इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि खुफिया सूचनाएं पुलिस तक नहीं पहुंचती. पुलिस के खुफिया अफसर चाहे वे आईबी में हों, सीआईडी में हों, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में हों, उनके सूत्र इस सरकार ने काट दिए. चूंकि मुखबिर नहीं हैं तो सरकार के पास सूचनाएं नहीं हैं. पैसा जरूर है, जिसे लोग खा-पी रहे हैं. कौन हैं इसके जिम्मेदार? आज के लोग जिम्मेदार नहीं हैं. इसकी शुरुआत आज से 20-25 साल पहले हुई थी, जबसे ये चीजें टूटने लगी थीं. जब आतंकवाद हमारे यहां ज़्यादा पैर पसारने लगा तो शायद अफसरों को लगा कि हम हर चीज आतंकवाद के सिर मढ़ दें और बच जाएं. इसी वजह से न केवल आतंकवाद, बल्कि किसी भी तरह के अपराध का कुछ भी पता नहीं चलता. न अपराध होने से पहले जानकारी आती है और न अपराध होने के बाद कोई केस खुलता है, न केस पर वर्कआउट होता है,

जितने भी हमले इस देश में हो रहे हैं, वे इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि खुफिया सूचनाएं पुलिस तक नहीं पहुंचती. पुलिस के खुफिया अफसर चाहे वे आईबी में हों, सीआईडी में हों, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में हों, उनके सूत्र इस सरकार ने काट दिए. चूंकि मुखबिर नहीं हैं तो सरकार के पास सूचनाएं नहीं हैं. पैसा जरूर है, जिसे लोग खा-पी रहे हैं. कौन हैं इसके जिम्मेदार?

क्योंकि केस के वर्कआउट में भी मुखबिरों की भूमिका होती है, जो बताते हैं कि इन-इन जगहों पर इन-इन लोगों ने वारदातें कीं.

अब पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं आती और आती भी है तो केवल उतनी, जिससे उन्हें हिस्सा मिलने में आसानी रहे. इस बहाने हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर सरकार और विपक्ष को प्रमुखता के साथ सोचना चाहिए. अगर उन्होंने नहीं सोचा तो देश में होने वाली न केवल आतंकवादी वारदातों को, बल्कि सामान्य अपराधों को भी पुलिस नहीं रोक पाएगी. अपराध के आंकड़े लगातार ऊपर जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मुखबिरों के जाल को सोच-समझ कर भ्रष्टाचार की वजह से, पैसा खाने की नीयत ने तबाह कर दिया है, छिन्न-भिन्न कर दिया है. इस तंत्र को फिर से खड़ा करने की ज़रूरत है. देश के गृह मंत्रालय को या प्रदेश की सरकारों को अगर यह बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर तय मानिए कि आज यह देश और इस देश के लोग उस जगह पहुंच गए हैं, जहां से नीचे गिरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा.

देश की सरकार, गृहमंत्री और गृह सचिव को चाहिए कि ये लोग बैठें और तत्काल पुलिस तंत्र को सुधारने के बारे में बात करें. लेकिन जब पुलिस तंत्र में सुधार की बात की जाए तो पुलिस के जवानों को मिलने वाले वेतन, सुविधाओं और उनके काम करने के तरीकों के ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए. इसलिए सोचना चाहिए, क्योंकि एक जवान अगर 24 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे लगातार काम करता है तो उसमें तनाव पैदा होना लाजिमी है. दिल्ली में 13 अगस्त की शाम पुलिस वाले बुला लिए गए, क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री को झंडा फहराना था. 13 अगस्त को बुलाए गए पुलिस वाले अगले 15 दिनों तक अपने घर नहीं जा पाए, क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो गया और इनमें से बहुतों की ड्यूटी लगातार लगी रही. इन जवानों के पास न खाने की सुविधा थी और न प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करने के साधन. ऐसा सिर्फ दिल्ली में इसी बार नहीं हुआ, बल्कि आजादी के बाद से ऐसा ही हो रहा है. बहुत सारे थानों में सिपाहियों के लिए रहने की जगह नहीं है, पुलिस वाले अपनी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा कहां करें, इसकी भी जगह नहीं है. यह मैं शहरों की बात कर रहा हूं. शहरों में वे या तो सिनेमा हॉल को पकड़ते हैं या किसी धर्मशाला को.

आज की महंगाई में हालत यह है कि पुलिस वाले काम के दौरान अपने पैसों से अगर कुछ खाना भी चाहें तो नहीं खा सकते. पचास या सौ रुपये खर्च करके एक या दो लोग खाना नहीं खा सकते. उन्हें बाहर का कोई भत्ता नहीं मिलता है कि वे खरीद कर खाएं और अगर मिलता भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि वह 5 या 10 रुपये से अधिक होगा. जवानों की सुविधाओं के बारे में सरकार नहीं सोच रही. जिन अफसरों ने पैसा खाने के चक्कर में मुखबिर तंत्र को तोड़ा, उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही. जैसा चल रहा है, उसी को सिस्टम मान लिया गया. शायद सोचने का वक़्त आ गया है. सोचिए, नहीं तो दिल्ली हाईकोर्ट जैसे धमाके इस देश के हर गली-मोहल्ले में होने लगेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

सोनिया गांधी के भरोसे कांग्रेस

सांसदों से संसद के भीतर अच्छे व्यवहार की उम्मीद कम ही की जाती है. बीते 27 अगस्त को अन्ना हजारे के मुद्दे पर यह देखने को मिला. सांसदों ने अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया और पूर्व की भांति वे एक-दूसरे पर चीखते-चिल्लाते नज़र नहीं आए, बल्कि उन्होंने एकजुटता दिखाई, लेकिन इसके बाद फिर से सदन की स्थिति वही हो गई है. रामलीला मैदान और पूरे देश में इन लोगों के ऊपर जो अविश्वास जताया गया, उसके बाद सांसद ओम पुरी और किरण बेदी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाने के मुद्दे के साथ वापस आए. संसद में एक-दूसरे पर चीखना, सामान फेंकना और अध्यक्ष के आसन के पास चला जाना सामान्य बात हो गई है, लेकिन यह कोई मनोरंजन नहीं है और न इसे मनोरंजन समझने की भूल करनी चाहिए. सांसदों को अगर अपनी गरिमा बरक़रार रखनी है तो उन्हें इसके लिए प्रयास करना होगा. कांग्रेस ने इस बीच बहुत अच्छे ढंग से अपना काम नहीं किया है. अन्ना हजारे के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या निकला?

संसद ने अन्ना की मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया. अन्ना ने भी इसे आधी जीत के रूप में ही स्वीकार किया. अन्ना के अनशन को ख़त्म कराने के लिए प्रधानमंत्री का संदेश लेकर विलासराव देशमुख गए. दोनों मराठी बोलते हैं और इस कारण कांग्रेस को लाभ हुआ तथा देशमुख अन्ना से मिल सके. अन्ना टीम के अन्य सदस्यों को बीच में आने का मौक़ा नहीं मिला और अन्ना द्वारा अनशन तोड़ने के फ़ैसले ने उनकी टीम को आश्चर्य में डाल दिया. कांग्रेस ने भाजपा के विरुद्ध फिर से अपनी पुरानी नीति अपना ली है. सदन में अरुण शौरी और नरेंद्र मोदी का मुद्दा ही छाया रहा. ऐसा लगता है कि इस प्रकरण के अलावा और कोई मुद्दा संसद के पास है ही नहीं. बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर चर्चा की तत्काल आवश्यकता है. उदाहरण के तौर पर भूमि अधिग्रहण विधेयक को ले सकते हैं. कांग्रेस ने यूपीए के अन्य सहयोगियों के ख़िलाफ़ भी अपना पत्ता खोला है. उसने खेल संगठनों को आरटीआई के दायरे में लाने की बात छेड़ दी है. अगर देखा जाए तो शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल एवं फारुक अब्दुल्ला, जो कुछ खेल संगठनों के प्रमुख हैं, की बात छोड़ दी जाए तो यह मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. इन लोगों का खेल संगठनों का प्रमुख बनना कोई अच्छी बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि किसी भी दूसरे देश में किसी केंद्रीय मंत्री को खेल संगठन का प्रमुख बनाए जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं माना जा सकता है.

कांग्रेस ने जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी है, उससे तो ऐसा लगता है कि मुद्दे को पहचानने का उसका सेंस कमजोर हो गया है. देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे बिल पड़े हैं, जिन पर कार्रवाई की सख्त आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती ही नहीं है. यह कांग्रेस के लिए भय पैदा करने वाली बात हो सकती है. कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर अपनी विश्वसनीयता खो दी है. इसके साथ ही 2014 में होने वाले चुनाव में उसकी स्थिति कमज़ोर रह सकती है. युवा वोट अन्ना हजारे के साथ है. हमें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव का इंतज़ार है, जो 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह तय करेगा कि राहुल कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे या नहीं, लेकिन दृश्य तो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है. आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस को परेशानी में डाल रखा है, महाराष्ट्र में यदि एनसीपी ने कोई बवाल खड़ा किया तो वहां भी परेशानी हो सकती है. पश्चिम बंगाल में ममता का बोलबाला है और पिछली कुछ घटनाओं से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को दिक्कत होने वाली है. कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वह दिखाए कि उसने अपनी ग़लती की पहचान कर ली है. साथ ही इस ग़लती की ज़िम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए, नहीं तो मतदाताओं को यह लगेगा कि कांग्रेस ने सुधार नहीं किया है. जैसा देखा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है, जैसी बजट के समय बताई गई थी. मुद्रा स्फीति भी लगातार बढ़ रही है, जबकि हर बार यह वादा किया जाता है कि 6 महीनों में इस पर काबू पा लिया जाएगा. ऐसे वादे पिछले दो वर्षों से हर महीने किए जा रहे हैं.

आज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसकी शुरुआत कब की जाएगी और कौन करेगा. ख़बर है कि सोनिया गांधी वापस आ रही हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता. अगर उन्हें 6 या 12 महीनों तक आराम करना पड़ा और इतने दिनों तक वह राजनीति से दूर रहीं तो कांग्रेस की समस्या बढ़ जाएगी. यदि वह पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और इस महीने के मध्य में अपना काम करना शुरू कर देती हैं तो कांग्रेस और कैबिनेट दोनों को इसका लाभ होगा. राहुल गांधी को वास्तविक राजनीतिक पद ग्रहण करना पड़ेगा. राहुल गांधी को ऐसा करना भी चाहिए, जबकि सोनिया गांधी राजनीतिक मामलों में उनका मार्गदर्शन कर सकती हैं. दु:ख की बात यह है कि कांग्रेस में कोई और नहीं है, जो इस पार्टी को सही ढंग से चला सके. वजह स्पष्ट है कि सारी ताक़त एक ही व्यक्ति के पास है और जब शक्ति का केंद्रीयकरण होता है तो फिर हमेशा उस एक केंद्र की आवश्यकता ही महसूस की जाती है. कांग्रेस और भारत के साथ यही त्रासदी है.

feedback@chauthiduniya.com

मनीष कुमार

कांग्रेस को दोस्ती निभाना नहीं आता

वे सांसद कहां हैं, जो अन्ना हजारे को यह समझा रहे थे कि संसद की एक गरिमा होती है, उसे बाहर से डिक्टेट नहीं किया जा सकता है. वे आज चुप क्यों हैं? संसद की गरिमा बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए. कैश फॉर वोट भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक स्कैम है. देश के सांसद बिकते हैं, ऐसा सोचकर ही घिन होती है. देश के प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं दिया जा सकता है. चाहे वह सरकारी पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर मीडिया. अमर सिंह जेल चले गए, लेकिन इस मामले के जो लाभार्थी हैं, वे बेदाग़ हैं! उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार को फ़ायदा मिलना था. सांसदों की ख़रीद-बिक्री सरकार बचाने के लिए की गई. अमर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों को सरकार के समर्थन में वोट देने के लिए पैसे दिए. सवाल यह उठता है कि अमर सिंह ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया? यह बात भी साफ़ है कि अमर सिंह किसी के कहने पर ही ऐसा काम कर रहे होंगे.

अमर सिंह दु:खी हैं. दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया है. जेल में उनके भाई जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा कर दिया. अमर सिंह ने कहा, मैं यहां शांति से हूं, अपनी ग़लतियों की सज़ा भुगत रहा रहा हूं. इतना तो कहा ही जा सकता है कि अगर अमर सिंह ने अपनी जुबान खोल दी तो देश के कई बड़े नेता अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे. अमर सिंह पिछले आठ सालों से, ख़ासकर 1996 से हिंदुस्तान की राजनीति की कई धुरियों में से एक रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कभी समाजवादियों ने तो कभी वामपंथियों ने और कभी कांग्रेसियों ने किया. भाजपा के अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने भी सहायता ली. इसलिए अगर अमर सिंह बोलेंगे तो यह किसी आरोपी का स्वीकारोक्त बयान नहीं होगा, लेकिन देश की राजनीति की तह में आठ- दस साल रहे व्यक्ति का ख़ुलासा होगा. कैश फॉर वोट मामले में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अमर सिंह को इस्तेमाल किया और काम निकल जाने के बाद उन्हें बेसहारा छोड़ दिया अथवा यूं कहें कि काम निकल जाने के बाद जेल भेज दिया. अमर सिंह जेल में हैं, लेकिन इस मामले की कई गुत्थियां अभी भी उलझी हुई हैं.

कैश फॉर वोट की कहानी में कई मोड़ हैं. किसने किसे, कहां और कैसे धोखा दिया, यह समझना भी बड़ा कठिन है. सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार वोटिंग से पहले बहुमत में नहीं थी. यह सबको पता था कि सरकार गिर सकती है. कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर सरकार बचाना चाहती थी. विकीलीक्स के ख़ुलासे के मुताबिक़ भी यह बात सामने आ चुकी है कि किस तरह कांग्रेस के लोग पैसे लेकर सांसदों को ख़रीदने में जुटे रहे. विकीलीक्स के मुताबिक़, कांग्रेस के एक नेता ने यह समस्या बताई थी कि पैसे लेने के बाद भी सांसद वोट देंगे या नहीं, पता नहीं. अमर सिंह उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे. समाजवादी पार्टी न्यूक्लियर डील के समर्थन में थी. इस दौरान एक और घटना हुई. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान जा रहे थे. जाने से पहले उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार को लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा. अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार इस मामले में अल्पमत में आ गई थी, लोकसभा में संख्या पूरी नहीं हो रही थी तो फिर मनमोहन सिंह ने ऐसा दावा क्यों किया. जिस तरह विकीलीक्स ने ख़ुलासा किया, उससे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वैसे लोगों की तलाश थी, जो उसे इस संकट से बाहर निकाल सकते हों. ऐसे में अमर सिंह की एंट्री होती है. विपक्ष के खेमे में भी हलचल थी. भारतीय जनता पार्टी भी मौक़े का फ़ायदा उठाना चाहती थी. लालकृष्ण आडवाणी के मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा फिर से जाग गई, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई. हुआ यह कि मायावती भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी लेकर दिल्ली आ गईं. उनके घर एक पार्टी भी हुई. छोटे-मोटे दलों के कई नेता वहां पहुंचे तो एक ग़ैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन का माहौल बनने लगा.

इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को पैसे का प्रस्ताव मिलता है. भारतीय जनता पार्टी इस मामले का स्टिंग ऑपरेशन कराने का फ़ैसला करती है. सीएनएन-आईबीएन चैनल के चीफ राजदीप सरदेसाई से संपर्क साधा जाता है. भारतीय जनता पार्टी और सीएनएन के बीच क्या डील हुई, इसका तो पता नहीं, लेकिन यह समझा जा सकता है कि दोनों के बीच ज़रूर कोई क़रार हुआ होगा. राजदीप सरदेसाई स्टिंग ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं. इस स्टिंग ऑपरेशन की कमान यहां से सुधींद्र कुलकर्णी के पास आ जाती है. फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है. स्टिंग ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है. इस ऑपरेशन के दौरान एक घटना घटी, जिस पर ज़्यादा ज़िक्र नहीं हो रहा है. यह घटना ली मेरेडियन होटल की है. वहां एक कांग्रेसी नेता को पैसे लेकर आना था. कैमरे वगैरह लगा दिए गए थे. यह भी तय हो गया था कि उस कांग्रेसी नेता को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस का वह नेता कभी नहीं आया. सवाल यह है कि कांग्रेस के उस नेता को किसी ने बता दिया कि होटल में ख़तरा है. किसने बताया? यह बात सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे और सीएनएन-आईबीएन की टीम जानती थी. भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को भला क्यों बताएंगे. इसलिए राजदीप सरदेसाई से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि किसने डबल क्रास किया, क्या राजदीप सरदेसाई ने ख़ुद यह काम किया या फिर उनकी टीम के किसी व्यक्ति ने किया? इस सवाल का जवाब सीबीआई के पास होना ज़रूरी है.

इस घटना के बाद भी बातचीत जारी रही. पैसे देने अब अमर सिंह के लोग आएंगे, ऐसा तय हुआ. अब स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भाजपा को पता था, राजदीप सरदेसाई को पता था और कांग्रेस को भी पता चल गया. अमर सिंह कांग्रेस की मदद करना चाह रहे थे. कांग्रेस के नेताओं ने इसी मोड़ पर आकर अमर सिंह के साथ दग़ाबाजी कर दी. कांग्रेस की यह ज़िम्मेदारी थी कि वह अमर सिंह को ख़बरदार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अमर सिंह यहीं फंस गए. इस दौरान एक बात और हुई. भाजपा और राजदीप सरदेसाई के बीच करार हुआ था कि संसद में बहस से पहले स्टिंग ऑपरेशन को सीएनएन-आईबीएन पर दिखाया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि पासा पलट चुका है और कांग्रेस को स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया जा चुका है. जब स्टिंग ऑपरेशन दिखाने से मना कर दिया गया, तब आडवाणी की सहमति से नोटों के बंडलों को लोकसभा में ले जाने का फ़ैसला लिया गया. नोटों को लोकसभा में उछाला गया. भारत के प्रजातंत्र पर काला धब्बा लगा, जांच शुरू हो गई और अमर सिंह जेल चले गए.

अमर सिंह को किसने यह काम सौंपा, जो पैसे दिए गए वे किसके हैं, जब तक असली टेप सामने नहीं आएगा और जब तक स्टिंग ऑपरेशन की सारी जानकारी सामने नहीं आएगी, तब तक इस मामले का सच छिपा रहेगा. कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि उसे न तो दोस्ती निभाना आता है और न दुश्मनी.

अब सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण का फ़ायदा जिन्हें होना था, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? अमर सिंह अपने मन से सरकार बचाने के लिए यह काम नहीं कर सकते, तो उनसे सत्ताधारी पार्टी के किस नेता ने संपर्क किया, वह पैसा कहां से आया और किसका था? अमर सिंह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे तो वह जेल पहुंच गए, लेकिन जिन्होंने अमर सिंह से यह काम कराया, वे क्यों छूट गए? बताया तो यह जाता है कि राजदीप सरदेसाई ने जो टेप जमा किया, वह संपादित है. स्टिंग ऑपरेशन का असली टेप कहां है और राजदीप सरदेसाई ने उसे क्यों नहीं दिखाया? अगर अमर सिंह पर ख़रीदने का आरोप है तो राजदीप पर इसे छुपाने का आरोप क्यों नहीं लगा? इस स्टिंग ऑपरेशन के मास्टर माइंड सुधींद्र कुलकर्णी को क्यों छोड़ दिया गया? अगर वह अमेरिका में हैं तो उनके ख़िलाफ़ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस क्यों नहीं जारी किया? जब तक यह पता नहीं चलेगा कि अमर सिंह को किसने यह काम सौंपा, जो पैसे दिए गए वे किसके हैं, जब तक असली टेप सामने नहीं आएगा और जब तक स्टिंग ऑपरेशन की सारी जानकारी सामने नहीं आएगी, तब तक इस मामले का सच छिपा रहेगा. कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि उसे न तो दोस्ती निभाना आता है और न दुश्मनी. अमर सिंह ने कांग्रेस की सरकार बचाने की कोशिश की तो वह जेल भेज दिए गए और बाकी के किरदार आज़ाद घूम रहे हैं.

प्रजातंत्र पर बदनुमा दाग़ लगाने वाले इस खेल के कई खिलाड़ी हैं. अरुण जेटली, सुधींद्र कुलकर्णी, लालकृष्ण आडवाणी, राजदीप सरदेसाई और कांग्रेस के वे तीन रहस्यमयी नेता, जिन्होंने अमर सिंह को आगे रखकर सांसदों को ख़रीदने का काम किया. इस खेल के दूसरे खिलाड़ी हैं सीबीआई और दिल्ली पुलिस. सांसदों की ख़रीद-बिक्री संसद के बाहर हुई और पैसा लोकसभा में दिखाया गया. इसके लिए नेताओं के साथ-साथ सरकारी संस्थाएं भी ज़िम्मेदार हैं. हर किसी का रोल संदेह के घेरे में है, इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट केस है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के सामने होनी चाहिए. इन सभी किरदारों को उसमें पेश किया जाना चाहिए, ताकि सच सामने आ सके और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके.

manish@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

रियलिटी शो और सेंसरशिप

छोटे पर्दे पर रियलिटी शो के ज़रिए अश्लीलता फैल रही है. रियलिटी शो पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि टीआरपी व्यवसाय की शक्ल अख्तियार करती जा रही है. इसके चलते अश्लीलता और फूहड़ता सभ्य समाज के भावनात्मक पारिवारिक रिश्तों में ज़हर घोल रही है. मनोरंजन के भी कुछ दायरे होते हैं. सेंसर बोर्ड के बावजूद फिल्मों में अश्लील और फूहड़ दृश्य दिख जाते हैं. सेंसर बोर्ड को गंभीरता बरतनी चाहिए, ताकि फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर अंकुश लग सके.

–संजय वर्मा, मनावर, धार, मध्य प्रदेश.

पेंशन में बढ़ोत्तरी हो

मध्य प्रदेश में बीते 15 सालों में मंत्रियों एवं विधायकों के वेतन में 900 प्रतिशत और विधायक निधि में 300 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि 14 लाख वृद्धों की पेंशन में कोई इज़ाफ़ा नहीं किया गया. उन्हें आज भी वृद्धावस्था पेंशन के रूप में महज़ 275 रुपये मिलते हैं. इसमें भी पिछले 15 सालों से राज्य शासन का हिस्सा केवल 75 रुपये है, जबकि केंद्र ने इस बीच अपना हिस्सा 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया यानी 166 प्रतिशत की वृद्धि. इन डेढ़ दशकों में मंत्रियों एवं विधायकों का वेतन 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह हो गया है. भत्ते मिला लें तो मंत्रियों को हर महीने 65 हज़ार और विधायकों को 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं. इस दौरान विधायक निधि भी 20 लाख से बढ़कर 80 लाख रुपये हो चुकी है. महंगाई की दुहाई देकर अपना वेतन और भत्ते बढ़ाने की मांग करने वाले इन जनप्रतिनिधियों को जनता का ख्याल क्यों नहीं आता? इतनी महंगाई में इतनी कम पेंशन में एक व्यक्ति का ख़र्च कैसे चल सकता है?

–अनवर, *इंदौर, मध्य प्रदेश.*

अख़बार अच्छा लगा

हांसी बस स्टैंड स्थित बुक स्टॉल से चौथी दुनिया ख़रीद कर पढ़ता हूं. आलेख–लोकपाल बिल, यह जनता के साथ धोखा है, प्रशंसनीय है. इसके अलावा हिमालय को बचाने की अंतरराष्ट्रीय पहल, समाज का अभिशाप–अमीरों का शौक़ आदि आलेख भी विचारणीय हैं. लेखकों ने ज़मीनी हक़ीक़त को बखूबी व्यक्त किया है. सूचना अधिकार संबंधी स्तंभ से उपयोगी जानकारी मिलती है.

–ईश्वर चंद्र आत्रेय, *हांसी, हिसार, हरियाणा.*

मैं हूं पुलिस, मुझे पहचानो

मैं हूं पुलिस मुझे पहचानो, मेरी सभी हरकतें जानो
छोड़ो गीता और कुरान, पढ़ो हमारा पुलिस पुराण
अगर काम करें हम अच्छे, कैसे पलेंगे बीवी–बच्चे
यह मेरा मनमानापन है, जनता से बेगानापन है
सरकारी दबंग कहलाऊं, हर चौराहे पर नोट कमाऊं
क़सम खा ली न सुधरेंगे, मनमानी क़ायम रखेंगे
भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए
कर लो चाहे जितना थू–थू, मेरी समझ न आए

–आनंद फ़ैज़ाबादी, *ईमेल से.*

भ्रष्टाचार का ख़ात्मा हो

दुनिया में भारत 178 भ्रष्टम देशों की सूची में 87वें स्थान पर है. एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनता को 11 चुनिंदा सेवाएं हासिल करने के लिए एक वर्ष में 900 करोड़ रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है. सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की इस स्थिति से जनता को यह संदेश मिल चुका है कि विधायिका और कार्यपालिका से कोई अपेक्षा करने के बजाय उसे इसके लिए खुद एकजुट होना चाहिए.

–नवीन कुमार, *चिरईगांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश.*

■ लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता दिखाई और अन्ना का साथ दिया. दरअसल भ्रष्टाचार रोकने में विभागीय पदाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है. जब तक अधिकारी और कर्मचारी ईमानदार नहीं होंगे, तब तक इस पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं है. हालत यह है कि न्यायपालिका पर भी उंगलियां उठने लगी हैं. देश में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है.

–प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

क्या यह ईश्वर की मर्ज़ी है?

ईश्वर जब सर्वशक्तिमान है और उसकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी मर्ज़ी के बिना एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकता, तो फिर इतने अपराध क्यों होते हैं? क्या लोग ईश्वर की मर्ज़ी से ही अपकर्म करते हैं? अगर हां तो फिर ईश्वर मनुष्य को दुष्कृत्य न करने की प्रेरणा क्यों नहीं देता?

–देशबंधु आर्य, *मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

यूनीसेफ ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर जारी अपने संदेश में कहा, भारत में डायरिया बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 19 सितंबर–25 सितंबर 2011

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

बच्चों ने किया कमाल

दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला टेढ़ी खीर है, लेकिन सरकारी स्कूल भी इस मामले में कम नहीं हैं. दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्तियां भी कई बार जरूरतमंद छात्र–छात्राओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन इन्हीं सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने सूचना कानून का इस्तेमाल करके भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था की कुंभकर्णी नींद तोड़ने का काम किया है. इस अंक में हम कुछ ऐसे ही बच्चों की कहानी बता रहे हैं. दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय का प्रशासन छात्राओं की छात्रवृत्तियां हड़पने की फिराक में था, लेकिन छात्रा सुनीता ने सूचना अधिकार कानून का सहारा लेकर स्कूल प्रशासन के इरादों पर पानी फेर दिया. सुनीता ने न केवल अपनी छात्रवृत्ति हासिल की, बल्कि स्कूल की सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाकर ही चैन की सांस ली. मामला यह था कि स्कूल की छात्राओं के अभिभावकों से हस्ताक्षर करा लेने के चार महीने बाद भी छात्रवृत्तियां वितरित नहीं की गईं. सुनीता ने सूचना अधिकार कानून के जरिए अधिकारियों से जवाब–तलब किया. आवेदन ने असर दिखाया और दो दिनों बाद ही अधिकारी इस संबंध में जांच करने स्कूल आए. इस बीच प्रिंसिपल ने छात्राओं को नाम काटने की धमकी देते हुए कहा कि वे अधिकारियों के सामने छात्रवृत्ति मिलने की बात कहें. अधिकारियों ने जब छात्राओं से इस बारे में पूछा तो उन्होंने प्रिंसिपल के कहे अनुसार जवाब दिए, लेकिन सुनीता ने ऐसा नहीं किया. उसने बेबाकी से प्रिंसिपल की शिकायत की और उनका काला चिट्ठा सामने रख दिया. सुनीता को इस तरह बोलते देखकर बाकी छात्राओं में भी उत्साह जागा और उन्होंने भी सब कुछ साफ–साफ बता दिया. इसके कुछ दिनों बाद स्कूल की सभी छात्राओं को छात्रवृत्तियां वितरित कर दी गईं. पढ़ाई के सपने संजोकर आजमगढ़ से दिल्ली आई अफरीदा बानो के सपने उस वक्त बिखरने लगे, जब कोंडली और दल्लूपुरा स्थित तीन स्कूलों ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया. कक्षा नौ में दाखिले के लिए उसने अपने पिता सनीफ अहमद के साथ कई चक्कर काटे, लेकिन स्कूलों ने तो जैसे दाखिला न करने की कसम खा ली थी. उप शिक्षा अधिकारी को दाखिले के लिए प्रार्थनापत्र भेजा गया, वहां से दाखिला करने के निर्देश मिले, लेकिन इस बार यह कहकर दाखिला देने से मना कर दिया गया कि कोई सीट खाली नहीं है. तब जाकर अफरीदा ने सूचना के अधिकार का सहारा लिया. उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में आवेदन दाखिल कर उसने कुछ सवाल पूछे. मसलन, मेरी शिकायत की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं और यह किस अधिकारी के पास है, उसका नाम पद और फोन नंबर बताएं, मेरा एडमिशन कब तक हो पाएगा तारीख बताएं, शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रधानाचार्य ने प्रवेश देने से इंकार कर दिया, क्या यह शिक्षा अधिकार संबंधी कानून का खुला उल्लंघन नहीं है, कृपया बताएं कि संबंधित तीनों सरकारी विद्यालयों में कक्षा नौ के लिए कितने सेक्शन हैं और प्रति सेक्शन कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया, कृपया प्रवेश रजिस्टर की कॉपी दें. आवेदन में पूछे गए सवालों का असर यह हुआ कि उप शिक्षा निदेशक कार्यालय हरकत में आया और अफरीदा बानो को स्कूल में दाखिला मिल गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की स्थिति)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक.....से.....के बीच प्राप्त की गई शिकायतों का संक्षिप्त विवरण, क्या शिकायत गुमनाम थी, शिकायत की तिथि, उन अधिकारियों या प्राधिकरणों का पूरा विवरण (नाम, पद एवं संपर्क का पता आदि), जिनकेखिलाफ शिकायत की गई है.
2. उपर्युक्त में से कौन सी शिकायतें तुरंत ख़ारिज़ कर दी गईं और कौन सी आगे की जांच के लिए स्वीकार की गईं. मामले के अनुसार शुरुआती जांच की तिथि या ख़ारिज करने की वजह का संक्षिप्त विवरण भी दें.
3. आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई शिकायतों में से कितने मामलों में जांच बंद हो चुकी है? प्रत्येक के बंद होने का संक्षिप्त विवरण दें.
4. विभिन्न कानून, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, मैन्युअल आदि के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराने के कितने समय बाद जांच पूरी हो जाती है. कृपया ऐसे दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं, जिसमें शिकायत प्राप्ति से लेकर उस पर कार्रवाई और दंडारोपण तक के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का वर्णन हो.
5. दिनांक.....से अब तक आयोग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उनमें से कितनी तत्काल ख़ारिज कर दी गईं और कौन सी आगे की जांच के लिए रखी गईं? उनमें से कितनी शिकायतों की छानबीन में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/ रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.....है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम.....
पता.....
फोन नं.....

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

ज़रा हट के

डायरिया से कैसे बचें

भारत में शिशु मृत्यु दर के ज़्यादा होने के कई कारण हैं. डायरिया भी एक बड़ा कारण है. बच्चों के विकास और उनके कल्याण के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनीसेफ ने कहा है कि भारत में डायरिया से प्रतिदिन 1000 बच्चों की मौत हो जाती है. बच्चों में अगर प्रतिदिन साबुन से हाथ धोने की आदत विकसित की जाए तो हर दिन 400 बच्चों की जान बचाई जा सकती है. यूनीसेफ ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर जारी अपने संदेश में कहा, भारत में डायरिया बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है. इसके कारण प्रतिदिन पांच साल से कम उम्र के 1000 बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं. हाथ धोने की आदत विकसित होने से 40 प्रतिशत बच्चों की जान बचाई जा सकती है. यूनीसेफ के मुताबिक, पानी के बेहतर रखरखाव से डायरिया फैलने की आशंका काफी कम हो जाती है. गरीबी और अज्ञानता के कारण भारत में हाथ धोने की आदत विकसित नहीं हो सकी है, जबकि इसे आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि डायरिया रोकने का यह सबसे सस्ता और आसान उपाय है.

बेहतर नुस्ख़ा

देश में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए नींबू घास की नई प्रजाति सुवर्णा अब एक वरदान साबित होगी. केंद्रीय औषधि सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) ने खास तौर पर सूखा और अकालग्रस्त इलाकों के लिए यह नई प्रजाति तैयार की है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी. सीमैप के प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय विकास विभाग के प्रमुख डॉ. ए.के. सिंह ने बताया कि नींबू घास की नई प्रजाति सुवर्णा बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों के लिए वरदान साबित होगी.

आम तौर पर नींबू घास की प्रजातियां सिंचित क्षेत्रों में होती हैं, लेकिन यह नई प्रजाति सूखाग्रस्त इलाकों के लिए विकसित की गई है, जो किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन में खुशहाली लाएगी. उल्लेखनीय है कि नींबू जैसी खुशबू आने के कारण लेमन घास को बोलचाल की भाषा में नींबू घास कहा जाता है. इसी सुगंध के कारण इससे निकलने वाले तरल पदार्थ (तेल) का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और पेय पदार्थों में भी किया जाता है. डॉ. सिंह ने बताया कि नींबू घास की नई उन्नत प्रजाति को एक हेक्टेयर में लगाने से साल में लगभग 200 किलोग्राम तेल निकलेगा, जिसका मूल्य बाजार में करीब 400 रुपये प्रति किलोग्राम है. यानी एक हेक्टेयर जमीन से अब किसानों को हर साल करीब 50–60,000 रुपये की कमाई होगी. अभी तक इस प्रजाति से एक हेक्टेयर में सौ–सवा सौ किलोग्राम तेल निकलता था, लेकिन उन्नत प्रजाति में उत्पादन की मात्रा बढ़कर 200 किलोग्राम हो गई है. पांच साल की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने इस उन्नत प्रजाति को विकसित किया है. अभी इस प्रजाति की रोपण सामग्री झांसी और बाराबंकी जिले के किसानों को सीमित मात्रा में दी गई है. किसानों से प्रतिक्रिया के आधार पर इस नई प्रजाति में सुधार किया जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
मित्रों से मिलाप हेतु यात्रा के प्रसंग प्रबल होंगे. अगर आप थोड़ा–बहुत भी हाथ–पांव मारेंगे या परिश्रम करेंगे तो तत्काल फ़ायदा हो सकता है. राजकीय पक्ष से कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है. यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हों तो उसकी सफलता आपके लिए ख़ुशी का कारण बन सकती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह अटकलों की वजह से कुछ योजनाएं टल सकती हैं. काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद कुछ अच्छे परिणाम मिलने की आशा रहेगी. मनोवांछित धन लाभ हो सकता है. परिवारीजन–मित्रगण आपसे प्रभावित होकर दावत या डिनर का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह गोचर शारीरिक और मानसिक सुख प्रदान करने में समर्थ रहेगा. काफी समय से अटका हुआ कोई काम आपके लिए अच्छा संदेश ला सकता है. दूर देश में रहने वाला मित्र सहयोगी बनकर सामने आएगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
कोई बौद्धिक और धार्मिक कार्य सफल होगा. काफी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद फ़ायदे कम और नुक़सान अधिक रहेंगे. जिस वांछित धन की आप आशा लगाकर बैठे हैं, वह अभी आपके हाथ में आने से रह जाएगा. एकाएक पैदा होने वाली ऐसी अड़चन से आपके अंदर खिन्नता बढ़ सकती है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आपके छोटे–मोटे प्रयास से ही अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं. जिस काम को आप काफी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही अचानक बनता हुआ नज़र आएगा. आपके अंदर जो क्षमता और हिम्मत है, वही आपको सफलता के द्वार पर लाती जा रही है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग कुछ इस प्रकार मिलेगा कि सभी रुके हुए काम अचानक पूरे हो जाएंगे. कारोबार या काम–धंधे में आपकी पहुंच गहरी होगी. रुका हुआ धन भी आपके हाथ लग सकता है. जहां तक हो सके, अपने अच्छे समय का सदुपयोग करें और प्रयास जारी रखें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
शारीरिक और मानसिक विकार तनाव पैदा कर रहे हैं. चंद्रमा के अशुभ गोचर के कारण आपको अपना रुका हुआ काम पूरा करने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा. विरोधियों और आलोचकों का भी सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह परिस्थितियां एकाएक जटिल हो सकती हैं. आपको अपने अटके हुए काम पूरे करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी. यदि कोई कोर्ट–कचहरी का मामला है तो उसकी तैयारी के लिए आपको समय निकालना होगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
सप्ताह के पहले दो दिन आपको अपने जनसंपर्क और शुभचिंतकों का लाभ मिलेगा. यदि आप घर से किसी काम को निकल रहे हैं तो अच्छी तरह तैयार होकर जाएं. हो सकता है, रास्ते में आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए, जो तत्काल मददगार साबित हो जाए.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
निकट–दूर की यात्राओं का मार्ग प्रशस्त होगा. आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करने में मदद मिलेगी. अतिरिक्त काम का बोझ, जो पिछले काफी समय से आपके लिए सिरदर्द बना हुआ था, कम हो जाएगा. जहां तक हो सके, पथ्य परहेज से रहें और समय पर दवा का उपयोग करते रहें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
सुनी–सुनाई बातों पर यक़ीन करने से कलह को जन्म मिलेगा. यदि आप युवा या विद्यार्थी हैं तो सप्ताह के पहले दो–तीन दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. पूर्व नियोजित कार्य पूरे करने में मदद मिलेगी. किसी नए कार्यक्षेत्र में जाने के लिए रास्ता साफ होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
उत्तम रहन–सहन का वातावरण तैयार होगा. कोई सामान गुम हो जाने का अंदेशा बना रहेगा. कारोबार या नौकरी में जोख़िम और वाद–विवाद की आशंका है. गंभीरता और धैर्य के बल पर आप अपने को काबू में रख पाएंगे. किसी को धन उधार देना ठीक नहीं है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

पुलिस का अनुमान है कि यह रकम नशीली दवाओं के व्यापार से कमाई गई थी. इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मैक्सिको में नशीली दवाओं का कारोबार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है.

ड्रग वॉर की चपेट में आम आदमी

राजीव कुमार

मैक्सिको की औद्योगिक राजधानी कहलाने वाला मोंटेरे शहर मस्ती में डूबा हुआ था. शहर में पैसे वालों की कमी नहीं है. लोग जुआघर में जुआ खेलने में मस्त थे. अचानक कुछ बंदूकधारी वहां घुस आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे. जुआघर में अफरातफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे. चारों ओर चीख-पुकार मच गई. बंदूकधारियों ने जुआघर को आग के हवाले कर दिया. अचानक हुए इस हमले में 50 लोगों की मौत हो गई. शहर के मेयर ने मरने वालों की संख्या और अधिक होने की बात की. अचानक हुआ यह हमला सरकार के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं था. न यहां की आर्थिक स्थिति ख़राब है और न यहां मध्य पूर्व के देशों की तरह शासन के ख़िलाफ़ लोगों में कोई आक्रोश है. मैक्सिको की अर्थव्यवस्था अभी भी विश्व की तेरहवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी यह मध्य आय वाले देशों के समूह में शामिल है. दरअसल, यह हमला था ड्रग माफ़ियाओं का. मैक्सिको में पिछले कुछ सालों से ड्रग वॉर चल रहा है.

मैक्सिको की सरकार मादक द्रव्यों की तस्करी और वर्चस्व की लड़ाई में हो रही मौतों से काफ़ी चिंतित है. सरकार इन तस्करों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पा रही है. यहां के लोग भी इस ड्रग वॉर से बहुत घबराए हुए हैं. माफियाओं के बीच चल रही इस जंग का शिकार आम आदमी बन रहा है. गोलीबारी में अक्सर निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस ड्रग वॉर में 2006 से अब तक 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य स्रोत इससे भी बड़े आंकड़े पेश करते हैं. उनके अनुसार, इस ड्रग वॉर में अब तक लगभग 35,000 हज़ार लोगों की जानें जा चुकी हैं. ख़ुफ़िया विभाग के प्रमुख वॉल्डेस का कहना है कि राष्ट्रपति फिलिप कालडेरॉन के पद संभालने के बाद इन गिरोहों के साथ सुरक्षाबलों की 963 मुठभेड़ें हुईं. आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान प्रतिदिन एक मुठभेड़ दर्ज की गई. पुलिस और सेना ने मिलकर 84 हज़ार हथियार, 35 हजार वाहन और 40 करोड़ डॉलर से ज़्यादा धनराशि ज़ब्त की.

पुलिस का अनुमान है कि यह रकम नशीली दवाओं के व्यापार से कमाई गई थी. इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मैक्सिको में नशीली दवाओं का कारोबार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है. कुछ दिनों पूर्व सेना के गश्ती दल को एक ग़ैरक़ानूनी अफीम का खेत मिला. मैक्सिको के उत्तरी राज्य बाजा कैलिफोर्निया में स्थित यह खेत 1.2 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 300 एकड़ में फैला है. अफीम का इतना बड़ा खेत अभी तक इस देश में नहीं मिला था. इस खेत में उगाई जाने वाली अफीम की मार्केट वैल्यू लगभग 10 करोड़ पाउंड है. इस खेत को प्लास्टिक की चादर से ढक दिया गया था, ताकि इसे खोजी कैमरों की नज़र से बचाया जा सके. सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इतना बड़ा खेत तो मिल गया, लेकिन उसके मालिक का कोई अता-पता नहीं है. इसलिए पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई. इससे ड्रग माफ़ियाओं की ताक़त और पहुंच का अनुमान लगाया जा सकता है. इस ड्रग वॉर से मैक्सिको के लोग काफ़ी त्रस्त हैं. सड़क पर चलते हुए उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता है कि कहीं किसी ओर से गोली न चल जाए. जुआघर में गोलीबारी और जेल में हुए संघर्ष से लोग काफ़ी घबरा गए हैं. नशीली दवाओं के तस्करों ने मीडियाकर्मियों को भी नहीं छोड़ा. कई पत्रकारों का अपहरण कर लिया गया. बीते जून माह में पत्रकार मिगुएल लोपेज, उनकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई. इस कारण नशीली दवाओं के तस्करों की रिपोर्टिंग करने से पत्रकार घबराने लगे हैं. यही नहीं, कुछ नेताओं को भी इस ड्रग वॉर का शिकार होना पड़ा. 2010 में 12 मेयरों की हत्या कर दी गई. तामुलिपास राज्य के गवर्नर पद के एक प्रत्याशी को भी मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस का कहना है कि यह हत्या भी नशीली दवाओं के तस्करों ने ही की. इससे सरकार की परेशानी बढ़ गई है. मैक्सिको के राष्ट्रपति फिलिपे काल्डेरान ने तो ड्रग माफियाओं के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला.

आख़िरकार इन तस्करों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, सरकार को ड्रग माफ़ियाओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? इन सवालों पर मैक्सिको के ख़ुफ़िया विभाग के प्रमुख गुइलेरमो वॉल्डेस का कहना है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. सरकार को काला धन सफ़ेद करने की प्रक्रिया रोकने के प्रयास करने होंगे और उन सरकारी संस्थाओं को मज़बूती प्रदान करनी होगी, जो सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के मामले में अभी भी कमज़ोर साबित हो रही हैं. तस्करों के पास हथियारों का ज़खीरा है, जो उन्हें पुलिस से लड़ने में मदद करता है. उनके पास काफ़ी धन है, जो सरकारी तंत्र को भ्रष्ट बना रहा है. सरकार को इन बातों पर ग़ौर करना चाहिए. मादक द्रव्यों की तस्करी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है और इससे निबटने के लिए व्यापक सहयोग की आवश्यकता है. विश्व के कई नेताओं एवं विशेषज्ञों ने एक 19 सदस्यीय आयोग गठित किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, अमेरिका के केंद्रीय बैंक के पूर्व चेयरमैन पॉल वॉकर, कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति सीजर गैविरिया, ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री जार्ज पापेंद्रु, प्रसिद्ध लैतिन अमेरिकी लेखक कार्लोस फ्युएंतेस एवं मारियो लोसा, यूरोपीय संघ में विदेश नीति विभाग के पूर्व प्रमुख जैवियर सोलाना, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ज के अलावा प्रसिद्ध उद्यमी रिचर्ड ब्रैनसन भी शामिल हैं.

इस आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि नशीली दवाओं के ख़िलाफ़ बनाई गई नीति विफल हो गई है, क्योंकि इससे संगठित अपराध को बढ़ावा मिला है, करदाताओं पर लाखों डॉलरों का बोझ पड़ा है और इस वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई. संयुक्त राष्ट्र के आकलन का हवाला देते हुए कहा गया है कि 1998 से 2008 के बीच दुनिया भर में अफीम युक्त मादक द्रव्यों की खपत में 35 फ़ीसदी, कोकीन की खपत में 27 फ़ीसदी और भांग की खपत में 8.5 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दमन की नीतियों के ज़रिए नशीली दवाओं की तस्करी समाप्त नहीं की जा सकती और न नशीली दवाओं के ख़िलाफ़ चल रही जंग जीती जा सकती है. इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाना ज़रूरी है. रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया है कि नशा करने वाले लोगों को, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें अपराधी ठहराने के स्थान पर दूसरे कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे एक तो नशीली दवाओं के कारण हो रहे संगठित अपराधों में कमी आएगी, साथ ही नशीली दवाएं लेने वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकेंगी, लेकिन इस रिपोर्ट को अमेरिका ने ख़ारिज कर दिया. अमेरिका द्वारा ख़ारिज किए जाने का मतलब है कि इस सुझाव को विफल मान लिया जाना, लेकिन अमेरिका ख़ुद भी ऐसी कोई नीति नहीं बना रहा है, जिससे नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाई जा सके.

विश्व के सबसे ताक़तवर देश के पड़ोस में ही मादक द्रव्यों का कारोबार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और वह कुछ नहीं कर रहा, तो अन्य क्षेत्रों में चल रहे इस धंधे के ख़िलाफ़ वह भला क्या कार्रवाई करेगा? हालांकि मैक्सिको के इस नशा व्यापार से अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के मुताबिक़, कोकीन और मेरिजुआना के इस्तेमाल में अमेरिका प्रथम स्थान पर है. 1970 के दशक से ही मैक्सिको के तस्कर अमेरिका में मेरिजुआना भेज रहे हैं. वे सड़क और समुद्र मार्ग, दोनों के माध्यम से मादक द्रव्यों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन अभी तक अमेरिकी सरकार इसे रोकने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठा सकी. अगर अमेरिका इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो मैक्सिको के साथ-साथ उसे भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. मैक्सिको में तेज़ी से बढ़ रहा मादक द्रव्यों का व्यापार और उस पर क़ब्ज़े के लिए हो रहा संघर्ष न केवल इस देश, बल्कि पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि आतंकवादी संगठनों को सबसे अधिक धन इसी व्यापार से मिलता है, जिसका उपयोग वे हथियार ख़रीदने और आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए करते हैं. अत: एक वैश्विक नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे इस संगठित अपराध को रोका जा सके. आतंकवाद आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आतंकवादी संगठनों के आर्थिक आधार को ध्वस्त किया जाए. आतंकवाद के ख़िलाफ़ जिस प्रकार के वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रयास मादक द्रव्यों की तस्करी ख़त्म करने के लिए भी करने होंगे, अन्यथा जो मैक्सिको में हो रहा है, उसे अन्य देशों तक फैलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

साईं अंतर्यामी हैं

एक बार एक भक्त के बुलावे पर साई बाबा उसके घर खाने के लिए गए, लेकिन वह कुत्ते के रूप में निश्चित समय से पूर्व ही उसके पास पहुंच गए. भक्त ने उस कुत्ते पर जलती हुई लकड़ी मारी और उसे भगा दिया. जब बाबा उसके घर खाने के लिए नहीं पहुंचे तो भक्त ने द्वारिका माई मस्जिद आकर उन्हें उलाहना दिया कि बाबा, आप तो आए नहीं. मेरा निमंत्रण स्वीकार करके भी आप क्यों नहीं आए?

भारत में जितने भी योगी, साधु-संन्यासी एवं सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनमें शिरडी के साईं बाबा का नाम सर्वोपरि है. उनके भक्तों एवं अनुयायियों की इतनी बड़ी संख्या का प्रमुख कारण है बाबा के प्रति उनका अटूट विश्वास. आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, धर्म नहीं है, जाति या वर्ग नहीं है, जिसके लोग श्री शिरडी साईं बाबा के दिव्य नाम से परिचित न हों. वह विश्व की महान आध्यात्मिक विभूति थे. संभवत: 1838 में उन्होंने ग्राम पथरी में जन्म लिया था और अस्सी वर्ष की आयु में उन्होंने शिरडी (महाराष्ट्र) में अपना भौतिक शरीर त्यागा था. वह संभवत: किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन में उन्हें एक मुस्लिम फ़क़ीर परिवार ने पाला-पोसा. इसके बाद वह ग्राम शेलू के एक ब्राह्मण संत गुरु वेंकुशा के आश्रम में 1842 से 1854 तक अर्थात 12 वर्ष रहे थे. 1854 में अपने गुरु के आदेश से वह शिरडी पहुंचे थे, जहां लगभग दो माह तक एक नवयुवक संत के रूप में रहने के बाद वह अचानक वहां से चले गए और पुन: तीन वर्ष बाद 1858 में चांद भाई पाटिल (धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार) के भतीजे की बारात के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी आए और फिर वहीं बस गए. वहां उन्होंने एक पुरानी त्यागी हुई वीरान मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया और उसे द्वारिका माई का नाम दिया.

1858 से 1918 तक अर्थात 60 वर्षों तक वह शिरडी में उसी मस्जिद में रहे. उन्होंने किसी को अपने परिवार, जाति एवं धर्म के बारे में नहीं बताया. यद्यपि कुछ प्रमाणों के अनुसार, वह ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे. वह शिरडी में मुस्लिम फ़क़ीर जैसा सीधा-सादा जीवन जीते थे. वह हमेशा अल्लाह मालिक है, कहते रहते थे. वह संस्कृत, उर्दू, अरबी, मराठी, हिंदी और तमिल आदि भाषाओं की अच्छी जानकारी रखते थे. वह शिरडी के केवल पांच विशेष परिवारों से ही रोज़ दिन में दो बार भिक्षा मांग लाते थे. टीन के बर्तन (मग) में तरल पदार्थ और कंधे पर डाले गए कपड़े की झोली बनाकर उसमें रोटी और ठोस पदार्थ, जो भी भिक्षा में मिल जाता था, द्वारिका माई में लाते थे. फिर सभी को मिट्टी के बड़े बर्तन (परात) में मिला देते थे और एक-दो घंटे तक खुला रख देते थे. कुत्ते, बिल्लियां एवं अन्य पशु-पक्षी आकर उसका एक अंश खा लेते थे, शेष को वह बाक़ी भक्तों के साथ मिल-बांटकर खा लेते थे. उन्होंने 1858 में द्वारिका माई में जो धूनी स्थापित की थी, वह आज भी लगातार प्रज्ज्वलित हो रही है. वह उसकी भस्म (जिसे वह ऊदी कहते थे) भक्तों एवं आगंतुकों को अपने आशीर्वाद के साथ दिया करते थे, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक कष्ट दूर हो जाते थे.

बाबा त्रिकालदर्शी थे. वह लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते थे, पशु-पक्षियों एवं अन्य प्राणियों के पूर्व जन्मों के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी थी. उन्होंने जिसे जो भी आशीर्वाद दे दिया, वह अवश्य फलीभूत होता था. उन्होंने दिखाने के लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से करुणावश कई अत्यंत रोमांचकारी चमत्कार किए. उनके चमत्कारों एवं भक्तों पर अनुग्रह की ख्याति धीरे-धीरे सारे महाराष्ट्र, दक्षिण भारतीय प्रांतों, बाद में संपूर्ण भारत और अंतत: विश्व भर में फैल गई. उन्हें विश्वगुरु स्वीकार किया गया. उनके शिरडी वास के दौरान हज़ारों भक्त दु:खी और याचक उनकी कृपा दृष्टि पाने आए और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुईं. महाराष्ट्र के एक महान भक्त दामोलकर हेमाड पंत ने उनसे प्रार्थना की थी कि वह अपने दिव्य जीवन, चमत्कारों और उपदेशों पर एक ग्रंथ लिखने की अनुमति दे दें. उन्होंने अपनी अनुमति और आशीर्वाद देते हुए यह कहा था, मेरा सद्चरित्र (श्री साई सद्चरित्र) लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है. जो प्रेमपूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी. जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा. जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें कथाएं श्रवण कर स्वाभाविकत: प्रसन्नता होगी. विश्वास रखो, जो मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिरसंतोष की उपलब्धि हो जाएगी. जो भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, स्मरण और ध्यान करता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं.

जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं एवं लीलाओं का प्रेमपूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं? मैं उन्हें मृत्यु से बचा लेता हूं. मेरी कथाएं सुनने से मुक्ति हो जाएगी. अत: मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो. सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है. केवल साई-साई के उच्चारण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे. श्री साई बाबा शिरडी संस्थान द्वारा प्रकाशित हेमाड पंत की अमर रचना श्री साई सद्चरित्र लाखों-करोड़ों भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान, मार्गदर्शन और अनुपम आत्मिक शांति दशकों से प्रदान करती आ रही है. संसार में सैकड़ों आध्यात्मिक संत, गुरु, अवतार, औलिया एवं चमत्कारी व्यक्तित्व हुए हैं और आज भी कई जीवित हैं. सभी ने यह उपदेश दिया कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक जैसी है. आत्मा परमात्मा की चिंगारी है, जो परमात्मा से ही निकली है और पुन: उन्हीं में लौटकर विलीन हो जाती है, लेकिन साई बाबा ही ऐसे एकमात्र अवतार पुरुष हुए, जिन्होंने यह प्रयोग कई बार करके दिखाया था कि कैसे प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक सी है. साई सद्चरित्र और बाबा पर लिखी गई अन्य पुस्तकों में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है. एक बार एक भक्त के बुलावे पर साई बाबा उसके घर खाने के लिए गए, लेकिन वह कुत्ते के रूप में निश्चित समय से पूर्व ही उसके पास पहुंच गए. भक्त ने उस कुत्ते पर जलती हुई लकड़ी मारी और उसे भगा दिया. जब बाबा उसके घर खाने के लिए नहीं पहुंचे तो भक्त ने द्वारिका माई मस्जिद आकर उन्हें उलाहना दिया कि बाबा, आप तो आए नहीं. मेरा निमंत्रण स्वीकार करके भी आप क्यों नहीं आए? अब आप मेरे साथ चलिए. बाबा ने उत्तर दिया, मैं तो कुत्ते के रूप में तुम्हारे घर भोजन करने गया था, परंतु तुमने तो जलती हुई लकड़ी मारकर मुझे भगा दिया. यह सुनकर भक्त सन्न रह गया. अचानक उसे बाबा की बात याद आ गई कि वह तो हर प्राणी में विद्यमान हैं और किसी भी रूप में किसी के सामने उपस्थित हो सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार-बार नमस्कार.

ज्ञानोदय

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए

- स्व. मालती कपूर

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है.

- प्रेमचंद

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.

- स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा

1976 में प्रदर्शित फिल्म कभी-कभी यश चोपड़ा की शहद से मीठी फिल्म है. कहा गया कि इसके नायक के व्यक्तित्व का आधार साहिर लुधियानवी थे.

अनंत विजय

लोक से दूर लेखक

बचपन से सुनता था कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहा करते थे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है. एक और बात सुनता था कि साहित्य राजनीति के पीछे नहीं, बल्कि समाज के आगे चलने वाली मशाल हैं. मैं इसे सुनकर यह सोचता था कि अगर साहित्य मशाल है तो साहित्यकार उस मशाल की लौ को लगातार जलाए रखने का काम करते हैं. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना हजारे का दिल्ली में ऐतिहासिक अनशन ख़त्म हो गया है. अब तमाम तरीक़े से लोग उस जन उभार और आंदोलन को मिले व्यापक जन समर्थन का आकलन कर रहे हैं. यह वह वक़्त था, जब साहित्य और साहित्यकारों के सामने यह चुनौती थी कि वे साबित करें कि वे राजनीति के पीछे चलने वाली मशाल नहीं हैं, लेकिन अन्ना के आंदोलन के दौरान कमोबेश साहित्यकारों का जो ठंडा या विरोध का रुख़ रहा, उससे घनघोर निराशा हुई. हंस के संपादक और दलित विमर्श के पुरोधा राजेंद्र यादव को अन्ना के आंदोलन में आ रहे लोग, भीड़ और उनका समर्थन एक उन्माद नज़र आता है. उस भीड़ और उन्माद को दिखाने-छापने के लिए वह मीडिया को कोसते नज़र आते हैं. उनका मानना है कि अन्ना के आंदोलन के पीछे व्यवस्था परिवर्तन का विचार कम और एक समानांतर सत्ता क़ायम करने की आकांक्षा ज़्यादा है. पता नहीं, राजेंद्र यादव को इसमें समानांतर सत्ता कायम करने के संकेत कहां से मिल रहे हैं, जबकि अन्ना हजारे और उनके लोग मंच से कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं.

अन्ना हजारे ने तो कई बार अपने साक्षात्कार में इस बात को दोहराया है कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत ज़ब्त हो जाएगी. टीम अन्ना भी हर बार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है. दरअसल यह जो सोच है, उसका आशय यह है कि वे अपने दायरे से बाहर न निकलने की जिद पाले बैठे है. राजेंद्र यादव को दूसरी शिकायत है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन है, वह लक्ष्यविहीन है और जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात की जा रही है, वह एक अमूर्त मुद्दा है. उनका मानना है कि जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में हम अंग्रेजों की सत्ता के ख़िलाफ़ लड़े थे या फिर जय प्रकाश आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन के ख़िलाफ़ पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, वैसा कोई साफ लक्ष्य अन्ना के सामने नहीं है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वह अदृश्य है. भ्रष्टाचार व्यापक रूप से समाज और नौकरशाही की रग-रग में व्याप्त है, उसे ख़त्म करना आसान नहीं है.

एक तरफ़ तो राजेंद्र यादव कहते हैं कि यह समानांतर सत्ता क़ायम करने की आकांक्षा है तो दूसरी तरफ़ उन्हें कोई मूर्त लक्ष्य दिखाई नहीं देता है. राजेंद्र यादव को अन्ना का आंदोलन बड़ा तो लगता है, लेकिन इसके अलावा उन्हें सबसे आधारभूत आंदोलन नक्सलवाद का लगता है. उनका मानना है कि नक्सलवादी आंदोलन सारे सरकारी दमन के बावजूद व्यवस्था परिवर्तन के लिए सैकड़ों लोगों को बलिदान के लिए प्रेरित कर रहा है. यादव जी को नक्सलवादी आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लगता है, जबकि अन्ना का आंदोलन समानांतर सत्ता क़ायम करने की आकांक्षा. क्या यादव जी यह भूल गए कि भारतीय सत्ता को सशस्त्र विद्रोह से उखाड़ फेंकने के सिद्धांत पर ही नक्सलवाद का जन्म हुआ. लगभग पांच दशकों बाद भी नक्सलवादी उसी सशस्त्र विद्रोह के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका अंतिम लक्ष्य दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ होना है. जबकि अन्ना का आंदोलन न तो कभी सत्ता परिवर्तन की बात करता है और न हिंसा की.

दरअसल राजेंद्र यादव भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा माओवादियों की समर्थक लेखिका अरुंधति राय बोल रही हैं. अरुंधति को भी जन लोकपाल बिल में समानांतर शासन व्यवस्था की उपस्थिति दिखाई देती है. अन्ना के आंदोलन में पहले भारत माता की तस्वीर लगाने और उसके बाद गांधी की तस्वीर लगाने और वंदे मातरम गाने पर भी ऐतराज है. ऐतराज तो अन्ना के मंच पर तमाम मनुवादी शक्तियों के इकट्ठा होने पर भी है, लेकिन अन्ना के साथ काम कर रहे स्वामी अग्निवेश और प्रशांत भूषण तो अरुंधति के भी सहयोगी हैं. अरुंधति को इस बात पर आपत्ति थी कि अनशन के बाद अन्ना एक निजी अस्पताल में क्यों गए. इन सब चीजों को अरुंधति एक प्रतीक के तौर पर देखती हैं और उन्हें ये सब चीजें एक ख़तरनाक कॉकटेल की तरह नज़र आती हैं.

पता नहीं, हमारे समाज के बुद्धिजीवी किस दुनिया में जी रहे हैं. अन्ना के समर्थन में उमड़े जनसैलाब में लोग दलितों, अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों को ढूंढने में लगे हैं. बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे अन्ना हज़ारे के आंदोलन में जिस तरह स्वत: स्फूर्त तरीक़े से लोग शामिल हुए, वह आंखें खोल देने वाला है. घरों में संस्कार और आस्था जैसे धार्मिक चैनलों की जगह न्यूज़ चैनल देखे गए, जिन घरों से सुबह-सुबह भक्ति संगीत की आवाज़ आया करती थी, वहां से न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टरों की आवाज़ या अन्ना की गर्जना सुनाई देती थी. अन्ना के समर्थन में सड़कों पर निकले लोगों के लिए ट्रैफिक ख़ुद-बख़ुद रुक जाता था और आंदोलनकारियों को रास्ता देता था. ये सब एक ऐसे बदलाव के संकेत थे, जिन्हें पकड़ पाने में राजेंद्र यादव और अरुंधति जैसे लोग नाकाम रहे. अन्ना हजारे के आंदोलन से तत्काल कोई नतीजा नहीं निकला तो क्या हुआ, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसे समझने में राजेंद्र-अरुंधति जैसे महान लेखक चूक गए. लेखकों के अलावा हिंदी में काम कर रहे लेखक संगठनों की भी कोई बड़ी भूमिका अन्ना के आंदोलन के दौरान देखने को नहीं मिली. अगर किसी लेखक संगठन ने चुपके से कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी हो तो वह ज्ञात नहीं है. यह एक ऐतिहासिक मौक़ा था, जिसमें शामिल होकर हिंदी के मृतप्राय: लेखक संगठन अपने अंदर नई जान फूंक सकते थे, लेकिन विचारधारा के बाड़े से बाहर न निकल पाने की जिद या मूर्खता उन्हें ऐसा करने से रोक रही है. समय को न पहचान पाने वाले इन लेखक संगठनों की निष्क्रियता पर अफसोस होता है. प्रगतिशील लेखक संघ अपने शुरुआती सदस्य प्रेमचंद की बात को भी भुला चुका है. साहित्य समाज का दर्पण तो है, पर आज के साहित्यकार उस दर्पण से मुंह चुराते नज़र आ रहे हैं. जब लेखकों के सामने यह साबित करने की चुनौती थी कि साहित्य राजनीति का पिछलग्गू नहीं है तो वे ख़ामोश रहकर इस चुनौती से मुंह चुरा रहे थे. इस ख़ामोशी से लेखकों और लेखक संगठनों ने एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया.

ऐसा नहीं है कि हिंदी के सारे साहित्यकार अन्ना के आंदोलन के विरोध में हैं. कई युवा और उत्साही लेखकों के अलावा नामवर सिंह और असगर वजाहत जैसे वरिष्ठ लेखकों को अन्ना का आंदोलन अहम लगता है. नामवर सिंह कहते हैं कि अन्ना का आंदोलन समाज को एक नई दिशा दे सकता है, यह सदिच्छा से किया गया आंदोलन है और इसका अच्छा परिणाम होगा. असगर वजाहत को भी लगता है कि अन्ना का आंदोलन एक नया रास्ता खोल रहा है. नामवर और असगर जैसे और कुछ लेखक हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन बड़ी संख्या में जन और लोक की बात करने वाले लेखक जन और लोक की आकांक्षाओं को पकड़ने में नाकाम रहे.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

रेशमी ख्वाबों का ख़ूबसूरत सफ़रनामा

सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा

समीक्ष्य कृति: रेशमी ख्वाबों की धूप-छांव
लेखक: प्रहलाद अग्रवाल
प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य: 300 रुपये

हिंदी फिल्में हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं. ये मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम होने के साथ-साथ विभिन्न दौर के सामाजिक परिवेश को भी बख़ूबी प्रस्तुत करती हैं. हाल में प्रकाशित प्रहलाद अग्रवाल की किताब रेशमी ख्वाबों की धूप-छांव में फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों के विभिन्न पहलुओं को इतने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक ख़ुद को इन फिल्मों के किरदारों के बेहद क़रीब पाता है. इसमें यश चोपड़ा की 1959 में आई फिल्म धूल का फूल से लेकर 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा तक के बारे में दिलचस्प जानकारी दी गई है. यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा में निर्देशकों की तीन पीढ़ियों के साथ सफ़र किया है. जब उनकी पहली फिल्म धूल का फूल प्रदर्शित हुई, तब महमूद, बिमल राय, राजकपूर, गुरुदत्त, विजय आनंद आदि का दौर था. 1973 में जब उन्होंने दाग़ के साथ यशराज फिल्म्स की शुरुआत की, तब व्यापारिक परिदृश्य में मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, श्याम बेनेगल, गुलज़ार, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, गोविंद निहलानी एवं सई परांजपे आदि फिल्मकारों की बहुआयामी पीढ़ी थी, जो हिंदी सिनेमा को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रही थी.

अब वह सूरज बड़जात्या, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, राम गोपाल वर्मा एवं आशुतोष गोवारिकर की पीढ़ी के साथ सृजनरत हैं. वह दर्शकों को रेशमी ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं. उनके प्रेम संबंध तर्क की सीमाओं से बाहर खड़े हैं. उनका कौशल यह है कि वह इस अतार्किकता को ग्राह्य बना देते हैं. वह समाज में हाशिए पर पड़े रिश्तों को गहन मानवीय संवेदना और जिजीविषा की अप्रतिम ऊर्जा से संचारित कर देते हैं. वह अपनी पहली फिल्म धूल का फूल से लेकर वीर ज़ारा तक अनाम रिश्तों की मादकता से अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं.

1976 में प्रदर्शित फिल्म कभी-कभी यश चोपड़ा की शहद से मीठी फिल्म है. कहा गया कि इसके नायक के व्यक्तित्व का आधार साहिर लुधियानवी थे. यही बात गुरुदत्त की कालजयी कृति प्यासा के लिए भी कही गई थी, पर इन दोनों ही संदर्भों में सच्चाई यह है कि दोनों फिल्मों के नायक साहिर की तरह कवि और शायर थे. वे भी अपने प्यार को पाने में नाकाम रहे थे. इसके आगे साहिर की निजी ज़िंदगी और इन फिल्मों का शायद ही कोई संबंध हो. चूंकि इन दोनों फिल्मों के गीत भी साहिर ने ही लिखे थे और इनमें उनकी पहले से लिखी नज़्मों का बहुत ख़ूबसूरत प्रयोग किया गया था, इसलिए इस तरह की संभावनाएं खोज लेना आम बात थी. साहिर का अस्तित्व सिर्फ़ सिनेमा में ही नहीं था, बल्कि वह उर्दू साहित्य की एक बड़ी शख़्सियत थे. साहिर ज़िंदगी भर अविवाहित रहे और उन्होंने अपना दबदबा फिल्मी दुनिया में क़ायम रखा. उनका नाम जिस फिल्म से जुड़ता था, उसमें वह सर्वोपरि होते थे. वह सिनेमा स्टार की तरह रहे, कवि या शायर की तरह नहीं. पीढ़ियों को लांघने वाली इस प्रेमकथा में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को उनकी स्थापित छवि एंग्री यंगमैन के बिल्कुल विरुद्ध एक संवेदनशील प्रेमी में तब्दील कर दिया था, उसे आमजन के बीच स्वीकार्य भी बना दिया था. 1975 से 1992 तक इस तरह की भूमिका में कोई अन्य निर्देशक जनमानस के बीच अमिताभ बच्चन को स्वीकार्य नहीं बना सका. यश चोपड़ा ख़ुद भी यह एक ही बार कर सके. अमिताभ और रेखा के अविस्मरणीय प्रणय दृश्यों के बावजूद सिलसिला को वह सहज लोकप्रियता नहीं मिली, जो कभी-कभी के हिस्से आई थी. सिलसिला का दिल को छू लेने वाला मधुर संगीत लोकप्रिय और श्रेष्ठ होने के बाद भी उस तरह जन-जन तक मन की हूक बनकर नहीं घुला-मिला, जैसे कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है...

फिल्म की पूरी ताक़त उसके शुरुआती दस मिनट हैं. अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो पूरी फिल्म नीरस हो जाएगी. नायिका नायक के गीत पर मुग्ध है और उससे ऑटोग्राफ मांगती है. नायक हतप्रभ है. जब वह ऑटोग्राफ देते हुए उसका नाम पूछता है तो नायिका कहती है कि उसका नाम पूजा है. नायक का जवाब होता है, तो मुझे पुजारी समझिए. इसी तरह विवाह के बाद नायिका का पति भी कहता है कि क्या मेरा नाम पुजारी नहीं हो सकता? नायिका के लिए एक नहीं, दो मुक़ाम हैं, जहां वह ईश्वरीय पवित्रता का रूप रखती है. कुल मिलाकर यह किताब यश चोपड़ा की फिल्मों का एक ख़ूबसूरत सफ़रनामा है.

विकास कुमार
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
रैदास वाणी

लेखिका
रचना भोला 'यामिनी'

प्रकाशक
डायमंड बुक्स

मूल्य
75 रुपये

इस किताब में संत रैदास की जीवनी और उनकी रचनाएं शामिल की गई हैं.

सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

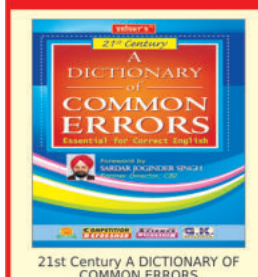
21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS
₹ 99

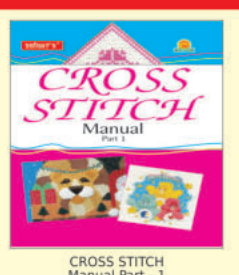
CROSS STITCH Manual Part - 1
₹ 60

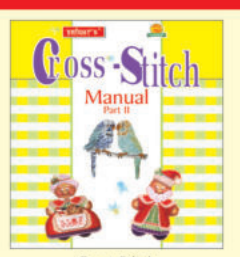
Cross-Stitch Manual Part - II
₹ 70

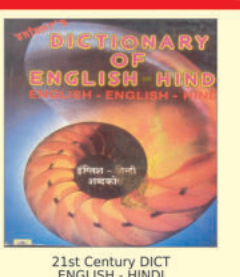
21st Century DICT ENGLISH - HINDI
₹ 75

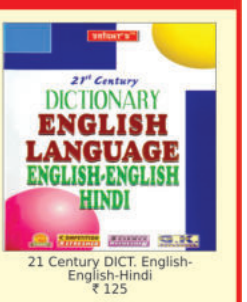
21 Century DICT. English-English-Hindi
₹ 125

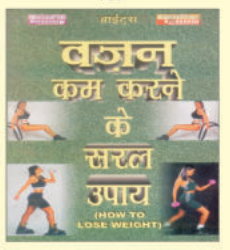
वज़न कम करने के सरल उपाय
₹ 50

इंगलिश सीखिए और बोलिए
₹ 199

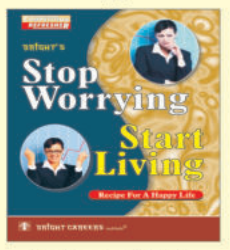
Stop Worrying Start Living
₹ 50

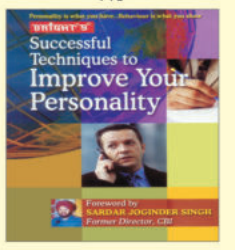
Successful Techniques to Improve Your Personality
₹ 99

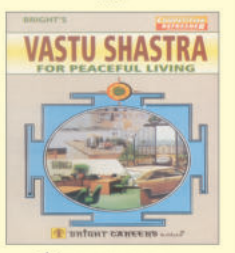
★ VASTU SHASTRA
₹ 70

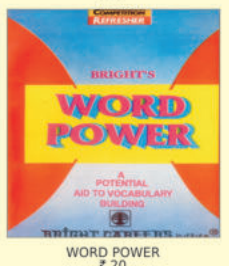
WORD POWER
₹ 20

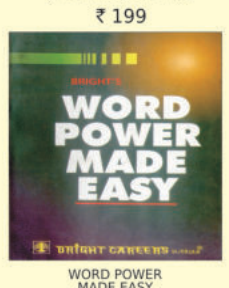
WORD POWER MADE EASY
₹ 80

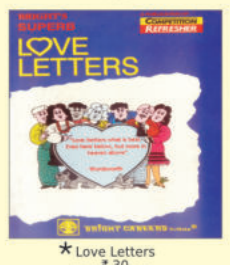
★ Love Letters
₹ 30

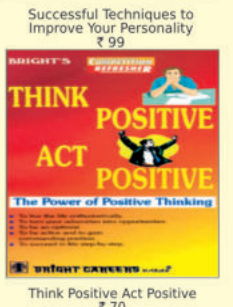
Think Positive Act Positive
₹ 70

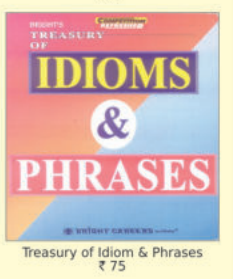
Treasury of Idiom & Phrases
₹ 75

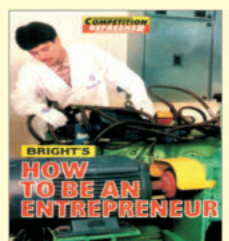
How to be an Entrepreneur
₹ 50

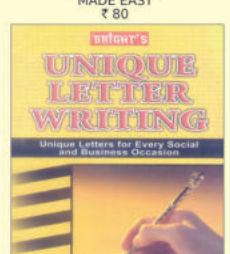
Unique Letter Writing
₹ 45

Guide to Good Health
₹ 40

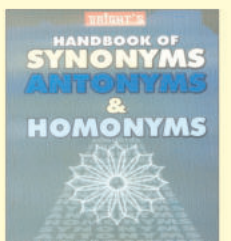
Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms
₹ 75

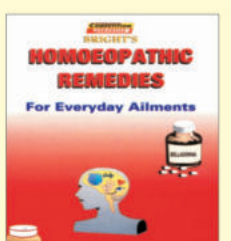
Homoeopathic Remedies
₹ 40

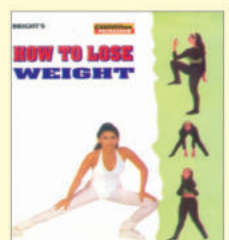
How to Lose Weight
₹ 50

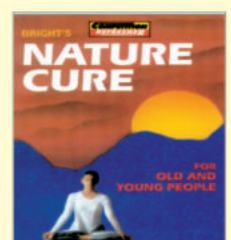
Nature Cure
₹ 35

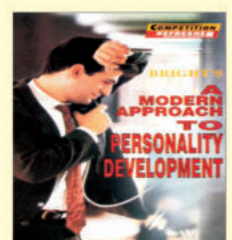
A Modern Approach to Personality Development
₹ 45

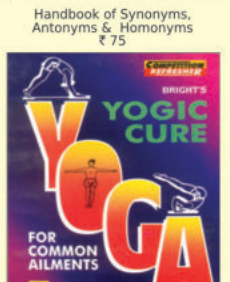
★ Yogic Cure
₹ 40

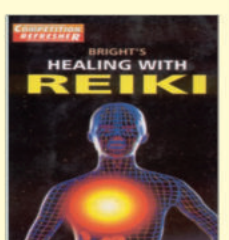
★ Healing with Reiki
₹ 60
★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

ब्राईट पब्लिकेशंस
भारत में सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियोगिता पुस्तकों के प्रकाशक
2767, कूचा चैलान, दरियागंज, दिल्ली-110002 (भारत) (स्थापित : 1968)
फोन : 011-64632226, 23282226, 23283226 — फैक्स : 011-23269227
ई-मेल: sales@brightpublications.com | वैब साइट: http://www.brightpublications.com

भारत में टेबलेट और स्मार्ट फोन का बाज़ार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए वह भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत बनाना चाहती है.

एचटीसी का इवो

टीवी में तो थ्रीडी का मज़ा आपने लिया ही होगा, मगर अब आप अपने मोबाइल में थ्रीडी मूवी और वीडियो देख सकेंगे. एचटीसी ने कई शानदार फीचरों से लैस इवो 3–डी नामक 3–डी मोबाइल बाज़ार में लांच कर दिया है. हाल में एलजी भी अपना ऑप्टिमस 3–डी फोन लांच कर चुकी है, मगर एचटीसी के इवो 3–डी में आप बिना चश्मे के 3–डी का मज़ा ले सकते हैं. नए इवो 3–डी में 4.3 इंच की स्क्रीन दी गई है. यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 1.2 गीगाहट्र्ज ड्यूल कोर प्रोसेसर पर चलता है, जो इसे दमदार परफार्मेंस देता है. 3–डी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए इवो में 5 मेगा पिक्सल के दो कैमरे दिए गए हैं, जो 2 मेगा पिक्सल के रेज्युलेशन के साथ 30 फ्रेम प्रति सेकेंड की गति से दो पिक्चर मिलाकर एक थ्रीडी पिक्चर तैयार करते हैं. एचटीसी इवो में 4 जीबी इंटरनल मेमोरी है, जो 32 जीबी एक्पेंडेबल है. इसमें 1 जीबी की रैम दी गई है. अगर आप अपने मोबाइल के 3–डी वीडियो को टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो सिर्फ़ अपने मोबाइल को 3–डी टीवी से अटैच कर दीजिए. स्क्रीन आइकॉन में तुरंत एक्सेस के लिए कई तरह के शार्टकट आइकॉन दिए गए हैं. इवो में दिए गए उन्नत प्रोसेसर की वजह से इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है. इसमें 1730 एमएएच लीथियम बैटरी दी गई है, जो 9 घंटे का टॉकटाइम देती है. एचटीसी इवो के फीचर एक नज़र में भा जाने वाले हैं. यह एंडरॉयड जिंजरब्रेड 2.3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है. इसमें 5 मेगा पिक्सल के दो कैमरे हैं. एचटीसी का यह नया इवो बाज़ार में 35,900 रुपये में उपलब्ध है.

इवो में दिए गए उन्नत प्रोसेसर की वजह से इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है. इसमें 1730 एमएएच लीथियम बैटरी दी गई है, जो 9 घंटे का टॉकटाइम देती है.

लैपटॉप में 3-डी का मज़ा

टेक्नालॉजी के क्षेत्र में दिनोंदिन उन्नति हो रही है. जहां पहले टेबलेट लांच हुए, वहीं लैपटाप में भी कई सुधार होते जा रहे हैं. चाहे वे नए प्रोसेसर हों या फिर स्क्रीन. एलजी ने एक क़दम आगे बढ़ाते हुए 3–डी टेक्नालॉजी से लैस लैपटाप बाज़ार में उतारने का निर्णय लिया है, जिनमें न सिर्फ़ डिजिटल पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, बल्कि ये हाई ग्राफिक को भी सपोर्ट करते हैं. पीसी बाजार में एलजी एक जानी–मानी कंपनी है, जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के अलावा कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है.

एलजी जल्द ही बाज़ार में एक्स नोट ए–530 नाम से 3–डी लैपटॉप पेश करेगी. इसमें 15.6 इंच की एचडी एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसमें कई तरह के ग्लास की परतों की वजह से इसकी 3–डी इमेज क्वालिटी काफी अच्छी है. कंपनी 3–डी ग्लास की कुछ क्लिपें भी साथ में दे रही है, जिन्हें साधरण लेंस में लगाकर आप 3–डी का मज़ा ले सकते हैं. नए एक्स नोट ए– 530 में इंटर का 2 जेनरेशन कोर आई–7 प्रोसेसर दिया गया है, जो 8 जीबी की रैम के साथ अच्छी परफार्मेंस देता है. 3–डी ग्राफिक के लिए एक्स नोट ए–530 में एनवीडिया जी फोर्स जीटी 555 एम ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जो एक जीबी का मेमोरी स्पेस लेता है. 750 जीबी के हार्ड डिस्क सपोर्ट के साथ एक्स नोट ए–530 में दो वेब कैम की सुविधा है, जो हाई क्वालिटी की 2–डी और 3–डी इमेज को कैप्चर करता है. सबसे आकर्षक फीचर है कॉम्बो ड्राइव, जिसमें ब्लूरे और डीवीडी की सुविधा दी गई है. कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई और ब्लूटुथ की मदद से आप डाटा ट्रांसफर और इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप मूवी और गानों का लुत्फ लेना चाहते हैं तो 3–डी पिक्चर के साथ नए एक्स नोट ए–530 में 3–डी एसआरएस टेक्नालॉजी से लैस दमदार साउंड क्वालिटी भी मिलती है. लैपटाप ऑन करने के लिए आपको पासवर्ड एक्सेस करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप आपके छूने से ही खुले तो इसके लिए इसमें फिंगर प्रिंट टेक्नालॉजी भी है, जो हाल में आई लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नालॉजी है. इसमें 7 इन कार्ड रीडर का फीचर भी आकर्षक है, जो 7 तरह के ऑप्शन प्रोवाइड कराता है. एलजी के एक्स नोट ए–530 में न केवल आप 3–डी पिक्चर्स देख सकते हैं, बल्कि चाहें तो अपनी 3–डी इमेज भी बना सकते हैं.

सैमसंग के नए टेबलेट्स

सारी कंपनियां चाहती हैं कि टेबलेट बाज़ार में आ रहे इस बूम को लपक लिया जाए. बाज़ार में हिस्सेदारी के मामले में एप्पल के आईपैड की धाक है, लेकिन अब उसके प्रतिद्वंद्वी भी मैदान में उतर रहे हैं.

टेबलेट बाज़ार में प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है. आने वाले सालों में टेबलेट बाज़ार में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. वर्ष 2011 के अंत तक टेबलेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी. सारी कंपनियां चाहती हैं कि टेबलेट बाज़ार में आ रहे इस बूम को लपक लिया जाए. बाज़ार में हिस्सेदारी के मामले में एप्पल के आईपैड की धाक है, लेकिन अब उसके प्रतिद्वंद्वी भी मैदान में उतर रहे हैं. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी सैमसंग ने दो नए टेबलेट लांच किए हैं. ये दोनों टेबलेट एंड्रॉयड आधारित हैं. गैलेक्सी टेब–730 और गैलेक्सी टेब–750 नामक इन टेबलेट्स की भारत में क़ीमत क्रमशः 33,900 और 36,200 रुपये है. कंपनी का कहना है कि भारत में टेबलेट और स्मार्ट फोन का बाज़ार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए वह भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत बनाना चाहती है. पिछले साल अक्टूबर में भी कंपनी ने एक टेबलेट लांच किया था, जिसकी क़ीमत 38 हज़ार रुपये रखी गई थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एंड्रॉयड फोन

स्मार्ट फोन–एंड्रॉयड फोन की बात करें तो दिमाग़ में सैमसंग, एचटीसी, एप्पल एवं नोकिया जैसी कंपनियों के नाम आते हैं. देशी कंपनियों ने भी भारतीय बाजार में अपने एंड्रॉयड स्मार्ट फोन लांच कर दिए हैं, मगर उनकी क़ीमत काफी ज़्यादा है, जो सबके बजट में फिट नहीं बैठती. इसी को ध्यान में रखते हुए सिस्तेमा श्याम टेली सर्विसेज (एसएसटीएल) की एमटीएस ने मात्र 5,000 रुपये से भी कम क़ीमत में दो एंडरायड फोन लांच किए हैं. एमटीएस इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विसेवोलोद रोजानोव ने बताया कि स्मार्ट फोन एमटीएस एमटैग 3.1 और एमटीएस लाइववायर दोनों ही क्वालकॉम के मोबाइल प्रोसेसर पर काम करते हैं, जिसमें आडियो और वीडियो की सुविधा दी गई है. आप चाहें तो गूगल मैप, गूगल टॉक, गूगल मेल का प्रयोग भी कर सकते हैं. फोटो कैप्चरिंग के लिए एमटीएस एमटैग में 3.2 मेगा पिक्सल कैमरे के अलावा कई शानदार फीचर होंगे. बाजार में इतने कम दाम में किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है.

किंगमैक्स की मल्टीकलर ड्राइव

पेन ड्राइव कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय है. पेन ड्राइव की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण शायद यह है कि इसमें एक फ्लॉपी या सीडी/डीवीडी से कहीं अधिक डेटा रखा जा सकता है, जबकि पेन ड्राइव का आकार इनसे कई गुना कम होता है. आकार छोटा होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सरल है. इसी कारण कई लोग अपने निजी एवं संवेदनशील डेटा संचित करने के लिए भी पेन ड्राइव का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने लगे हैं. पेन ड्राइव की सुरक्षा पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि डेटा की सुरक्षा भी इसी पर निर्भर करती है. अपने डेटा और अन्य दस्तावेजों के स्टोरेज को लेकर चिंतित रहने वाले लोगों के लिए अब एक नई पेन ड्राइव बाज़ार में आई है. मेमोरी उपकरण बनाने वाली मशहूर कंपनी किंगमैक्स ने पीडी–03 नाम से एक पेन ड्राइव लांच की है. इसे तीन रंगों में बाज़ार में उतारा गया है. रंगों के हिसाब से इनकी मेमोरी भी अलग–अलग है. हरे रंग की पेन ड्राइव की मेमोरी 5 जीबी से 32 जीबी तक है. लाल रंग की पेन ड्राइव की मेमोरी 4 जीबी से 32 जीबी तक है. जबकि नीले रंग की पेन ड्राइव की मेमोरी 8 जीबी है. कंपनी का कहना है कि इनका वजन बहुत कम यानी केवल 9 ग्राम है. इनमें दस्तावेजों के साथ ही संगीत, वीडियो और फोटोग्राफ भी स्टोर किए जा सकते हैं.

पीडीएफ रिकवरी सॉफ्टवेयर

तकनीकी उपकरणों पर काम करना कभी–कभी परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन अब ऐसी परेशानियों के लिए उपाय भी बाज़ार में उपलब्ध हो गए हैं. कई बार अनजाने में या फिर किसी अन्य कारणवश कंप्यूटर या किसी मेमोरी में पड़ी आपकी कोई पीडीएफ फाइल करप्ट हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपका काफी नुक़सान हो जाता है, लेकिन अब स्टेलर फोनिक्स ने आपकी इस समस्या का समाधान खोज निकाला है. कंपनी ने एक पीडीएफ रिकवरी सॉफ्टवेयर लांच किया है. पीडीएफ रिकवरी वी–1 नामक इस सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी के साथ करप्ट पीडीएफ फाइल फिर से प्राप्त की जा सकती है. कंपनी का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप तीन आसान चरणों में अपनी करप्ट पीडीएफ फाइल दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. कंपनी ने इसकी क़ीमत दो हज़ार रुपये रखी है और काम न करने की स्थिति में 30 दिनों के अंदर पैसा वापस करने की गारंटी भी दी है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

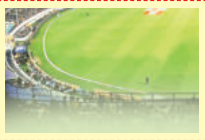

सात टीमें पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, जबकि शेष तीन टीमों का फ़ै सला छह टीमों के बीच 19 से 21 सितंबर तक हैदराबाद में होने वाले क्वालीफाई टूर्नामेंट से होगा.

फिर से फटाफट क्रिकेट

तारीख	समय	मैच	स्थान
19 सितंबर 2011	16:00	क्वालीफायर : त्रिनिदाद एंड टोबैगो बनाम रूहाना रीहीनोस	हैदराबाद
19 सितंबर 2011	20:00	क्वालीफायर: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम ऑकलैंड एसेस	हैदराबाद
20 सितंबर 2011	16:00	क्वालीफायर: त्रिनिदाद एंड टोबैगो बनाम लेसेसस्टर शायर	हैदराबाद
20 सितंबर 2011	20:00	क्वालीफायर: सोमरसेट बनाम ऑकलैंड एसेस	हैदराबाद
21 सितंबर 2011	16:00	क्वालीफायर: लेसेसस्टर शायर बनाम रूहाना रीहीनोस	हैदराबाद
21 सितंबर 2011	20:00	क्वालीफायर: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सोमरसेट	हैदराबाद
23 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप बी: पहला टी-20: रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु बनाम शेवरोलेट वॉरियर्स	बंगलुरु
24 सितंबर 2011	16:00	ग्रुप ए: दूसरा टी-20: केप कोबरास बनाम न्यू साउथ वेल्स बल्यूस	चेन्नई
24 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप ए: तीसरा टी-20: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस	चेन्नई
25 सितंबर 2011	16:00	ग्रुप बी: चौथा टी-20: शेवरोलेट वॉरियर्स बनाम साउथ ऑस्ट्रेलियन रेडबेक्स	कोलकाता
25 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप बी: पांचवा टी-20: टीबीसी बनाम टीबीसी	कोलकाता
26 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप ए: छठा टी-20: मुंबई इंडियंस बनाम टीबीसी	बंगलुरु
27 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप बी: सातवां टी-20: टीबीसी बनाम साउथ ऑस्ट्रेलियन रेडबेक्स	कोलकाता
28 सितंबर 2011	16:00	ग्रुप ए: आठवां टी-20: न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यूस बनाम टीबीसी	चेन्नई
28 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप ए: नौवां टी-20: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम: केप कोबरास	चेन्नई
29 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप बी: दसवां टी-20: टीबीसी बनाम रॉयल चैलेंजर्स	कोलकाता
30 सितंबर 2011	20:00	ग्रुप ए: ग्यारहवां टी-20: मुंबई इंडियंस बनाम केप कोबरास	बंगलुरु
1 अक्टूबर 2011	16:00	ग्रुप बी: बारहवां टी-20: साउथ ऑस्ट्रेलियन रेडबेक्स बनाम टीबीसी	कोलकाता
1 अक्टूबर 2011	20:00	ग्रुप बी: तेरहवां टी-20: टीबीसी बनाम शेवरोलेट वॉरियर्स	कोलकाता
2 अक्टूबर 2011	16:00	ग्रुप ए: चौदहवां टी-20: मुंबई इंडियंस बनाम न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यूस	चेन्नई
2 अक्टूबर 2011	20:00	ग्रुप ए: पंद्रहवां टी-20: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम टीबीसी	चेन्नई
3 अक्टूबर 2011	20:00	ग्रुप बी: सोलहवां टी-20: रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु बनाम टीबीसी	बंगलुरु
4 अक्टूबर 2011	16:00	ग्रुप ए: सत्रहवां टी-20: केप कोबरास बनाम टीबीसी	चेन्नई
4 अक्टूबर 2011	20:00	ग्रुप ए: अट्ठारहवां टी-20: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यूस	चेन्नई
5 अक्टूबर 2011	16:00	ग्रुप बी: उन्नीसवां टी-20: शेवरोलेट वॉरियस बनाम टीबीसी	बंगलुरु
5 अक्टूबर 2011	20:00	ग्रुप बी: बीसवां टी-20: रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु बनाम यू साउथ वेल्स ब्ल्यूस	बंगलुरु
7 अक्टूबर 2011	20:00	पहला सेमी फाइनल: टीबीसी बनाम टीबीसी	बंगलुरु
8 अक्टूबर 2011	20:00	दूसरा सेमी फाइनल: टीबीसी बनाम टीबीसी	चेन्नई
9 अक्टूबर 2011	20:00	फाइनल : टीबीसी बनाम टीबीसी	चेन्नई

चैंपियंस लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत को सौंपी गई है और इसके मैच 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में खेले जाएंगे. लीग में रिकॉर्ड 13 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन मुख्य टूर्नामेंट दस टीमों के बीच ही खेला जाएगा. टूर्नामेंट पिछले संस्करण के आधार पर ही खेला जाएगा. सात टीमें पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, जबकि शेष तीन टीमों का फ़ैसला छह टीमों के बीच 19 से 21 सितंबर तक हैदराबाद में होने वाले क्वालीफाई टूर्नामेंट से होगा. आईपीएल में चौथे स्थान पर रही कोलकाता नाइट राइडर्स, वेस्टइंडीज की घरेलू टी-20 चैंपियन त्रिनिदाद एंड टोबेगो और न्यूजीलैंड की घरेलू चैंपियन आकलैंड एसेस तथा इंग्लैंड की दो और श्रीलंका की एक टीम क्वालीफाई टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. हालांकि इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों ने अभी इसमें खेलने की पुष्टि नहीं की है. आईपीएल की विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स, उपविजेता रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, तीसरे नंबर की टीम मुंबई इंडियंस, आस्ट्रेलिया की साउथ आस्ट्रेलियन रेडबेक्स, न्यू साउथ वेल्स ब्लूज, दक्षिण अफ्रीका की वारियर्स और केप कोबराज की टीमें पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

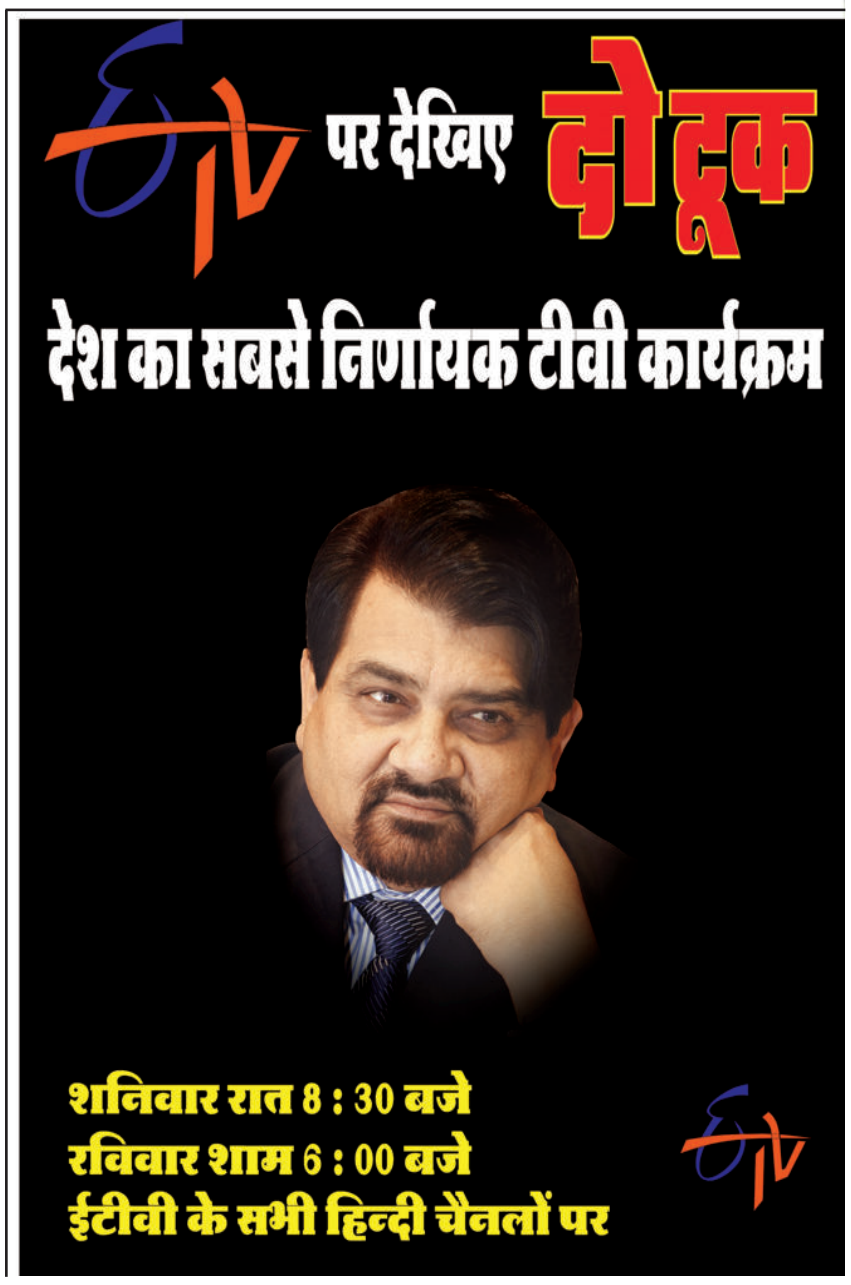

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 19 सितंबर–25 सितंबर 2011

यशराज बैनर की फिल्म धूम-3 में आमिर ख़ान के अपोजिट कास्ट होने के लिए कई अभिनेत्रियां कोशिश कर रही हैं. इनमें दीपिका पादुकोण सबसे आगे हैं.

ईशा का डर

बॉलीवुड में काफी लंबे समय बाद ईशा देओल एक धमाकेदार एंट्री करने वाली हैं. वह एक बार फिर अपनी क़िस्मत आजमाने के लिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं फिल्म टेल मी ओ खुदा से. उपेक्षा का एक लंबा दौर देख चुकी ईशा बहुत हिम्मत बांधकर वापसी कर रही हैं. ज़ाहिर है, इस फिल्म से उन्हें उम्मीदें भी बहुत हैं. फिल्म की ख़ास बात यह है कि इसकी डायरेक्टर ख़ुद हेमा मालिनी हैं. एक और ख़ास बात है कि धर्मेंद्र ने भी अपनी बेटी की खातिर अभिनय किया है. ईशा अपने माता-पिता की तरह इंडस्ट्री में धाक नहीं जमा पाईं. अपने करियर में ईशा को कोई ख़ास सफलता नहीं मिली. ईशा ने कई फिल्में कीं, लेकिन कोई जोरदार सफलता हाथ नहीं लगी. जो भी सफलता हाथ लगी, उसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिल सका, क्योंकि वे फिल्में मल्टीस्टारर थीं. लगातार फिल्में फ्लॉप होने की वजह से वह पर्दे से बहुत दूर हो गई थीं. फिर भी निराश नहीं हैं ईशा. दरअसल, ईशा किसी और चीज से डरती हैं. उन्हें हारर फिल्में करना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे दिमाग़ जागरूक हो जाता है और अभिनय करते समय उन्हें ख़ुद डर लगने लगता है. उन्होंने अब तक 20 फिल्मों में काम किया और उनमें से उनकी पसंदीदा फिल्म अनकही है. इसमें उन्होंने मानसिक रोगी का किरदार निभाया था. इसके अलावा उन्हें युवा, डार्लिंग और धूम में भी ख़ूब मजा आया था. ये उनके करियर की यादगार फिल्में हैं. टेल मी ओ खुदा के लिए उन्होंने ख़ूब मेहनत की है. स्क्रिप्टिंग, स्टेज से लेकर हर स्तर तक. ईशा का कहना है कि यह ज़िंदगी का एक नया फेज है, जहां वह मूवी की सिर्फ़ एक एक्ट्रेस नहीं हैं. वह एडिटिंग और प्रोसेसिंग जैसे अलग लेवल पर भी इन्वॉल्व रही है. उन्होंने फिल्म निर्माण के छोटे-छोटे पहलुओं को भी समझा. अब तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा टेल मी ओ खुदा का जवाब.

दीपिका की कोशिश

बॉलीवुड सितारे कभी किसी के साथ नज़र आते हैं तो कभी किसी के साथ. कुछ समय बाद आने वाली यशराज बैनर की फिल्म धूम-3 में आमिर ख़ान के अपोजिट कास्ट होने के लिए कई अभिनेत्रियां कोशिश कर रही हैं. इनमें दीपिका पादुकोण सबसे आगे हैं. ऐसा सुनने में आया कि दीपिका ने ख़ुद फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा से इस बारे में बात की, क्योंकि वह धूम-3 में अपने पसंदीदा अभिनेता आमिर के साथ काम करने को इच्छुक हैं. वैसे तो दोनों की जोड़ी ख़ूब जमेगी, लेकिन थोड़ा सा अड़ंगा दीपिका की हाइट को लेकर हो सकता है, क्योंकि वह आमिर से काफी लंबी हैं. ख़बर यह भी है कि अगर दोनों की जोड़ी रिजेक्ट हो जाती है तो विदेशी तारिकाओं को भी मौक़ा मिल सकता है. इसके लिए नताली पोर्टमैन, इव लोंगोरिया और पेनेलोप क्रूज के नाम चर्चा में हैं. इस फिल्म के लिए कैटरीना को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने बिकनी पहनने से इंकार कर दिया. अब देखना यह है कि अगर दीपिका इस फिल्म के लिए फाइनल हो जाती हैं तो वह बिकनी में दिखती हैं या नहीं.

फिल्म प्रीव्यू

यू आर माई जान

हीर रांझा, लैला मजनूं, दिल है कि मानता नहीं और आशिकी आदि ऐसी फिल्में हैं, जो बॉलीवुड की फेवरिट और हिट थीम लव स्टोरी पर बेस्ड हैं. ये सभी अलग-अलग वक्त पर रिलीज हुईं और इन्होंने ख़ूब बढ़िया बिजनेस किया, लेकिन ऐसी लव स्टोरी बेस्ड रोमांटिक फिल्में काफी समय से देखने को नहीं मिल पा रही हैं. इस वजह से ऐसी फिल्में देखने की चाह रखने वाले दर्शकों को निराशा हो रही थी, लेकिन ऐसे ही दर्शकों के लिए ख़ास तौर से एक फिल्म बनाई है एरोन गोविल प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने. इस बैनर तले बनी फिल्म का नाम है यू आर माई जान. फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं एरोन गोविल. यू आर माई जान आजकल की युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छी लव स्टोरी वाली फिल्म है. फिल्म की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के बिजनेस टाइकून आकाश यानी मिकाल से, जो वहां से मुंबई आता है, जिसे बिजनेस के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती. उधर रीना यानील प्रिती नामक लड़की चंडीगढ़ से मुंबई आती है, जो बॉलीवुड में बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती है. संयोगवश दोनों की मुलाक़ात होती है और फिल्म कैसे करवट बदलती है, इस चीज को काफी ख़ूबसूरती के साथ दिखाया गया है. फिल्म के हीरो मिकाल हैं, जिन्होंने इससे पहले फिल्म शूट ऑन साइट में काम किया है और प्रिती की बतौर अभिनेत्री यह पहली फिल्म है. निर्माता-निर्देशक एरोन गोविल अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. इससे पहले उन्होंने फिल्म शूट ऑन साइट का निर्माण और कई फिल्मों को फाइनेंस किया है. फिल्म यू आर माई जान में संगीत संजीव दर्शन ने दिया है, कैमरा वर्क शीर्षा रे का है. संजय इंगले ने एडिटिंग की है और आर्ट वर्क किया है सुनील नीगवेकर ने. फिल्म के मुख्य कलाकार मिकाल और प्रिती के अलावा राजेश खेरा, अमन वर्मा, हिमानी शिवपुरी, अनिल धवन, ऐश्वर्या सखुजा, अभिलाषा और रवि दुबे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुग्धा की ख़ुशी का राज़

यह तो नहीं पता कि मुग्धा कुछ वक़्त पहले आई अपनी हिट फिल्म फैशन के सिक्वल में रहेंगी या नहीं, लेकिन वह निराश हरगिज नहीं हैं. यही वजह है कि वह अपने अगले प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. फ़िलहाल उनके ख़ुश रहने और उदास न होने के कई कारण हैं. पहला कारण है कि अभी हाल में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया. अब इसे संयोग कहा जाए या भाग्य, लेकिन मुग्धा ने एक बार फिर अपना जन्मदिन थाईलैंड में मनाया. पिछले साल भी वह अपने जन्मदिन पर फिल्म विल यू मैरी मी की शूटिंग के लिए वहीं थीं. इस साल भी वह फिल्म अफरातफरी की शूटिंग के लिए थाईलैंड में थीं. मुग्धा ख़ुश थीं कि आधी रात को फिल्म की टीम ने उन्हें सरप्राइज पार्टी दी, जिसमें गोविंदा, सुनील शेट्टी, गुलशन ग्रोवर, आर्य बब्बर, प्रोड्यूसर किशन चौधरी और निर्देशक इशराक शाह मौजूद थे. पिछले साल भी उन्हें इसी तरह सरप्राइज पार्टी दी गई थी. एक तो फिल्म की शूटिंग और फिर जन्मदिन की ख़ुशी, तनाव भला कैसे होगा. मुग्धा जल्द ही फिल्म गली-गली में चोर है में नज़र आएंगी, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग भोपाल में तय की गई है. बॉलीवुड की फिल्मों के साथ ही मुग्धा दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं. वह क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी पर बनने वाली फिल्म में काम करने वाली हैं. यह फिल्म बन रही है तेलुगु सिनेमा वर्ल्ड में, लेकिन बॉलीवुड में कम फिल्में मिलने की वजह से मुग्धा ने साउथ की फिल्मों में काम करना बेहतर समझा. एक्टर-डायरेक्टर प्रकाश राज की पत्नी पोनी वर्मा, जो मुग्धा की अच्छी दोस्त हैं, उनकी बात मानकर वह फिल्म धोनी में काम करने के लिए तैयार हो गईं. यह फिल्म मुग्धा के करियर में उछाल ला सकती है, क्योंकि इसे सिर्फ़ तेलुगु ही नहीं, बल्कि तमिल भाषा में भी रिलीज किया जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

हॉट प्रियंका

शाहिद कपूर को आजकल प्रियंका काफी हॉट लग रही हैं, तभी तो हाल में एक बयान में शाहिद ने अपनी एक्स लवर करीना को हॉट न बताकर प्रियंका को हॉट बताया. शाहिद कपूर और प्रियंका दोनों पुराने आशिक हैं. हालांकि पिछले दिनों उनके बीच ब्रेकअप की ख़बरें आई थीं, लेकिन अब सुनने में आया है कि वे दोबारा नज़दीक आ रहे हैं. पिछले दिनों दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी हैं और इस दौरान कई बार उन्हें एक-दूसरे के साथ देखा गया है. ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों प्रियंका चोपड़ा का नाम हरमन बावेजा से लेकर रणबीर कपूर और अक्षय कुमार तक जोड़ा जा चुका है. ऐसे में यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि उनका मिस्टर राइट कौन होगा. दूसरी ओर शाहिद करीना कपूर से ब्रेकअप के बाद अब तक अपने लिए कोई पार्टनर तलाश नहीं पाए हैं. अब एक बार फिर शाहिद और प्रियंका के क़रीब आने की ख़बरें साफ इशारा करती हैं कि दोनों एक-दूसरे के बिना बेकरार हैं. अब दोनों अपनी आने वाली फिल्में साथा और पिगी के अलावा कुणाल कोहली की एक अन्य फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 19 सितंबर–25 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

भाजपा

क़द बढ़ाने की बेचैनी

सरोज सिंह

बिहार में जदयू–भाजपा गठबंधन में खटास का स्वाद अब साफ़–साफ़ पता चलने लगा है. भाजपा में स्पष्ट राय बनने लगी है कि अब पहले वाली बात नहीं है. पार्टी अपनी ताक़त के हिसाब से सम्मान पाने की हक़दार है और उसे उसका हक़ मिलना ही चाहिए, लेकिन जदयू अपने बड़े भाई की हैसियत में रत्ती भर भी कमी नहीं चाहता है. जदयू चाहता है कि पहली पारी की तरह इस सरकार में भी भाजपा अपनी भूमिका निभाए, पर भाजपा दूसरी पारी में इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि जनता ने उसकी हैसियत चुनाव में बढ़ा दी है. पूर्णिया उपचुनाव में अल्पसंख्यकों के मिले समर्थन से भी भाजपा का हौसला बढ़ा है. अगड़ी जातियों में तो उसकी मज़बूत पैठ है ही. दलित, महादलित व अति पिछड़ों को अपने पाले में लाने का अभियान शुरू हो गया है. ऐसे में भाजपा अब झुकने वाली इमेज से बचना चाहती है. हाल में ही कुंभ को लेकर अनंत कुमार का और गठबंधन को लेकर हृदय नाथ का जो बयान आया, उससे इसकी झलक मिल गई.

दरअसल इन्हीं कारणों से नीतीश कुमार अपनी दूसरी पारी में भाजपा को लेकर बहुत सुकून में नहीं हैं. सुशील मोदी व नीतीश कुमार भले ही एक–दूसरे को देखकर मुस्करा रहे हैं, पर दोनों ही पार्टियों में एक–दूसरे को लेकर कड़वाहट धीरे–धीरे बढ़ रही है. वजह बस एक ही है. जदयू व भाजपा दोनों ही चाहते हैं कि वे ज़्यादा मज़बूत दिखें. सत्ता संतुलन के लिए यह आवश्यक शर्त है. दोनों ही दलों के संगठन से जुड़े लोग अपनी पूरी ताक़त से कार्यक्रम बनाकर अपना आधार और मज़बूत करने में जुटे हैं. जदयू ने जब विशेष राज्य के बाद पौधा लगाने का अभियान चलाया तो भाजपा को लगा कि वह पिछड़ती ही जा रही है. यही वजह रही कि वैशाली में कार्यसमिति की बैठक में पौधारोपण के मुक़ाबले में एक बड़ा अभियान चलाने की बात तय की गई. भाजपा का दर्द यह है कि सारी अच्छी चीज़ों का श्रेय जदयू के खाते में जा रहा है, जबकि विधानसभा में ताक़त के हिसाब से वह जदयू से ज़्यादा पीछे नहीं है. एएमयू की शाखा से लेकर कुंभ आयोजन तक भाजपा अपने स्टैंड पर मज़बूती से खड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है. इसका मलाल पार्टी को है और इसी पीड़ा ने भाजपा को कुछ आक्रामक होने का मौक़ा दिया.

कड़े तेवरों की शुरुआत फ़िलहाल केंद्रीय नेताओं ने की है. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी अनंत कुमार ने कहा कि सिमरिया घाट पर कुंभ का आयोजन होना ही चाहिए. उनका तर्क था कि समुद्र मंथन के जिस मंदार पर्वत का उपयोग किया गया वह बिहार में ही है. जब अमृत निकला तो इसकी कुछ बूंदें निश्चित रूप से सिमरिया में गिरी होंगी. इसलिए यहां कुंभ लगना ही चाहिए. कुमार ने कहा कि शंकराचार्य ने भी सिमरिया में कुंभ के आयोजन पर सहमति जताई है. साथ ही बनारस पंचांग, मिथिला पंचांग और दक्षिण भारतीय पंचांग में कुंभ के दावे का उल्लेख है. उधर, सर्वमंगला परिवार के संस्थापक स्वामी चिदात्मन जी महाराज समेत परिवार के सदस्य वहां अर्द्धकुंभ के आयोजन को मान्यता देने की मांग पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि संघ इस आयोजन का पूरी तरह समर्थन कर रहा है. पिछले दिनों जब संघ प्रमुख बिहार आए थे तो उन्होंने इसके संकेत दिए थे. इस सबके बीच राज्य सरकार का तर्क है कि धार्मिक आयोजन धर्माचार्यों का काम है, सरकार का काम सुविधाएं मुहैया कराना है. ऐसे समय में भाजपा के बिहार प्रभारी का सिमरिया कुंभ के पक्ष में खड़े होना आयोजकों का उत्साह बढ़ाएगा, पर इससे जदयू के माथे पर बल पड़ गया है. अनंत कुमार ने साफ़ किया कि किसी भी जगह का महत्व आस्था से जुड़ा होता है. इसलिए जनभावना से जुड़े मुद्दों पर विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. भाजपा नेता कुमार की बातों को आगे बढ़ाते हुए सिमरिया कुंभ आयोजन समिति के राज्य प्रतिनिधि और भाजपा वाणिज्य मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि समुद्र मंथन के बाद जहां भी अमृत की बूंदे गिरीं, वहीं मोक्षधाम बन गया. राजा जनक से लेकर मंडन मिश्र और विद्यापति तक ने सिमरिया में कल्पवास किया था. अभी भी वृद्धावस्था में लोग एक माह का कल्पवास करने सिमरिया आते हैं, इसलिए कुछ लोगों के सिमरिया के ख़िलाफ़ बयान देने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.

सिमरिया में कुंभ का आयोजन ज़रूर होगा. इसलिए आने वाले दिनों में कुंभ के आयोजन को लेकर तक़रार बढ़नी तय है. उधर, वैशाली में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी टकराव के रंग देखने को मिले. पूर्व प्रदेश क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं किसान मोर्चा के वर्तमान राष्ट्रीय प्रभारी हृदयनाथ ने माना कि बिहार की दृष्टि से हमारी स्थिति सुदृढ़ नहीं है. यह अलग बात है कि गठबंधन का दौर है. जदयू का नाम लिए बिना उन्होंने यहां तक कहा कि हमारी ताक़त के कारण ही लोग हमसे जुड़े हैं. सशक्त के साथ ही लोग जुड़ते हैं. हमें संगठन को अपने बलबूते खड़ा करने की संभावना तलाशनी होगी. मतलब इशारों ही इशारों में भाजपा ने साफ़ किया कि उसे अपने आप को इतना मज़बूत कर लेना है कि भविष्य में उसे किसी बैसाखी की ज़रूरत न पड़े. जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में चल रही गठबंधन सरकार को भाजपा वक़्त का तक़ाज़ा मान रही है. भाजपा की कोशिश यह है कि आनेवाले दिनों में स्वयं के बलबूते बिहार की गद्दी पर उसका क़ब्ज़ा हो. पार्टी को अपने बलबूते खड़ी करने की संभावना को तलाशने की अंदर ही अंदर कोशिश शुरू हो गई है, निशाना है दलित महादलित एवं अति पिछड़ों को पार्टी के पक्ष में गोलबंद कर मैदान जीतने का. ठोस रणनीति के साथ इस दिशा में ज़मीन पर प्रयास शुरू करने का पार्टी ने संकल्प लिया है, ताकि आने वाले दिनों में मिशन बिहार का सपना साकार हो सके. भाजपा के इन तेवरों का अहसास जदयू को भी है. इसलिए गठबंधन पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ प्रसाद सिंह ने बहुत ही संभली हुई प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन दो दलों का नहीं, बल्कि दो दिलों का है. हमलोग एक साझा कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल दिखाकर काम कर रहे हैं. बाक़ी दोनों पार्टियों की अपनी नीतियां व कार्यक्रम हैं और वे अपने–अपने स्तर से ख़ुद को मज़बूत करने का काम करती हैं. ग़ौरतलब है कि विस चुनाव के समय जदयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लेने की वकालत की थी. इस समय काफ़ी हंगामा हुआ था, पर चुनावी ज़रूरतों ने दोनों दलों को एक रखा. लेकिन नए जनादेश में दोनों ही दल अपनी–अपनी तैयारी में लगे हैं. जदयू का एक ख़ेमा इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो तब क्या होगा. ऐसे में न चाहते हुए भी जदयू को गठबंधन के मुद्दे पर पुनर्विचार करना होगा. इसलिए ज़रूरी है कि वार से पहले ही वार कर दिया जाए. देखना है कि जदयू व भाजपा का यह गठबंधन आने वाले दिनों में किस–किस चुनौतियों से गुज़रता है.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा नेता अनंत कुमार कुमार की बातों को आगे बढ़ाते हुए सिमरिया कुंभ आयोजन समिति के राज्य प्रतिनिधि और भाजपा वाणिज्य मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि समुद्र मंथन के बाद जहां भी अमृत की बूंदे गिरीं, वहीं मोक्षधाम बन गया. राजा जनक से लेकर मंडन मिश्र और विद्यापति तक ने सिमरिया में कल्पवास किया था. अभी भी वृद्धावस्था में लोग एक माह का कल्पवास करने सिमरिया आते हैं, इसलिए कुछ लोगों के सिमरिया के ख़िलाफ़ बयान देने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.

पीड़ित परिवार के लोगों ने कई बार पदाधिकारियों के कार्यालय की चौखट चूमी, लेकिन उनकी आवाज़ नक्कारख़ाने में तूती की आवाज़ साबित होकर रह गई.

ऐसा लगता है कि भारत की अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी खटाई में पड़ गई है.

परहेज़ ही बेहतर इलाज है : मिश्रा

डॉ.के.एस. मिश्रा

बरसात के ख़त्म होते ही कोसी इलाक़े के लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रख्यात जनरल फिज़ीशियन डॉ. के. एस. मिश्रा कहते हैं कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए. रोग के कारणों, बचाव व समाधान पर उनसे बातचीत के प्रमुख अंश.

- **कोसी इलाक़े में कौन-कौन से रोग के फैलने की संभावना दिखती है?**

कोसी इलाक़े में बरसात के मौसम में दमा, एलर्जी व चर्म रोग का प्रकोप बढ़ सकता है. वहीं बरसात के ख़त्म होते ही गैस्ट्रोइंट्राइटिस, वायरल इंफेक्शन जैसे नज़ला, इंफ्लुएंज़ा, स्वान फ्लू, बर्ड फ्लू आदि रोग का प्रकोप बढ़ेगा.

- **क्या इन रोगों में जानलेवा रोग भी हैं?**

नज़ला, इंफ्लुएंज़ा आदि अतीत में भी महामारी का कारण बने और आज भी बन सकते हैं. वहीं दमा का रोग निदान न होने से यह भी जानलेवा बीमारी है. आज तक दमा के रोग का निदान नहीं ढूंढा जा सका है.

- **इन रोगों से ग्रसित लोगों के प्राथमिक उपचार किए जाने क्या करना चाहिए?**

प्राथमिक उपचार के लिए एंटीहिस्टमनेट, गलगला करना, सूंघने वाली दवा (जो युकेलिप्टस के तेल से बनी हो) को सूंघना, लहसुन को तेल में डाल गर्म करके पैर, तलवा, हाथ, नाक, गर्दन, पीठ पर मालिश करनी चाहिए. नीम के पत्ते से चर्म रोग का उपचार फ़ायदेमंद साबित होगा. वहीं गैस्ट्रोइंट्राइटिस (कै, दस्त) के शिकार बच्चे अधिक हो जाते हैं, जो इनके लिए जानलेवा है. अत: इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं.

- **रोगों को नियंत्रित रखने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?**

जनरल इंफ्लुएंज़ा अपने आप कंट्रोल होता है. वहीं चर्म रोग को नियंत्रित करने के लिए नीम पांच रोज़ पत्ते से बचें. खान-पान में सावधानी बरतें, स्वान फ्लू की जांच अस्पताल में उपलब्ध है, जांच कराएं. इन रोगों के होने के पश्चात होने वाले अन्य रोगों का उपचार संभव है और सावधानी बरतने पर इन पर नियंत्रण भी संभव है.

- **ऐसी सलाह जिससे इन रोगों से बचा जा सके?**

गोल बैंगन (भाटा) और रखे हुए पत्तल बहुत प्रदूषित होते हैं. इनमें कई जानलेवा बीमारी के विषाणु मौजूद होते हैं. इनसे बचने की आवश्यकता है. छोटी मछली और खुले में रखी चीज़ों को न खाएं. बूट पहन कर खेती का काम करें और रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर से सलाह लें.

मनोज ठाकुर
feedback@chauthiduniya.com

A fastest Growing Company
Maker Of
OFLOGYL-OZ
Ofloxacin & Ornidazole Tablets/Sus.
LIV-GUARD
100% Liver Tonic With Kalmegh 100mg Syp/Drop
MEME
Multi Vitamins, Zinc & L-Lysine Drops
ARIZYME SYP.
Digestive enzymes (pine apple Flavour)
A-COLIC
Simethicone Emulsion, Dill Oil,Fennel Oil Drops
AREX
Dextromethorphan,Guaiphenesine Ammonium Chloride Cough Syp.
ariskon Pharma Pvt.Ltd.

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू।
Contact : 9386595926, 9334115955

उपेंद्र ने ताक़त का अहसास कराया

पूरे बिहार से जुटे कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के हटने तक संघर्ष जारी रहेगा. दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक उनसे इसी आक्रामकता की उम्मीद लिए पटना आए थे. समर्थकों को लग रहा था कि फिर कहीं एक बार टाल-मटोल वाला रुख़ न हो जाए.

चार सितंबर को खचाखच भरा पटना का श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल और इससे कहीं ज़्यादा इस हॉल से बाहर खड़े लोग उपेंद्र कुशवाहा की ताक़त का अहसास करा रहे थे. कानों को भेद देने वाले नीतीश विरोधी नारों से जब हॉल गूंजने लगा तो लगा कि सूबे में लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, पर विकल्पहीनता के कारण उनकी जुबान बंद है. पूरे बिहार से जुटे कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के हटने तक संघर्ष जारी रहेगा. दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक उनसे इसी आक्रामकता की उम्मीद लिए पटना आए थे. समर्थकों को लग रहा था कि फिर कहीं एक बार टाल-मटोल वाला रुख़ न हो जाए. लेकिन इस बार भारी भीड़ देख उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि बिंदुवार अपने समर्थकों के सारे सवालों का जवाब दे दिया. कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और इससे मैंने सबक़ सीख लिया है. इस जीवन में तो उनसे मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि नीतीश कुमार के हटने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. दरअसल, पूरे सम्मेलन के दौरान कुशवाहा कार्यकर्ताओं के मूड को पढ़ते रहे. मंच पर बोलने वाला हर शख़्स भी कुशवाहा से आरपार की लड़ाई का ऐलान सुनना चाहता था. कुशवाहा ने कहा कि लड़ाई शुरू हो गई है और यह मुक़ाम तक पहुंचेगी. जल्दबाज़ी में कोई ग़लत क़दम नहीं उठाया जाएगा. नीतीश कुमार के हर क़िले को बेहतर रणनीति और संगठन की मदद से ध्वस्त कर दिया जाएगा. बिहार नव निर्माण मंच नीतीश के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वाले हर शख़्स के साथ खड़ा है. पटना में जुटी भीड़ से गदगद उपेंद्र कुशवाहा ने गांधी मैदान में बड़ी रैली का ख़ाका खींचना शुरू कर दिया है. असल में कुशवाहा यह दिखाना चाहते हैं कि वह केवल कुशवाहा समाज के नेता नहीं हैं. श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में सभी वर्गों की भागीदारी ने यह बात साबित भी कर दी. गांधी मैदान की रैली में कुशवाहा इसी राजनीतिक सच्चाई पर मज़बूत मुहर लगवाना चाहते हैं. इस बीच सभी ज़िलों में जागरण अभियान चलता रहेगा. कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जदयू का आरजेडीकरण हो रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी या परिवार के लिए टिकट नहीं मांगा था, बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कहा था. लेकिन इस मांग पर मुझे दलविरोधी मान लिया गया. संघर्ष के दिनों में जिन्होंने गालियां दीं आज वही दरबार के रत्न बने हुए हैं. उन्होंने अपनी पुरानी मांग दोहराई कि मंत्रियों की संपत्ति के स्रोत का भी खुलासा होना चाहिए. सम्मेलन में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य में जाली डॉक्टर और जाली शिक्षक बहाल हो रहे हैं. सम्मेलन में रामबिहारी सिंह की अनुपस्थिति पर खुसुर-फुसुर जारी थी, पर बाद में पता चला कि वह राजद के कार्यक्रम में फारबिसगंज गए हुए थे. बिहार नवनिर्माण मंच के इस कार्यक्रम से दूसरे दलों के नेताओं ख़ासकर कुशवाहा नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है.

सरोज सिंह
feedback@chauthiduniya.com

ग़रीबों का आशियाना
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा

राजेश सिन्हा

नीतीश सरकार द्वारा भूमिहीन महादलितों के साथ-साथ ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन गुज़र बसर कर रहे लोगों को सरकारी स्तर से ज़मीन उपलब्ध कराकर आशियाना सजाने का सपना तो दिखाया गया था, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों और बिचौलियों के कारण कई परिवारों का सपना साकार नहीं हो पा रहा है. कहीं लोगों को भूमि और इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर जमकर चूना लगाया गया तो, कहीं उन्हें विभिन्न नदियों के गर्भ में पल रही ज़मीन उपलब्ध कराकर रोने के लिए मजबूर कर दिया गया. पीड़ित परिवार के लोगों ने कई बार पदाधिकारियों के कार्यालय की चौखट चूमी, लेकिन उनकी आवाज़ नक्कारख़ाने में तूती की आवाज़ साबित होकर रह गई. चौथी दुनिया की पड़ताल में कई हैरतअंगेज़ कारनामे सामने आए. खगड़िया ज़िले के ओलापुर गंगौर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2008-09 में तीन सौ लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया था. लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही कहें या बिचौलियों की करतूत, लाभुकों द्वारा योजना का लाभ लेने के समय दिए गए इक़रारनामे में ज़मीन का ब्योरा ही नहीं दिया गया. इतना ही नहीं वित्तीय वर्ष 2009-10 में भी लगभग छह दर्जन महादलितों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया. इनमें भी कई ऐसे हैं जिनकी ज़मीन का विवरण या तो फ़र्ज़ी है या उस ज़मीन पर उनका क़ब्ज़ा ही नहीं है. इसके कारण ऐसे परिवारों के लोग अपने लिए इंदिरा आवास तो नहीं बना पाए, अब ऐसे लााभुकों की गर्दन पर तलवार भी लटकने लगी है. क्योंकि इंदिरा आवास की राशि किसी दूसरे मद में ख़र्च हो गई. अब इंदिरा आवास का निर्माण आख़िर होगा कैसे? इस तरह की अनियमितता सामने आने के बाद ग्रामीण विकास विभाग पटना के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) ने 6 जुलाई 2011 को ही विभागीय आदेश के विपरीत इंदिरा आवास योजना का लाभ देने संबंधित मामले की जांच का ज़िम्मा जिलाधिकारी को सौंपा था. जिलाधिकारी द्वारा इस मामले की किस सांचे में जांच हो रही है या इसे किस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यह तो वही जानें, लेकिन सुलगता सवाल यह है कि लाभुकों के इक़रारनामे में विवरण नहीं था या अगर विवरण फ़र्ज़ी था तो फिर इंदिरा आवास का लाभ उन्हें क्यों दिया गया.

अधिकांश महादलित परिवार अशिक्षित हैं, ऐसे में वह सरकारी प्रावधान को कैसे समझें और नियम क़ानून के तहत विवरणी भरकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष कैसे जमा कराएं. इस मामले में कहीं न कहीं रुपये कमाने की चाहत में बिचौलियों ने महादलितों को मूर्ख बनाया और पैसा पाकर संबंधित पदाधिकारियों ने लाभुकों द्वारा जमा किए गए ज़मीन के विवरण पर ग़ौर करना मुनासिब नहीं समझा. लक्ष्य प्राप्ति की चाहत में संबंधित पदाधिकारी ने लाभुकों के काग़ज़ात पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर कर दिए. अब जब बात सामने आई है तो वर्तमान प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के सिर ठीकरा फोड़ रहे हैं. वर्तमान प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की ग़लती के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है. इस मामले को कुछ देर के लिए अगर नज़रअंदाज़ कर दिया जाए तो भी ऐसे कई मामले सामने आते जा रहे हैं, जिससे प्रखंड विकास कार्यालय के पदाधिकारियों का दामन दाग़दार होता दिख रहा है. शायद यह कम पढ़े-लिखे लोगों को भी मालूम है कि भूदान की ज़मीन को न ही ख़रीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है. भूदान की ज़मीन का पर्चा भूमिहीनों को देकर बसाए जाने का प्रावधान है. बावजूद इसके करोड़ों की भूदान की ज़मीन को बागमती नदी के अस्तित्व की ज़मीन से अदल-बदल कर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने एक अनोखा कीर्तिमान बनाया है. दरअसल वर्षों पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से सटे परमानंदपुर मौजे की करोड़ों की ज़मीन को उजियार साह ने भूदान घोषित कर दान कर दिया था. कई भूमिहीनों को पर्चा देकर इस ज़मीन पर आशियाना सजाने का आदेश भी दे दिया गया. जब इस ज़मीन की क़ीमत में काफ़ी उछाल आ गया तब उजियार साह के पोते ने अंचलाधिकारी को मेल में लेकर इस ज़मीन की अदल-बदल बागमती नदी की ज़मीन से करा ली. हद तो तब हो गई जब अंचलाधिकारी ने खगड़िया अंचल की वाद संख्या 05.10.11 का निष्पादन करते हुए पत्रांक 581 दिनांक 03.03.11 के माध्यम से उजियार साह के पोते के नाम से भूदान की उक्त ज़मीन की नई जमाबंदी क़ायम करने का आदेश दे दिया. इसके पूर्व ही परमानंदपुर मौजे के राजस्वकर्मी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जमाबंदी नंबर 99 का राजस्व अभिलेख से मिलान करने पर यह प्रमाणित हुआ है कि हाजीपुर मौजा परमानंदपुर निवासी स्वर्गीय रामस्वारथ साह के पुत्र स्वर्गीय उजियार साह ने तौजी नंबर 525, थाना नंबर 271, खाता नंबर 102, खसरा 112 की चार एकड़ आठ कट्ठा 19 धूर ज़मीन भूदान में दी थी. लेकिन भूदान की ज़मीन की अदल-बदल फरकिया स्थित बागमती की ज़मीन अर्थात थाना नंबर 189, खसरा नंबर 02,08 एवं 98 से कर ली गई है. ज़िला निबंधन कार्यालय का अभिलेख भी इस बात की गवाही दे रहा है कि थाना नंबर 189, खसरा नंबर 02,08 एवं 98 बागमती के अस्तित्व की ज़मीन है. डीसीएलआर पुष्पेश कुमार का कहना है कि भूदान की उक्त ज़मीन एवं बदलेन की गई ज़मीन के बीच कोई तालमेल ही नहीं है. तत्कालीन डीसीएलआर के ग़लत निर्णय का अंचाधिकारी ने नाजायज़ फायदा उठाया है. बावजूद इसके यह मामला गंभीर जांच का विषय है. जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का कहना था कि मामले की तफ्तीश की जा रही है. उधर, एक मामले में नामज़द अभियुक्त बनने के बाद फ़रार चल रहे अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना था कि पूर्व डीसीएलआर द्वारा पारित वाद संख्या 01.05. 2006 के आलोक में इस तरह का आदेश दिया गया. हालांकि लूट का यह खेल सिर्फ़ खगड़िया प्रखंड में ही नहीं खेला गया है. जानकारों का कहना है कि खगड़िया ज़िले के सभी प्रखंडों सहित अन्य ज़िलों में भी इस प्रकार से ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन गुज़र बसर कर रहे लोगों सहित महादलितों के साथ धोखा किया गया है. ज़रूरत है ऐसे मामलों को उजागर कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की, ताकि धोखाधड़ी के शिकार लोगों को न्याय मिल सके.

feedback@chauthiduniya.com

20 करोड़ के घोटाले पर शासन चुप

रोहतास

क्षमता के अनुसार हर कोई खाने और पचाने की कोशिश करता है. घोटालों के साथ भी यहीं युक्ति लागू होती है. देश में बैठे अफ़सरशाह अगर अरबों में खेल रहे हैं तो ज़िले में लाखों का वारा न्यारा लाज़िमी है. पहले काम के बदले अनाज घोटाले में 8 करोड़ 25 लाख रुपये को घोटाला उजागर हुआ. उसके बाद विद्यालय में छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल एवं पोशाक पर 12 करोड़ की राशि का घोटाला उजागर हुआ है. दिनारा प्रखंड में सोलर लाइट योजना में 27 लाख का घोटला सामने आया. काम के बदले अनाज योजना में सवा 8 करोड़ के घोटाले पर आनन-फानन में सबसे निचले स्तर पर जविप्र दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इस घोटाले में लापरवाही करने वाले बड़े अधिकारियों के ख़िलाफ़ कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है. इस घोटाले में प्रशासन ने 400 से ज़्यादा जविप्र दुकानदारों को चिन्हित करने की बात कही है. सासाराम एवं नोखा प्रखंड के 33 जविप्र दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज भी हो गई है. इस बाबत जब उप विकास आयुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 2002-2007 के बीच ज़िले के सभी जविप्र दुकानदारों को 8 करोड़ 25 लाख की राशि बांटी गई थी, न तो वह राशि वापस मिली और न ही इसकी रिपोर्ट. इस अनियमितता में 29 जविप्र दुकानदार ऐसे हैं, जिन पर 4 लाख से ज़्यादा की राशि बक़ाया है.

इन पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. बचे हुए दुकानदारों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होंगे. डीडीसी से जब साइकिल, पोशाक एवं सोलर लाइट घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी होने से इंकार किया. उधर, जब साइकिल और पोशाक राशि वितरण की रिपोर्ट पर नज़र जाती है तो ज़िले में विद्यालयों के छात्रों के बीच बंटने वाली साइकिल एवं पोशाक राशि में लगभग 12 करोड़ रुपये का वारा-न्यारा होता दिखता है. इसमें घटिया साइकिल एवं पोशाक वितरित कर राशि उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है. यही नहीं घोटाले की प्रामाणिकता तब सामने आई, जब नोखा प्रखंड क्षेत्र में बिसेनी खुर्द स्थित आंगनवाड़ी केंद्र सं.- 77 तथा 139 पर प्रशासन ने स्वयं ही जांच कर बच्चों को दी जाने वाली पोशाक राशि में गड़बड़ी पाई. इसके आरोप में सेविकाएं चंद्रकला देवी एवं सुमन देवी पर सीडीपीओ श्वेता सिंह द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इस संदर्भ में ज़िला जन संपर्क पदाधिकारी रवि भूषण सहाय ने बताया कि जन शिकायत के आधार पर कराई गई जांच में यह अनियमितता उजागर हुई है. उधर, जिलाधिकारी अनुपम कुमार से इस मामले में ली गई जानकारी पर पता चला कि प्रशासन के पास पोशाक एवं साइकिल राशि वितरण में बड़े पैमाने पर बरती गई अनियमितता की कोई रिपोर्ट नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. दिनारा प्रखंड में विभिन्न गांवों में लगने वाली सोलर लाइट योजना की राशि लगभग 40 प्लेटों एवं बैट्रियों को गाड़ देने की रिपोर्ट प्रेषित है, जो कभी इन गांवों में पहुंची हीं नहीं.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

भूमि-अधिग्रहण पर किसान भड़के

सारण

विजयेंद्र कुमार

लगता है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर पश्चिम बंगाल के सिंगुर एवं ग्रेटर नोएडा के मामलों से सरकार अभी तक सबक़ नहीं ले पाई है. हालत यह है कि उत्तर बिहार के हाजीपुर से लेकर छपरा तक सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पर किसानों की पुश्तैनी ज़मीन के अधिग्रहण का जो सरकारी तरीक़ा अपनाया गया है, उससे सैकड़ों किसान त्रस्त हैं. ज़िला भू अर्जन विभाग छपरा के अधिकारियों द्वारा फोरलेन सड़क बनाने की निमित सूचना प्रकाशित कर अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र उपस्थपित करने का फ़रमान जारी कर दिया गया है. इसके आलोक में किसानों ने अपनी-अपनी ज़मीन से संबंधित सभी दस्तावेज़ ज़िला भू अर्जन कार्यालय में जमा करा दिए हैं. मगर स्थिति यह है कि हाजीपुर से लेकर छपरा तक के सड़क के किनारे की दो फ़सली उपजाऊ भूमि को भू अर्जन विभाग एक फ़सली होने की बात कहकर इसके मूल्य निर्धारण में मनमानी करने का सबूत पेश कर रहा है. ऐसी हालत में जिन खेतों में किसान अबतक दो फ़सल काटते आए हैं, वे खेत विपरीत परिस्थिति में ही सही देने को तैयार तो हैं, मगर एक फ़सली होने का हर्जाना सहकर इसे देने में किसानों को भारी नुक़सान उठाना पड़ रहा है. इसकी लिखित शिकायत करने पर भी संबंधित अधिकारी किसानों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. भूमि के सर्वेक्षण काल में इन अधिकारियों ने भूमि के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तरीय मानक पर हर्जाने के साथ भूमि अधिग्रहण की बात कही थी, मगर अब ज़मीन की क़ीमत देने के समय भू अर्जन विभाग मनमानी रवैया अपनाकर बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित क़ीमत ही किसानों को देने की बात करता है. किसानों ने अपना विरोध तेज़ कर दिया है और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का मन बनाया है. किसानों के विरोधी रुख़ को देखते हुए भू अर्जन पदाधिकारी अनिल चौधरी ने सोनपुर, दिघवारा व सदर छपरा के किसानों से बात करने के लिए कई बार बैठक करने की तिथि तय की.

छपरा शहर के पूर्वी हिस्से के दिघवारा व सोनपुर इलाक़े की समस्त अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि काफ़ी उपजाऊ है, जिसमें धान व गेहूं के साथ-साथ फल व सब्ज़ियों का भी भरपूर उत्पादन होता है. ऐसी हालत में औने-पौने दाम पर सरकार द्वारा अधिग्रहण की मंशा किसानों के साथ मज़ाक़ है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि किसानों के लिए न्याय की गुहार कौन लगाएगा?

मगर ऐन मौक़े पर उक्त तिथि को बैठक स्थगित कर देने की बात बताई जाती है, जिससे किसानों के बीच असंतोष पनप रहा है. अगर भू अर्जन विभाग के आला अधिकारियों ने किसानों की बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार न किया तो सारण के किसान सड़क निर्माण के कार्यों को बाधित करने के मूड में भी आ सकते हैं. सच्चाई यह है कि छपरा शहर के पूर्वी हिस्से के दिघवारा व सोनपुर इलाक़े की समस्त अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि काफ़ी उपजाऊ है, जिसमें धान व गेहूं के साथ-साथ फल व सब्ज़ियों का भी भरपूर उत्पादन होता है. ऐसी हालत में औने-पौने दाम पर सरकार द्वारा अधिग्रहण की मंशा किसानों के साथ मज़ाक़ है. इस मामले को लेकर भोजपुरी किसान विकास मोर्चा के सदस्यों ने किसानों को वास्तविक मूल्य दिलाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन अगर किसानों का गुस्सा फूटा तो यह क्षेत्र सिंगुर व ग्रेटर नोएडा की घटना दोहरा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

अनिल सुलभ को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर स्थानीय डॉ. ज़ाकिर हुसैन संस्थान एवं आईआईबी एवं सभागार में आयोजित साधना का सम्मान कार्यक्रम में प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के संस्थापक-निदेशक प्रमुख डॉ. अनिल सुलभ को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर ग्यारह अन्य विद्वानों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इनमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ. एस.एन. गुहा, संता आचार्य सुदर्शन, डॉ. क्यू हैदर, प्रो. डॉली सिन्हा, मृदजा प्रकाश, डॉ. जनार्दन, डॉ. पी दास तथा डॉ. वी जहां शामिल हैं. सभी पुरस्कत विद्धानों एवं विदूषियों को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने धवल चादर पुष्प-गुच्छ स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर बिहार सरकार के प्रधान सचिव विजय प्रकाश प्रो. चंद्रवती अवकाश प्राप्त भाप्रसे अधिकारी बच्चा ठाकुर तथा अधिवक्ता हरि मोहन मिश्र समेत बड़ी संख्या में विद्धतजन, शिक्षक एवं छात्रगण उपस्थित थे. सभा की अध्यक्षता प्रो. उत्तम कुमार सिंह ने तथा अतिथियों का स्वागत एवं मंच-संचालन डॉ. अक्षय कुमार नायक ने किया.

होली डे होम्स का भूमि पूजन संपन्न

रांची की सुप्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी यशराज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट होली डे होम्स की विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुई. यशराज इंटरप्राइजेज एन एच 33 पर रांची की सबसे बड़ी टाउनशिप लेकर आए हैं, जो सर्वसुविधा युक्त विश्वस्तरीय टाउनशिप होगी. अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझते हुए यशराज ने इस टाउनशिप में हर वर्ग का ख्याल रखा है. जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, प्ले स्कूल, चिल्ड्रन पार्क, गार्डन व चौड़ी सड़कें आदि शामिल हैं. जन्माष्टमी के अवसर पर इस टाउनशिप की बुकिंग भी शुरू की गई है. भूमि पूजन में वृंदावन से आए भागवत कथा वाचक बाल व्यास श्री श्री भूपेंद्र शास्त्रीजी एवं व्यास श्री श्री सुनिल जी ने विधिवत पूजा कार्य संपन्न कराया. पूजन में जजमान यशराज के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.के.मिश्रा भी रहे.

सच्चाई की जीत : जे.एन. सिंह

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन (सेंट्रल) के चीफ सेक्रेटरी एवं पटना सर्किल के महासचिव जे. एन. सिंह को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद बेउर जेल से रिहा कर दिया गया. एसबीआई के प्रधान कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर कई कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे. बैंक के गेट पर पहुंचते ही जे. एन. सिंह ज़िंदाबाद के नारे लगने लगे. माला पहनाकर स्वागत करने के लिए होड़ मच गई. कर्मियों ने मिठाइयां खिलाकर एक-दूसरे का स्वागत किया. इस अवसर पर सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से ज़मानत मिलने का फ़ैसला सच्चाई की जीत है. वे न्यायालय पर हमेशा भरोसा करते हैं. सच्चाई को अल्पकाल के लिए झुठलाया जा सकता है, मगर हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन परिवार से ज़्यादा अपने संगठन तथा सदस्यों के हित में समर्पित किया है. अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा से अपने संगठन तथा बैंक कर्मियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए तत्पर रहा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जयनगर-काठमांडू रेल परियोजना खटाई में

अफ़ज़ल ईमाम, मुन्ना

उत्तर बिहार से सटी भारत-नेपाल की सीमा पर स्थित जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम तक विगत कई वर्षों से रेलवे ट्रैक पर नेपाली ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल आज तक नहीं पहुंची है. काठमांडू पहुंचने के लिए अभी भी हवाई मार्ग या बस का ही सहारा लेना पड़ता है.

सुरक्षा और पर्यटन के दृष्टिकोण से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल चले, इसी उद्देश्य को लेकर 21 वर्ष पूर्व भारत के तत्कालीन रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने जयनगर से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने की घोषणा की थी. लेकिन समय बीतने के साथ अब ऐसा लग रहा है कि यह योजना खटाई में पड़ गई है. यह परियोजना पूरी हो जाए तो काठमांडू की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी. इस परियोजना के लिए वर्ष 1990 में भारतीय रेलवे सर्वेक्षण दल ने नेपाल में रेल लाइन बिछाए जाने संबंधी जांच पड़ताल भी की थी, किंतु उसे आज तक धरातल पर नहीं उतारा जा सका, जबकि रेल मंत्रालय को जांच रिपोर्ट भी वर्षों पूर्व मिल चुकी है. ताज्जुब की बात यह है कि इस रिपोर्ट पर अभी तक अमल नहीं किया गया है. दूसरी ओर रेल विभाग ने खानापूर्ति के लिए यदा-कदा समस्तीपुर रेल मंडल मुख्यालय में दोनों देशों के रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुप्पी साध ली है. ज्ञात हो कि भारत-नेपाल के साथ पारगमन संधि का मसला सुलझाने के बाद ही भारत ने जयनगर से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई थी, ताकि जयनगर से आगे भारतीय रेल को काठमांडू तक ले जाया जा सके. किंतु अब ऐसा लगता है कि भारत की अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी खटाई में पड़ गई है. यह रेल परियोजना क्यों अधर में लटक गई, बिहारवासियों के लिए यह अनसुलझा प्रश्न बनकर रह गया है. इस संदर्भ में रेलवे सूत्रों का कहना है कि यह योजना वर्ष 1990 में बनी थी. जब योजना की सुगबुगाहट हुई तो उस समय न केवल नेपाल के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने भारत सरकार की इस योजना का स्वागत किया था, बल्कि भारतवासियों ने भी सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम के प्रति सरकार की सहानुभूति को सराहा था. इससे भारतीय रेलवे की आय में वृद्धि की भी आशा व्यक्त की गई थी.

उस समय भारत सरकार भी काफ़ी उत्सुक दिख रही थी तथा 16 दिसंबर 1990 को भारतीय रेलवे सर्वेक्षण दल जनकपुर धाम गया था. रेल लाइन बिछाए जाने संबंधी कई तरह के सर्वेक्षण भी किए गए थे. सर्वेक्षण दल ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में राय व्यक्त करते हुए जयनगर से जनकपर, हिटौरा, मैली-टिस्टू, पाले और चितलो मैले होते हुए काठमांडू के मार्ग को हर दृष्टि से रेल चालने के लिए उपयुक्त बताया था. ज्ञात हो कि नेपाल का हिटौरा एक औद्योगिक क्षेत्र है, जबकि जनकपुर में रूस की ओर से निर्मित एक सिगरेट फैक्ट्री के अतिरिक्त कई छोटे-बड़े उद्योग भी हैं. इस मार्ग में कम ऊंचाई की पहाड़ी चितलो मैली है, जिसे समतल बनाने में ख़र्च भी कम आएगा. साथ ही काठमांडू की दूरी भी कम हो जाएगी. ग़ौरतलब है कि सड़क मार्ग से जनकपुर की दूरी क़रीब 250 किलोमीटर है, जबकि रेलमार्ग से इसकी दूरी घटकर 150 किलोमीटर ही रह जाएगी. इस बातकर उल्लेख भारतीय रेलवे सर्वेक्षण दल ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया था. वर्ष 1990 में भारत सरकार के इस निर्णय से नेपाल सहित भारतवासियों में भी उमंग की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन इस योजना के खटाई में पड़ जाने से लोगों में काफ़ी आक्रोश है. तत्कालीन रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस के बाद जो भी रेलमंत्री बने उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया. लालू प्रसाद यादव ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया. ममता बनर्जी को तो पश्चिम बंगाल से फ़ुर्सत ही नहीं रही. ऐसा लगता है कि बिहार की कई रेल परियोजनाओं की तरह जयनगर-काठमांडू रेल परियोजना भी अधर में लटक गई है.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

बाघों के मारे जाने से यहां के लोगों को लग रहा है कि अब जंगल के जीवन में प्रकृति चक्र टूट गया है.

बाघों का जीवन ख़तरे में

प्रो. अरविंद नाथ तिवारी

देश की प्रख्यात वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में बाघों का जीवन अब सुरक्षित नहीं रह गया है. इस परियोजना में हर वर्ष बाघों की संख्या घट रही है. 1990 में इस परियोजना में बाघों की संख्या 81 थी, जो बीस वर्षों के अंतराल में घटकर मात्र आठ रह गई है. संख्या घटने का कारण बाघों के अंगों की तस्करी होना और ग्रामीण क्षेत्र में भूख मिटाने के दौरान बाघों को ग्रामीणों द्वारा लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मारा जाना है. बाघों की घटती संख्या को लेकर जहां सरकारें चिंतित होकर काग़ज़ी कार्यवाही कर तथा बाघ वर्ष मनाकर अपनी ज़िम्मेदारी की इतिश्री कर रही हैं, वहीं परियोजना के बाबू और अधिकारियों के घर अकूत संपत्ति से भरते जा रहे हैं. बाघों के मारे जाने से यहां के लोगों को लग रहा है कि अब जंगल के जीवन में प्रकृति चक्र टूट गया है. यही कारण है कि एक दशक के भीतर एक हज़ार से ज़्यादा बाघों का जीवन भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है. बाघों के अंगों की तस्करी के मामले में दुनिया के तीन चर्चित देशों में भारत भी शामिल है.

केंद्र सरकार ने बाघों के जीवन, रखरखाव और समृद्धि के लिए वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना को 1994 में परियोजना का स्वरूप दिया. परियोजना बनाए जाने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि बाघों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी. 880 वर्ग किलोमीटर परियोजना परिधि में 335 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है, 545 वर्ग किलोमीटर बाघों के रहने के लिए सुरक्षित क्षेत्र है. 1990 के दशक में बाघों की संख्या परियोजना में 80 थी, जो घटकर 2002 में 56, 2003 में 52, 2005 में 40, 2007 में 18 और अब 2010 के अप्रैल माह के बाद से मात्र 8 रह गई है. सभी आंकड़ों की पुष्टि वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने की है. बाघों की ताज़ा गणना गत वर्ष 13 मई और 14 मई को कैमरा के ट्रैप विधि से हुई है. बुद्धिजीवियों ने अचानक इस हद तक संख्या के घट जाने के लिए ग्रामीणों, परियोजना के अधिकारियों और सरकार को ज़िम्मेदार माना है. बुद्धिजीवियों का कहना है कि सरकार क़ानून तो बनाती है, पर तस्करी को रोकने के लिए तस्करों पर क़ानून का डंडा नहीं चला पाती है. तस्करों के साथ-साथ परियोजना के बाबू और अधिकारी भी इसका लाभ उठाते हैं. दूसरी तरफ़ परियोजना में रहने वाले बाघों के रखरखाव और भोजन पर पदाधिकारियों के ध्यान न देने से बाघ भोजन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ़ जाते हैं. यहां बार-बार बाघों के अटैक करने से ग्रामीण तंग आकर उन पर जानलेवा हमला बोल देते हैं. वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में 2008 के जुलाई से सितंबर माह तक बाघ के हमले में एक महिला, एक पुरुष व एक एसएसबी का जवान मारा गया. उधर, गत वर्ष 11 अक्टूबर को दोन क्षेत्र के एक घर में बाघ ने हमला बोलकर आधा दर्जन बकरों को मार डाला और गृहस्वामी को घायल कर दिया. गत वर्ष 10 मई को उनरवा थाना क्षेत्र में साहपुर परसौनी गांव में एक बाघ ने ग्रामीण होशीला पटेल पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. बाघ ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को बुरी तरह से घायल भी कर दिया. अंत में ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बाघ को मार डाला. इसके अलावा तस्करों की गिद्ध दृष्टि भी बाघों के कम होने का एक कारण है. तस्कर बाघों को अपने जाल में फंसाकर मार डालते हैं. इसकी भनक ग्रामीणों को पहले और परियोजना के बाबू और पदाधिकारियों को बाद में लगती है. तब तक बाघों की जान जा चुकी होती है. उदाहरण स्वरूप 10 मई 2008 को मदनपुर वन क्षेत्र के नौरंगिया वन कक्ष संख्या 15 में शिकारियों ने आइरन ट्रैप में एक रायल बंगाल टाइगर को फंसा रखा था. परियोजना के बाबू और अधिकारी जब वहां पहुंचे तो बाघ कराह रहा था, किंतु ट्रेकुलर गन के अभाव में बाघ की जान नहीं बचाई जा सकी.

ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल में एक तस्कर है, जिसका संबंध देश-विदेश के तस्करों से है. तस्कर की नज़र वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना पर रहती है. परियोजना के बाबुओं और अधिकारियों से उसकी साठगांठ है. यही कारण है कि जंगल में बाघों की संख्या कम हो रही है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इस पर नियंत्रण करने के लिए 29 जुलाई 2010 को नेपाल के काठमांडू में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के डीआईजी फॉरेस्ट एसपी यादव और नेपाल के डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के गोपाल प्रसाद उपाध्याय ने मिलकर संयुक्त संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. वहीं बाघों की घटती संख्या पर चिंता ज़ाहिर करते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रैफिक ने कहा है कि जनवरी 2000 से अप्रैल 2010 तक 1220 बाघों को दुनिया भर में मारा गया है. संस्था का कहना है कि प्रत्येक वर्ष 109 से 199 बाघ मारे जा रहे हैं. भारत में बाघ के सर्वाधिक अंग 276 बरामद किए गए हैं. इसके लिए 469 से लेकर 533 बाघों को मारा गया है. 40 अंगों के चीन में बरामद होने पर 116 से 124 बाघों के मारे जाने की ख़बर है. नेपाल में 39 अंग बरामद हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि नेपाल में 130 बाघ मारे गए. भारत में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना को बाघों के रखरखाव में सबसे अच्छा माना जाता था. अब बाघों के इस आंकड़े के बाद वाल्मीकि परियोजना के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. उधर, पिछले दिनों वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के मदनपुर रेंज में स्थित गांवों में पशुओं पर बाघों के हमलों से लोगों को यह डर सताने लगा है कि बाघों का जीवन ख़तरे में है. हालांकि परियोजना के डीएफओ का कहना है कि बाघों के जीवन सुरक्षा चक्र को पहले से ज़्यादा मज़बूत किया जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

गत वर्ष 10 मई को उनरवा थाना क्षेत्र में साहपुर परसौनी गांव में एक बाघ ने ग्रामीण होशीला पटेल पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई. बाघ ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को बुरी तरह से घायल भी कर दिया. अंत में ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बाघ को मार डाला. इसके अलावा तस्करों की गिद्ध दृष्टि भी बाघों के कम होने का एक कारण है. तस्कर बाघों को अपने जाल में फंसाकर मार डालते हैं. इसकी भनक ग्रामीणों को पहले और परियोजना के बाबू और पदाधिकारियों को बाद में लगती है. तब तक बाघों की जान जा चुकी होती है.

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-

POST GRADUAGE COURSES:
- MPT Master of Physiotherapy
- MOT Master of Occupational Therapy
- MPO Master of Prosthetic & Orthotic
- MASLP Master of Audiology & Speech Language Pathology
- BPT Bachelor of Physiotherapy
- BOT Bachelor of Occupational Therapy
- BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
- BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology
- BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
- BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
- B.Ed. (Special Education)
- B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology

संस्थान द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ
- स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श
- टीकाकरण
- फिजियोथेरापी
- अकुपेशनल थेरापी
- स्पीच थेरापी
- नेत्र जाँच
- सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो,लकवा,गठिया,हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं उपचार
- हकलाना, तुतलाना सहित गूंगे-बहरों की जाँच एवं उपचार हियरिंग-एड
- मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जाँच एवं उपचार
- कृत्रिम हाथ,पैर,कैलीपर,पोलियो के जूते,वैशाखी, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण
- लाचार विकलांगों को तिपहिया-साकिल तथा व्हीलचेयर
- विकलांगों की शल्य चिकित्सा,सर्जिकल करेक्शन
- रियायती दर पर पैथोलोजिकल जाँच,एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य

1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
- DPT Diploma in Physiotherapy
- DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
- DMLT Diploma in Medical Lab. Tech
- D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
- DHM Diploma in Hospital Management
- DOTA Diploma in Operation Theater Assistant
- DECG Diploma in E.C.G.

certificate courses:
- CMD Certificate in Medical Dressing
- Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-. Send a DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2

Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same. 10+2 with science for Under Graduate & Diploma Courses. For B.Ed. Degree in any Subject.

Admission Going On...

डा. अनिल सुलभ
निदेशक-प्रमुख

फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email. iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

बी.एड. नामांकन सूचना 2011-12

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बी.एड. (नियमित) में नामांकन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

अवधि - एक वर्ष | सीट - 100 | चयन : प्रवेश परीक्षा के आधार पर

Eligibility : (a) candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent there to, are eligible for admission to the programme. b) The reservation in seats and relaxationin the qualifying marks in favour of the reserved categories shall be as per the rules of the State Govt.

आवेदन पत्र (विवरणिका के साथ) दिनांक 05 सितम्बर, 2011 से 01 अक्टूबर, 2011 तक निम्नलिखित अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है एवं आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2011 तक जमा किया जा सकता है :

1) Deptt. of Education, M.U. Campus 2) Gaya College, Gaya
3) J.D. Women's College, Patna 4) A.N. College, Patna, 5) Nalanda College, Biharsharif,
6) S. Sinha College, Aurangabad 7) Sri Arvind Mahila College, Patna

उपरोक्त अध्ययन केन्द्रों पर रूपये 800/- (सामान्य/अन्य जाति के लिए) एवं रूपये 500/- (अनुसूचित/अनु.जनजजाति के लिए) नगद या बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। जिसे Director, DDE, M.U. Bodh Gaya के नाम से देय तथा अदाकर्ता शाखा Bodh Gaya होना चाहिए। आवेदन पत्र (विवरणिका के साथ) डाक द्वारा प्राप्त करने के लिए रूपये 50/- अतिरिक्त शुल्क देय होगा। निदेशालय के website www.mudde.org, www.mudde.org.in द्वारा downloaded आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा किया जा सकता है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार

डॉ. मो. इसराईल खां
निदेशक

चौथी दुनिया

दिल्ली, 19 सितंबर–25 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

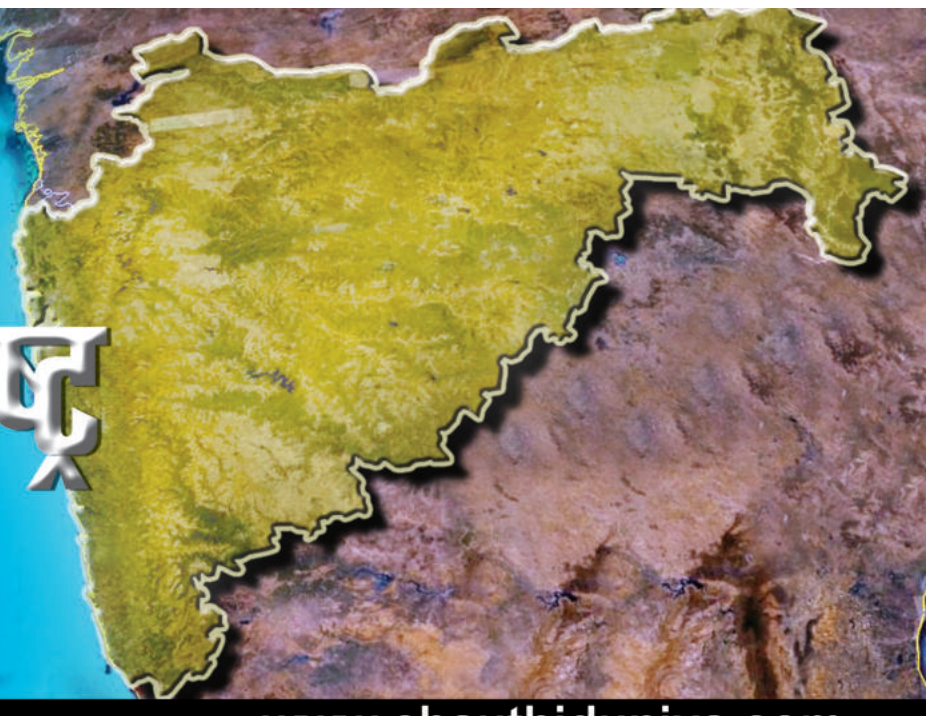

महाराष्ट्र को खोखला करता भ्रष्टाचार

अन्ना ने भ्रष्टचारियों के कारनामों को उजागर करने के लिए सबसे पहले सत्याग्रह महाराष्ट्र में ही किया था. उनके आंदोलनों की बदौलत महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना था, जिसने सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया था. इससे लोगों में भ्रष्टचार के प्रति जागरूकता भी आई और लोग अपनी शिकायतें लेकर वरिष्ठ अधिकारियों व एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी जाने लगे. भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार कर मामले भी दर्ज किए गए. इसके बावजूद भ्रष्टचार की गंगोत्री बदस्तूर बह रही है.

प्रवीण महाजन

आज भ्रष्टाचार का नाम सामने आते ही अन्ना हज़ारे की तस्वीर सामने आ जाती है. उन्होंने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ कर जहां पूरे देश में भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार किया है. वहीं दूसरी ओर यह अन्ना का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जहां से उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी, वही महाराष्ट्र, जो कि उनका गृहराज्य भी है वह आज देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बन गया है. प्रदेश में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, जिसे भ्रष्टाचार का रोग न लगा हो. हर नागरिक भ्रष्टाचार से त्रस्त है. मगर सरकार इसके आगे लाचार नज़र आती है. भ्रष्टाचार रोकने के जितने उपाय वह करती है, उन सभी उपायों पर राज्य की भ्रष्ट अफ़सरशाही पानी फेर देती है. अन्ना ने भ्रष्टाचारियों के कारनामों को उजागर करने के लिए सबसे पहले सत्याग्रह महाराष्ट्र में ही किया था. उनके आंदोलनों की बदौलत महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना था जिसने सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया था. इससे लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता भी आई और लोग अपनी शिकायतें लेकर वरिष्ठ अधिकारियों व एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी जाने लगे. भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार कर मामले भी दर्ज किए गए. इसके बावजूद भ्रष्टाचार की गंगोत्री बदस्तूर बह रही है. भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई. नतीजतन, हर माह भ्रष्टाचार के 6-7 बड़े मामले सामने आते हैं. रोज़ कोई न कोई अधिकारी-कर्मचारी एंटी करप्शन ब्यूरो की पकड़ में आ जाता है. समाजसेवी अन्ना हज़ारे के जन लोकपाल बिल को संसद में पेश किए जाने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान पर अपना अनशन तोड़ने के दो दिन बाद ही यह रिपोर्ट आई कि महाराष्ट्र देश का सबसे भ्रष्ट प्रांत बन चुका है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इसका ख़ुलासा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के हर माह तीन-चार बड़े मामले दर्ज किए जा रहे हैं. इस मामले में राजस्थान दूसरे और उड़ीसा तीसरे नंबर पर है. ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2007 में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बिहार को बताया था, लेकिन अब यह ताज महाराष्ट्र को मिल गया है. यहां आए दिन किसी न किसी बड़े नेता-अफ़सर से जुड़े घोटाले उजागर होते रहते हैं. सप्ताह-दो सप्ताह में कोई न कोई वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार होता है. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण राज्य की जनता से साफ़-सुथरा पारदर्शी प्रशासन देने का वादा करते हैं, तो वहीं इस ख़बर का आना राज्य सरकार की आंख खोल देने वाला है कि भ्रष्टाचार का अजगर किस तेज़ी से हर विभाग को अपने लपेटे में ले चुका है. राज्य सहकारी बैंक घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, टेंडर घोटाला, ज़मीन से संबंधित घोटाले तो नित्य ही सामने आ रहे हैं. इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की सबसे अधिक मार आम आदमी को भोगनी पड़ रही है. जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या कास्ट वैलिडिटी का मामला हो, अधिकारी-कर्मचारी की जेब गरम किए बिना उसका काम नहीं होता है.

राज्य में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई योजनाओं का फ़ायदा जनता को कम और उससे जुड़े अफ़सरों व कर्मचारियों को अधिक हो रहा है. केंद्र सरकार की पहल पर राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस के तहत ई-विलेज (महा ई-सेवा) योजना राज्य में लागू की है. निजी सहभागिता से संचालित होने वाली यह योजना अब तक ज़मीनी स्तर पर राज्य के अधिकारियों की उदासीनता के चलते लागू नहीं हो पा रही है. पिछले दो-ढाई साल से यह योजना अटकी पड़ी है. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 1 मई 2011 को महाराष्ट्र दिवस पर महा ई-सेवा योजना को लागू करने की घोषणा की थी. इसके 15 दिन बाद इससे संबंधित सॉफ्टवेयर का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था. यह भी बताया गया कि 15 अगस्त से महा ई-सेवा शुरू हो जाएगी. इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ही ग्रामवासियों को 70 से अधिक प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क और निर्धारित समय सीमा पर दिए जाने की सुविधा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को तहसील (तालुका) व जिलाधिकारी या कचहरी में अपने कामों के लिए बार-बार चक्कर लगाने से राहत दिलाना था, ताकि उनके समय व पैसों की बचत हो. परंतु सरकार की इस योजना को अब तक लागू नहीं किया जा सका है. प्रशासकीय विभागों के सूत्रों का कहना है कि महा ई-सेवा या ई-विलेज योजना को लागू किए जाने में सबसे बड़ी रुकावट वरिष्ठ अधिकारी हैं. ये अधिकारी नहीं चाहते कि उनकी ऊपरी कमाई पर किसी तरह का अंकुश लगे. तहसीलदारों का इस योजना के संबंध में कहना है कि जब तक कर्मचारियों को कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, तब तक इसे कैसे लागू किया जा सकेगा. कई कर्मचारियों ने बताया कि तहसीलों में आने वाले नागरिकों से क्लर्कों को हर दिन 500 से लेकर हज़ार-दो हज़ार की ऊपरी आमदनी होती है. पटवारी प्लॉट (ज़मीन) का सातबारा बनाने के लिए 200 से 500 रुपये मांगता है. नियम के अनुसार काम करेगा तो उसे मात्र 20 रुपये में करके देना होगा. ऐसे में पटवारी क्यों चाहेगा कि महा ई-सेवा लागू हो और उसको सातबारा पर होनेवाली आमदनी बंद हो. तहसीलदार किसी भी काग़ज़ात पर सिर्फ़ हस्ताक्षर करने के पैसे मांगता है. ऐसे में भ्रष्टाचार बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? इन परिस्थितियों में भले ही मुख्यमंत्री ने योजना लागू करने की घोषणा कर दी हो, पर उसका क्रियान्वयन तो राज्य की नौकरशाही को ही करना है. महा ई-सेवा योजना एक उदाहरण है कि किस तरह राज्य में भ्रष्ट नौकरशाही जनहित में लागू की गई योजनाओं को अपना बंधक बना लेती है. ऐसी सैकड़ों योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं. इन हालात में यदि महाराष्ट्र को देश में भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल बताया गया तो आश्चर्य की क्या बात है. इससे तो यही लगता है कि सत्ताधीश और अफ़सरशाह मिलकर राज्य की जनता को ठग रहे हैं, क्योंकि मंत्रीगण विधानसभा व विधान परिषद में योजनाओं के लागू होने की घोषणा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं. उसके बाद योजना ज़मीनी स्तर पर कितनी आगे बढ़ी, इसकी हक़ीक़त जानने की वे स्वयं कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि नौकरशाहों की रिपोर्ट पर निर्भर रहते हैं.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2000 से 2009 तक महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार संबंधी 4566 शिकायतें प्राप्त हुईं. 2009 में 476 शिकायतें दर्ज कराईं गई थीं. उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं. राज्य में हर साल औसतन 450 से 460 शिकायतें भ्रष्टाचार की मिलती हैं. इनमें सर्वाधिक शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित होती हैं. राजस्व विभाग के बाद शिकायतें स्कूलों व कॉलेजों के संबंध में आती हैं. राज्य के गृहविभाग से संबंधित शिकायतें भी बड़ी मात्रा में नागरिकों द्वारा की जाती हैं. खास बात यह है कि ज़मीन, मकान और जाति प्रमाण पत्र के लिए सबसे अधिक रिश्वत मांगने के मामलों में तेज़ी से बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. ब्यूरो ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इन मामलों पर यह मान कर चलिए कि यदि एक शिकायत मिली है तो 20 शिकायतें दबा दी गई हैं. यह एक कड़वी सच्चाई है. ब्यूरो ने सिर्फ़ सरकार द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई है. असलियत इससे भी अधिक भयावह है. भ्रष्टाचार की लाखों शिकायतें दर्ज ही नहीं कराई जाती हैं. लोग शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि शिकायत करने के बाद उसका काम होता नहीं है. उलटा उसे प्रक्रियागत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. इसका ताज़ा उदाहरण हैं बाबा रामदेव, अन्ना टीम के अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलने पर उनके ख़िलाफ़ सरकार ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी. जब इतने बड़े लोगों को सरकार नहीं बख्श रही है तो आम आदमी की क्या बिसात कि वह सरकार के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुंह खोले. ऐसे में आम आदमी की शिकायत कराने के बाद भी अधिकतर भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी साफ़ बचकर निकल जाते हैं या उन पर कार्रवाई ही नहीं की जाती है. राज्य में 2009 में भ्रष्टाचार की 473 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनके आधार पर 647 लोगों की जांच होनी थी. मगर प्रत्यक्ष रूप में 137 लोगों को ही जांच के बाद दोषी पाया गया और गिरफ्तार मात्र 38 को किया गया. इसी तरह वर्ष 2010 में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायतें आईं, पर आरोप सिद्ध हो सका मात्र 28 लोगों पर. इसकी वजह पर प्रकाश डालते हुए फोरम फोर इपेक्टिवनेस एंड अकाउंटबिलिटी के सदस्य मिलिंद कोटक बताते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी अपने बचाव में नामी-गिरामी वकील अदालत में खड़ा कर बच निकलते हैं. सरकारी वकील पीड़ित का पक्ष प्रभावी तरीक़े से अदालत के समक्ष नहीं रख पाते हैं. दूसरी ओर पीड़ित पक्ष अलग से वकील रखने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है. इससे भ्रष्टाचारियों को कोई भय नहीं लगता है. वहीं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के पुलिस उपमहासंचालक निकेत कौशिक बताते हैं कि सिर्फ़ मुंबई में ही भ्रष्टाचार की कम से कम हर वर्ष क़रीब डेढ़ सौ शिकायतें मिलती हैं, पर मुश्किल से 60 से 65 प्रतिशत दोषियों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई हो पाती है. अधिकांश मामलों में सरकारी काम करने के लिए अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने की बात सामने आती है. हम हर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हैं. इसके लिए जनता को जागृत करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है. नागरिकों को भ्रष्ट व रिश्वतख़ोर अधिकारियों की शिकायत करने के लिए मोबाइल वैन, इंटरनेट पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा हमारे विभाग ने शुरू की है. संभवतः यही कारण है महाराष्ट्र भ्रष्टाचार के मामले में पहले क्रमांक पर आया है. मगर कौशिक की बात से यह लगता है कि उनके विभाग की सक्रियता के बाद भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं कसी जा सकी है.

यह समझने वाली बात है कि क्यों टाटा उद्योग समूह पश्चिम बंगाल छोड़कर नैनो का प्रोडक्शन करने के लिए पहले महाराष्ट्र आया और दो-चार दिन में ही गुजरात चला गया. इसी तरह विश्व प्रसिद्ध कार बनाने वाली फोर्ड कंपनी ने अपनी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए महाराष्ट्र का चयन किया था, पर जब क़रार की बात आई तो वह भी गुजरात चली गई. बताया जाता है कि यहां के उच्च पद पर बैठे अधिकारी इन कंपनियों से बातचीत के दौरान अपना हिस्सा भी चाहते थे. इसलिए उक्त कंपनियों ने महाराष्ट्र को छोड़ना ही उचित समझा. इससे यह पता चलता है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार का दीमक किस क़दर नुक़सान पहुंचा रहा है. आख़िर राज्य में उद्योगपति अपना व्यवसाय शुरू करने से क्यों हिचकते हैं? जो उद्योगपति पहले से यहां थे उन्होंने भी धंधा समेट कर राज्य से पलायन करना ही उचित समझा. आज सरकार का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो. भ्रष्टाचार के चलते ही राज्य के बड़े शहरों में भू-माफ़िया, तेल माफ़िया, कोयला माफ़िया, अनाज माफ़िया, शराब माफ़िया और न जाने कितने गिरोह जन्म ले रहे हैं. माफ़िया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि एक राजपत्रित अधिकारी को भी राह चलते पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है. कार्रवाई करने गए पुलिस दल के ऊपर हमला कर दिया जाता है. सरकार सिर्फ़ कार्रवाई करने की घोषणा करती है या आश्वासन देती रहती है. समस्या का कोई समाधान होता दिखाई नहीं देता है, बल्कि वह और जटिल होती जाती है. इसकी वजह तो यही नज़र आती है कि सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की इच्छाशक्ति का अभाव है. यहां ध्यान दिला दें कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के कई सदस्यों पर भी विविध घोटालों में शामिल होने का आरोप जब तब लगता रहता है, पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार हों या शिवाजीराव मोघे हों, नितिन राउत हों या विलासराव देशमुख सभी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त नज़र आते हैं. लोगों का मानना है कि आबकारी विभाग, यातायात विभाग, राज्य का पुलिस महकमा, राजस्व विभाग 70 प्रतिशत से अधिक भ्रष्ट है. आदिवासी विकास विभाग व शिक्षा विभाग 50 से 60 प्रतिशत तक भ्रष्ट है. कहने का मतलब यह है कि मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायतें और शासन-प्रशासन तक में भ्रष्टाचार व्याप्त है. इस भ्रष्टाचार की दीमक से राज्य की जनता परेशान है. मुख्यमंत्री चव्हाण व अन्य मंत्री भले ही भाषणों में राज्य की जनता से पारदर्शी प्रशासन देने का वादा करते हों, पर उनके यह वादे झूठे साबित हो रहे हैं. महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार का ऐसा रोग लग गया है जिससे जनता परेशान है.

गृह मंत्रालय से जानकारी नहीं मिली

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में जारी किए गए आंकड़ों के संबंध में जब राज्य के गृह मंत्रालय में फोन कर अधिकारियों-कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो कोई जानकारी देने को तैयार नहीं था. सचिव सारंगी के पीए/पीआरओ से संपर्क किया तो बताया गया कि सचिव साहब सरकारी काम से पूना गए हैं. भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी किससे मिलेगी, पूछे जाने पर एंथोनी ने उपसचिव चव्हाण का नंबर दिया. उस पर संपर्क करने पर सबसे पहले एक महिला ने फोन उठाया और उसने बताया कि वह उधर से गुज़र रही थी तो फोन बज रहा था इसलिए उठा लिया. फिर दूसरी बार फोन किया तो उपसचिव चव्हाण सचिव के पास गए हैं, यह बताया गया. एंथोनी से पुनः संपर्क करने पर उन्होंने उपसचिव चव्हाण का मोबाइल नंबर दिया, जो बंद था. तीसरे दिन पुनः मंत्रालय में फोन करने पर जाधव नाम के चपरासी ने फोन उठाया और बताया कि साहब जगह पर नहीं हैं. मज़े की बात यह है कि फोन करने पर वहां से कर्मचारी पंद्रह-बीस मिनट टालमटोल करते रहे. अंततः कॉल कट करना ही मुनासिब लगा. अब यदि कोई सूचना या आंकड़े ग़लत चले जाते हैं तो मंत्रियों-अधिकारियों को शिकायत रहती है कि ग़लत जानकारी छापी गई. मंत्रालय में फोन करो तो कोई सूचना देने को तैयार नहीं. ऐसा लगता है कि मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों को मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र में धूमधाम से मना गणेश उत्सव

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अपनी पत्नी सत्वशिला चव्हाण के साथ अपने निवास स्थान वर्षा में गौरीपुत्र गणेश की आरती करते हुए.

नागपुर स्थित गणेश कॉलोनी प्रतापनगर में बाल गणेशोत्सव मंडल, इनसेट में अध्यक्ष विनोद पांडे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अपने आवास भागीरथी भवन में पत्नी अमिता चव्हाण, पुत्री श्री जया व सुजया के साथ गजानन की पूजा-अर्चना करते हुए.

महाराष्ट्र के उद्योगमंत्री नारायण राणे कणकवली स्थित अपने आवास में स्थापित गणपति की पूजा करते हुए, उनके साथ मौजूद हैं उनकी पत्नी नीलम राणे, पुत्र नीलेश राणे और नंदिता राणे.

पुणे गणेशोत्सव का उद्घाटन करते फिल्म निर्माता सुभाष घई एवं नृत्य पेश करतीं अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी.

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह के बांद्रा स्थित आवास पर सांसद एकनाथ गायकवाड़ श्री गणेश की पूजा-अर्चना करते हुए.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे सोलापुर स्थित अपने फार्म हाउस में विधायक पुत्री प्रणिता और पत्नी उज्जवला के साथ विनायक की पूजा करते हुए.

सार्वजनिक निर्माण कार्यमंत्री छगन भुजबल मांझगांव स्थित गणेशोत्सव में सपरिवार श्री गणेश की पूजा करते हुए.

कंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख मुंबई स्थित वर्ली अपने आवास पर पत्नी वैशाली, पुत्र अमित और पुत्रवधू अदिति के साथ पूजा करते हुए.

भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे मुंबई स्थित वर्ली अपने आवास पर सपत्नीक क्षी गणेश की पूजा-अर्चना करते हुए.

नागपुर स्थित धंतोली में श्री अष्टविनायक बहुउद्देशीय संस्था, इनसेट में अध्यक्ष संजीत जैस्वाल.

नागपुर स्थित धरमपुर झंडा चौक में स्थापित भगवान गणेश की 21 फुट ऊंची प्रतिमा.

नागपुर की विधायक कुंभारे अपने परिजनों के साथ श्री गणेश की पूजा-अर्चना करते हुए.

पुणे के मशहूर सेठ दगडू हलवाई के श्री गणेश.

गौरीनंदन गणेशमंडल परतवाड़ा.

नागपुर स्थित गरूड़ खांव रोड महाल में श्री गणेश मंडल, इनसेट में अध्यक्ष सलिल मुले.

तिलकनगर नागपुर स्थित प्रभाकर वर्धने के घर में महालक्ष्मी की प्रतिमा.

नागपुर स्थित हिलटॉप में एकता गणेशोत्सव मंडल.

नागपुर स्थित नेताजी मार्केट सीतावर्डी में विराजमान गणेश जी, इनसेट में अध्यक्ष राजेश यादव.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, राणा प्रताप नगर, नागपुर.

नागपुर स्थित इतवारी तीन नल चौक पर श्री तरुण बालमित्र गणेशोत्सव मंडल, इनसेट में अध्यक्ष नितिन सारोकर.

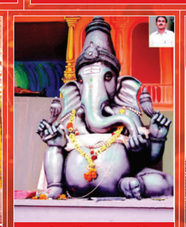

हिलटॉप स्थित गणेश मंडल में पांच हाथियों पर विराजमान गणेशजी की आकर्षक प्रतिमा.

कारपोरेशन कॉलोनी गणेशोत्सव मंडल, इनसेट में अध्यक्ष अशोक चौधरी.

नागपुर महाल स्थित गुरुजी के अखाड़ा में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा इनसेट में अध्यक्ष सोहम मांदककर.

नागपुर स्थित इंद्रप्रस्थ नगर निवासी संजय जोशी के घर में विराजमान महालक्ष्मी.

नागपुर के स्वाबलंबी नगर स्थित पूर्व ज़िलाधिकारी विनायक राव उपाध्ये के आवास पर स्थापित महालक्ष्मी की प्रतिमाएं.

नागपुर के रामनगर निवासी अजय डबीर के घर में स्थापित महालक्ष्मी की प्रतिमा.

हिलटॉप गणेश मंडल में बालाजी के रूप में विराजे भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा.

नागपुर स्थित हिलटॉप गणेश मंडल में दगड़ू महाराज की आकर्षक मूर्ति.

बाल विजय समाज गणेश उत्सव गांधीनगर, इनसेट में अध्यक्ष विकी बैसवारे.

धरमपेठ स्थित मामा रोड में गणेशोत्सव की अद्भुत झांकी, इनसेट में अध्यक्ष धनंजय बंसोड.

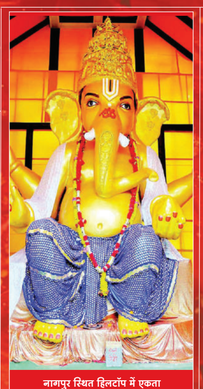

हिलटॉप गणेश मंडल में श्री गणेश की आकर्षक मूर्ति, इनसेट में अध्यक्ष प्रकाश गजभिये.

नागपुर स्थित रेशमबाग में नागपुर के महाराजा के नाम से मशहूर विघ्नहर्ता की आकर्षक प्रतिमा, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.

नागपुर स्थित गांधी पुतला न्यू इतवारी में नूतन गणेशोत्सव मंडल, इनसेट में अध्यक्ष दत्ता सेठे.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल नटराज टॉकिज रोड, जर्मन पैलेस नागपुर, इनसेट में अध्यक्ष आदित्य भिलकर.

नागपुर स्थित दत्त नगर कुंभार टोली में भगवान गणेश श्री बाला जी के रूप में विराजमान, इनसेट में अध्यक्ष उमेश आमगे.

नागपुर की महापौर अर्चना डेहनकर अपने आवास पर पति व पुत्र के साथ पूजा-अर्चना करते हुए.

मानेवाड़ा स्थित न्यू बालाजी नगर में विश्व शांति गणेशोत्सव मंडल, इनसेट में अध्यक्ष विनोद मंडलवार.

नागपुर स्थित हरिहर नगर बेसा में श्री गणेशोत्सव मंडल, इनसेट में सचिव आशीष रोकड़े.

सभी फोटो–*परीक्षित डोंगरे, निशा वर्मा, अजंता भौमिक*